

Third Series, Vol. LVII, No.3

Wednesday, July 27, 1966

Sravana 5, 1888 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(THIRD SERIES)

Vol. LVII, 1966/1888 (Saka)

[July 25 to August 5, 1966/Sravana 3 to 14, 1888 (Saka)]



Fifteenth Session, 1966/1888 (Saka)

(Vol. LVII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 3.—*Wednesday, July 27, 1966 (Sravana 5, 1888 (Saka))*

	COLUMNS
Obituary Reference	577—78
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 61 to 65.	578—615
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 66 to 90.	615—35
Unstarred Questions Nos. 265 to 287, 289 to 291, 293 to 296, 298 to 321, 323 to 336, 339 to 431, 433 to 441 and 443 to 455.	635—766
Re. Calling Attention Notices—	
(<i>Query</i>)	766—69
Papers Laid on the Table	769—75
Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
Ninetieth Report	775
Petition <i>re.</i> Inquiry Commission on Maharashtra-Mysore boundary question	775
Re. Recent Railway Accidents	775-76
Business Advisory Committee—	
Forty-eighth Report.	776
Cotton Fabrics (Additional Excise Duty)—(Repeal) Bill—	
<i>Introduced</i>	776—77
Motion <i>re.</i> Present Economic Situation in the country—	
<i>Debate adjourned.</i>	777—89
Re. Revocation of Suspension of Members	790
Personal Explanation by Member (<i>Shri Khadilkar</i>)	790—92
Merchant Shipping (Amendment) Bill	792—800
Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	792—800
Shri C. M. Poonacha	792—96
Clauses 2 to 39, new clauses 40 and 41, and clause 1.	799—800
Motion to pass, as amended	800
Electricity (Supply) Amendment Bill	801—09
Motion to consider	801—09
Dr. K. L. Rao.	801—06
Business of the House	809—10
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Reported Decision of Government to appoint Shri S. Bhoothalingam as Ambassador to E.E.C. at Brussels.	811—16

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

LOK SABHA

Wednesday, July 27, 1966/Sravana 5,
1888 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Chaudhri Hyder Husein who passed away at Lucknow on the 24th July, 1966 at the age of 76.

Chaudhri Hyder Husein was a Member of the Constituent Assembly of India, the Provisional Parliament and the First Lok Sabha during the years 1949 to 1957. We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): Mr. Speaker, Sir, it pains me to refer to the death of yet another friend of this House, Chaudhri Hyder Husein, who had been associated with us in the Constituent Assembly of India, in the provisional Parliament and in the first Lok Sabha. Chaudhri Hyder Husein had first come into contact with parliamentary life in 1937 when he was elected to the UP Legislative Assembly. Though he was a leading and busy lawyer, he gave in an ample measure his time and attention to a large number of educational institu-

tions and other social organisations in the State of Uttar Pradesh. The number of institutions with which he was actively connected runs into more than two scores. He was also actively engaged in the task of emancipation of women and was the guiding spirit behind many an institution devoted to this task. He had a suave and amiable personality which made him distinguished and popular in whichever company he sat.

I hope the House will join with me in mourning the death of this friend. I request that you may kindly convey the condolences of the House to the members of the bereaved family.

Mr. Speaker: The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Insurance of Jobless People

+

61. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bagri:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1609 on the 11th May, 1966 regarding the Insurance of Jobless People and state:

(a) whether the proposal to introduce the scheme of Unemployment

Insurance for persons who are employed but may lose employment has since been considered; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The proposal is still under consideration.

(b) The details have not yet been finalised.

डा० राम मनोहर लोहिया: मैं तफसील का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मिद्दान्त का पूछ रहा हूँ, इस लिये मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूँ कि वह जवाब देंगे—कि रपट में किम मिद्दान्त पर बेकारी के बोम की बात कही गई है? या तो जो तनख्वाह और आमदनी है उसके किमी अनुपात या प्रतिशत या जीवन निर्वाह? अगर प्रतिशत है आमदनी का तो कितना और अगर जीवन-निर्वाह है तो कम से कम कितना जीवन-निर्वाह भत्ते का दिया जायगा, वह मेहरबानी कर के मंत्री महोदय बतायें और इस पर उनकी सैद्धान्तिक रूप से क्या प्रतिक्रिया है, यह भी बतायें?

श्री शाहनवाज खाँ: जैसा कि मैंने अभी कहा है कि यह ड्राफ्ट स्कीम है और अभी जेरे गौर है।

अध्यक्ष महोदय: पहली चीज तो वह यह पूछने हैं कि एज ए सैटर आफ पालिसी क्या यह माना जाता गया है कि ऐसा इन्तजाम किया जायगा कि जॉब-लैम को मुआवजा दिया जायगा?

श्री शाहनवाज खाँ: असूलन इस चीज को मान लिया गया है। दूसरे स्टैंडिंग लेबर कमेटी के मामले, जो उसकी अगली मीटिंग होगी, उस में यह सारी स्कीम रखी जायेगी और मरेदस्त ख्याल यह है कि तमाम वे कर्मचारी जो एम्पलाईड प्राविडेन्ट फंड और एम्पलाईड स्टेट थ्योरैन्स स्कीम के तहत जिनका

बीमा है या उसके तहत आते हैं, वे लोग सब से पहले इसमें लिये जायेंगे, उनके बाद दूसरी केटेगरीज को लिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है कि ऐसा करते वक्त क्या यह देखा जायगा कि जो कुछ उनको वेतन मिलता है उसका कोई प्रतिशत या सेन्ट-परसेन्ट उनको दिया जाय, या यह देखा जायगा कि जिससे उसके परिवार का गुजारा हो सकता है, वह उसको दिया जाय? क्या मैंने ठीक सवाल रखा है?

डा० राम मनोहर लोहिया: जी हाँ।

श्री शाहनवाज खाँ: इस चीज को जेरे गौर रखा जायगा कि जो उनको तनख्वाह मिलती है, उसके तनासिब से ही उनको फैंसिलिटीज मिलेगी।

डा० राम मनोहर लोहिया: अध्यक्ष, महोदय, आज यह आपका सवाल है। आज तो आप इनसे जवाब दिलवाइये ही, जेरे-गौर के कोई मतलब नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: डाक्टर साहब, अगर गवर्नमेन्ट ने अभी तक इस पर फैंसला नहीं किया है

डा० राम मनोहर लोहिया: वह तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब आप दूसरा सवाल कीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया: अब सवाल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जब इस तरह के जवाब आते रहते हैं। अब आप ही बतलाइये, बड़ा सीधा सवाल उन से मैंने पूछा था। मेरा दूसरा सवाल भी यही है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि ये मंत्री अपने महकमे की कोई चीज भी नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय: इस से कोई ज्यादा जवाब आप दे सकते हैं?

श्री शाहनवाज खां: इस चीज पर अभी आखरी फैसला नहीं हुआ है।

श्री मधु लिमये: क्या वजह है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर उत्तर देने के लिये जगजीवन बाबू सदन में नहीं हैं, वह आते तो शायद इसका जवाब दे सकते थे। यह एक मुख्य महकमा है, लेकिन मंत्री यहां नहीं रहते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया: सिद्धान्त का जवाब दिलवा दीजिये तफसील का न सही, खाली सिद्धान्त का?

अध्यक्ष महोदय: आपने कहा कि मेरा दूसरा सवाल भी यही है, उन्होंने कहा कि वह इस से ज्यादा जवाब नहीं दे सकते, आप कहिये मैं और क्या कर सकता हूं?

डा० राम मनोहर लोहिया: जो आप इधर वालों के साथ किया करते हैं, उनके साथ भी कीजिये, जरा कुछ देर के लिये इन को निकाल दीजिये।

श्री रामसेवक यादव: मंत्री महोदय ने कहा कि व्योरे पर गौर हो रहा है, मैं व्योरा नहीं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं? दूसरे, क्या ऐसे कर्मचारियों के बारे में भी सोचा जा रहा है जो बड़े उद्योगों में आने के कारण बेकार होंगे, क्या वे भी इस में शामिल होंगे?

अध्यक्ष महोदय: वह तो उन्होंने कह दिया है। तमाम वे लोग जो एम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम और एम्पलाइज स्टेट प्राविडेंट फण्ड के तहत आते हैं, वे इस में आयेंगे।

श्री राम सेवक यादव: इसकी मुख्य-मुख्य बातें अग क्या हैं?

श्री शाहनवाज खां: अभी इस पर आखरी फैसला नहीं हुआ है।

श्री यशपाल सिंह: क्या सरकार बतला सकती है कि देहात के जो 85 फीसदी कर्मचारी हैं, इस स्थिति में हैं कि उनकी नौकरी 8-6 महीने में छूट जाती है, उन्हें प्रायोरिटी देने के लिये सरकार ने क्या कोई मद रखी है और क्या यह भी बतला सकते हैं कि डम पर सरकार कितना खर्च करेगी?

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरा सवाल है।

श्री यशपाल सिंह अध्यक्ष महोदय, मैं इतना बतला दूँ कि हर जगह प्रायोरिटी शहरों को मिलती है, देहात के लोग देखते रह जाते हैं।

श्री क० ना० तिवारी: क्या सरकार ने कोई सर्वे किया है कि ऐसे कर्मचारियों की तादाद कितनी है और वे किस कटेगरी के हैं?

श्री शाहनवाज खां: मैंने कहा है कि एम्पलाईज प्राविडेंट फण्ड के नीचे 45 लाख मुलाजमीन हैं वे सब इस स्कीम के तहत आयेंगे।

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कभी उन्होंने हमारे संविधान में रोजी और बेकारी के सम्बन्ध में जो तीन निदेशक सिद्धान्त हैं, उनकी ओर ध्यान दिया है। जैसे धारा 39 है, उसमें कहा गया है कि हर एक को रोजी मिलनी चाहिये, धारा 41 है, उसमें बेकारी का सवाल है, धारा 45 में पोषण का मामला है।

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल इतना लम्बा है कि यह इस में नहीं आता है।

श्री मधु लिमये: क्या इन निदेशक सिद्धान्तों की ओर उनका ध्यान गया है और वे सिद्धान्त कब तक निर्गुण, निराकार ब्रह्म के रूप में रहेंगे या पांच साल में, दस साल में या पन्द्रह साल में उनकी ठोस साकार, सगुण रूप दिया जायगा। क्या कभी इन के बारे में आपने सोचा है या हम लोगों के साथ मजाक चला रहे हैं।

Mr. Speaker: That is a matter of wider policy; that cannot be put as a supplementary question.

श्री मधु लिम्पे: इसी को लेकर सीमित प्रश्न का उत्तर तो दें, तीन धाराओं के बारे में तो जवाब दें, सभी निदेशक सिद्धान्तों के बारे में जवाब न दें। इन धाराओं के बारे में बतायें ?

Shri Kapur Singh: In any case, Sir, this House cannot compel the Treasury Benches to think; it is unreasonable.

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार का इस स्कीम पर जो जल्द से जल्द लागू करने का इरादा है और क्या इस को देहाती क्षेत्रों में भी लागू किया जायगा ?

श्री शहनवाज खां : फिलहाल इस को देहाती क्षेत्र में लाने का कोई ख्याल नहीं है। जसा मैंने कहा यह सारी स्कीम लेकर स्टैंडिंग कमेटी के सामने अगली मीटिंग में रखी जायगी और वहां जो तय पाया जायगा उस के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

Shri Shama Lal Saraf: From this question, I find that this is restricted to such employees who may be rendered jobless. May I know if, where people are serving in Government Departments, they are rendered jobless, and they get some sort of compensation under this scheme and also if, where labourers who are covered under labour laws are working in factories and they are rendered jobless, they are also included under this scheme?

Shri Shahnawaz Khan: All the industrial labourers are entitled to certain lay-off and retrenchment benefits. The benefits under this scheme will be in addition to those benefits and the quantum as it is proposed which has yet to be decided would be about 6 months' half salary on average pay.

Shri Dinen Bhattacharya: As the Minister just now stated, this will be an additional benefit over and above the lay-off and the retrenchment benefits. May I know whether it is in the knowledge of the Government that in many cases, specially in the cases of closures of mills, the employers always deprive the workers of the retrenchment benefits on some plea or the other?

Shri Shahnawaz Khan: When there are any specific cases of grievances, there is a set procedure for dealing with such disputes and grievances.

Shri A. P. Sharma: According to the proposal, it seems that this scheme will be applicable during the unemployment period in the case of those who are already employed and rendered jobless for a certain period. May I know whether this scheme will be applicable to lakhs and lakhs of workers who are only given the name of casual workers and who remain unemployed for certain periods?

Shri Shahnawaz Khan: For the time being, the casual labour would fall outside the ambit of this scheme.

श्री गुलशन : क्या सरकार ने इस बीमा स्कीम में उन देहाती खेत मजदूरों को भी शामिल करने का कोई विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस स्कीम में तो वह नहीं हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा नाम कैसे रह जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी इस वक्त रह गया है।

श्री बागड़ी : हमेशा ही रह जाता है यही तो मेरी बदकिस्मती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई इरादा नहीं होता।

पाकिस्तानी जासूस

+

62. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री यशपाल सिंह :

श्री रामेश्वरानन्द :

श्री सुबोध हंतदा :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री भागवत झा आजाद :

श्री स० ला० द्विवेदी :

श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालन्धर में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का एक केन्द्र है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने एक दर्जन व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनमें भारतीय और पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है और उनके क्या नाम हैं ; और

(घ) उनको कञ्चे से बरामद की गई वस्तुओं का विवरण क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मार्च 1966 में कुछ व्यक्ति जिनमें एक पाक नागरिक भी शामिल था, पाकिस्तान के लिये जासूसी करने के आरोप में जालंधर में गिरफ्तार किये गये।

(ग) और (घ). मामले की अभी तक जांच की जा रही है और इस स्थिति में अग्रे व्यौरा बताना जन-हित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा क्योंकि इसे बताने से जांच की कार्यवाही र असर पड़ सकता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास ऐसी कौन सी सामग्री मिली है ? क्या कुछ ऐसे हथियार या कुछ ऐसे कागजात उन लोगों के पास से मिले हैं जोकि जासूसी करते पकड़े गये हैं, यदि हां, तो वह किस-किस प्रकार के हथियार या कागज थे ?

श्री हाथी : क्या क्या उन पाकिस्तानी जासूसों के पास से मिला है वह सब तो मैं नहीं बतला सकूंगा लेकिन हथियार नहीं मिले हैं इतना मैं कह सकता हूँ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: यह जो लोग पकड़े गये हैं क्या उनसे पूछताछ से कुछ इस बात की जानकारी मिली है कि इस प्रकार के उनके गिरोह के जासूस देश में और भिन्न स्थानों में फैले हुए हैं, यदि हां, तो उन्हें पकड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : अभी सारी बात हम नहीं बतला सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंबर साहब ने कह ऐसे क्लृप्त और इस प्रकार की बहुत सी बातें आई हैं और बशर्त कि हम उस बारे में कुछ बात न करें, उन का पता लगाना आसान होगा वरना उसमें बहुत मुश्किल होगी।

Shri P. C. Borooah: Not only in Jullundur on the West Pakistan border but also in Assam on the East Pakistan border, spying activities are rampant. One Mr. Mohit Choudhury who is a Pakistani Muslim spy . . .

Mr. Speaker: Can the Minister remember one individual?

Shri P. C. Borooah: One Mr. Mohit Choudhury who is a Pakistani Muslim spy, after coming to India, married 3 Bengali girls, 2 Assamese girls and one Bihari girl, and was carrying on spying activities and he was arrested at Ghatshela in May last. He made the confession before the Magistrate wherein the names of several Indians also appeared. The Central Government wanted those persons to be apprehended. But nothing has been done up till now. May I know whether the Punjab Government is also

following the same course in handling the spying activities in Punjab on the West Pakistan border?

Shri Hathi: This question relates only to Jullundur. So far as West Bengal and other cases are concerned, I will require notice . . . (Inter-ruptions).

Shri Tyagi: One misunderstanding has been created. The hon. Member has said that the Bengal Government has flouted the instructions of the Central Government. That at least may be clarified. Is it a fact that the Home Minister directed the Bengal Government to get some people arrested and they flouted the instructions?

Shri Surendranath Dwivedy: The State Government did not support because some persons working in the All India Congress Committee office are connected with this matter. Therefore, the State Government is not helping even in arresting those having complicity with the Pakistan spies.

Shri Hathi: There is no question of any State Government flouting the instructions of the Central Government.

Shrimati Renu Chakravartty: Has he been arrested?

Mr. Speaker: He may answer this question.

Shri Hathi: I have no information.

Mr. Speaker: Mr. Prakash Vir Shastri.

Shri Hem Barua: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: There is no point of order. Mr. Prakash Vir Shastri.

Shri Hem Barua: He should give definite information . . .

Mr. Speaker: Mr. Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद जलन्धर के अतिरिक्त भी क्या पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार के पाकिस्तानी जासूसों का पता लगा है जो वहां आ कर बस गये थे और सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में काम कर रहे थे वहां आ कर उन्होंने विवाह आदि भी कर लिये, यदि हां, तो उन की क्या संख्या है और दूसरे यह कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद ही यह दूढ़ ढांड क्यों प्रारम्भ हुई उस से पहले सरकार हमारी इतनी सतर्क क्यों नहीं रही ?

श्री हाथी : जी हां, पंजाब के कुछ स्थानों में ऐसे लोग काम करते हैं जिन का कि पता लगा है । पहले भी लगा था और इस के पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उन की संख्या कितनी है ?

श्री हाथी : पंजाब की तो नहीं बाक़ी सब मिला कर 80-85 होगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जासूस जो पाकिस्तान से आते हैं और यहां आ कर मिल जाते हैं तो क्या उन लोगों के बारे में यह पता लगा है कि मुसलमानों के अतिरिक्त वे हिन्दू, सिक्ख और ईसाईयों आदि के साथ भी रहते हैं ?

श्री हाथी : मैं समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना यह है कि यहां जो इंडियन सिटीजन्स रहते हैं वे पाकिस्तानी लोग उन के साथ मिल कर रहते हैं और यह कि यहां के लोग उन की मदद करते हैं ।

श्री हाथी : दो प्रकार के लोग है । एक तो यहां के लोग भी हैं जोकि कुछ जासूसी

का काम करते हैं बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जोकि वहां से यहां आये हैं और यहां के रहने वाले इंडियन सिटीजंस के साथ रहते हैं और अपना अवांछनीय काम करने लगे ।

श्री भागवत झा आजाद : हाल के कुछ महीनों में पाकिस्तानी जासूसों की गति-विधियां जम्मू-काश्मीर जैसे स्थानों में बढ़ गयी हैं और वहां पर राज्य सरकार चूँकि अब उन के खिलाफ कार्यवाही कर रही है तो उन से बचने के लिए पाकिस्तानी जासूसों ने जालन्धर आदि ऐसे स्थानों में अपने अड्डे बना रखे हैं, अगर यह बात सच है तो इन अड्डों को तोड़ने के लिए सरकार क्या क्रदम उठा रही है ?

श्री हाथी : नहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां काश्मीर से निकल कर यहां आये हैं बल्कि यहां पहले से ही पंजाब में कुछ काम करते थे और वहां से उन को गिरफ्तार भी किया गया है बाकी जैसे जैसे उन के खिलाफ कार्यवाही में तेजी हुई है और भी लोग पकड़े जा रहे हैं ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि जालन्धर का जो आप ने कहा कि एक पाकिस्तानी मिपाही पकड़ा गया है तो वह कितने साल से यहां काम कर रहा था और उस वक्त जालन्धर की पुलिस ने उस के खिलाफ तो कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री हाथी : मैंने कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ तो ऐक्शन लिया भी था और कुछ लोगों को पकड़ा भी बाकी यह सही है कि कुछ लोग अभी भी हैं जोकि पकड़े नहीं गये हैं और हम उन्हें भी तलाश करके पकड़ेंगे ।

श्री बड़े : वह कितने सालों से यहां था ?

श्री हाथी : दो, एक सालों से था ।

Shri S. C. Samanta: May I know whether the incriminating papers that were seized from those spies have

been examined, and whether any clue in other border States has been found?

Shri Hathi: As I have said, we have got some material and that is being examined. That is why I have said that we would not give further details because it leads to certain clues also or it is likely to lead to certain clues also.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सी० आई० डी० ऐसी कार्रवाइयों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है या सोई हुई रहती है । हमारे जैसे पोलिटिकल वर्क्स जो होते हैं उनके पीछे तो पांच-पांच छः-छः और सात-सात आदमी लगा दिए जाते हैं लेकिन जॉ जासूस दूसरी जगहों से आये होते हैं उनकी इतनी भी तलाश नहीं होती कि गंगोत्री माउन्टेन पर चढ़ने के वास्ते गुजरात की जो स्टूडेंट्स लड़कियां भेजी गई थीं उनके नेता के बारे में आप को यह पता लगता कि वह पाकिस्तानी जासूस थी ।

श्री हाथी : जलंधर में जो पकड़े गये ह उनमें कोई पोलिटिकल वर्कर नहीं था ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह पोलिटिकल बात नहीं है तो क्या है ।

श्री हाथी : मैं ने जो कहा वह यह कि जो 80 या 85 आदमी जासूसों के रूप में पकड़े गये हैं उनमें कोई भी अपोजीशन पार्टीज का या पोलिटिकल वर्कर नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री हाथी : यही बात है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब हम लोगों के पीछे सी० आई० डी० लगते हैं तो और लोगों के पीछे भी सी० आई० डी० लगाइये ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह में तो आखिर नहीं बोलना चाहिये। मैंने बार-बार दरवास्त की कि जब जवाब चल रहा है तो दर्म्यान में कोई न बोले (व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order, order. I might be allowed to proceed.

श्री हुकम चन्द कद्वनाथ : पहले गुजरात के बारे में तो जवाब दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस की इजाजत नहीं देता।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इधर थोड़े दिनों से काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की कारवाइयां कुछ ज्यादा हो रही हैं और बहुत सी पाकेट्स वहां पर ऐसी बन गई हैं जहां भारत के विरुद्ध काम हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो काश्मीर में कितने आदमी अरेस्ट किये गये हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : काश्मीर में कुछ दिन हुए मैंने जा कर सारी हालत देखी और मैं समझता हूँ कि वहां बड़ा अच्छा काम हुआ है और उन्होंने बड़ी सफलता से वहां पर जो जो सैल बन गई थी उन को अनअर्थ किया। मैं कह सकता हूँ कि वहां पर जो उन लोगों का नेट वर्क था वह करीब करीब तोड़ दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : वहां पर अरेस्ट कितने हुए हैं।

श्री नन्दा : पिछले दिनों में काफी लोग अरेस्ट हुए हैं।

श्री श्यामलाल सराफ : कितने भाग गये।

श्री नन्दा : भाग भी गये होंगे यह भी सम्भव है। 100 की सदी कामयाबी नहीं हुई

है लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी हुई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दख्खीस्त करूंगा कि मुझे कोई ऐसी मशीनरी दे दी जाये जिस से मैं "आर्डर, आर्डर" कहता चला जाऊँ। मैं बोलता रहता हूँ और अपना गला खराब करता रहता हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं है।

Shri Sham Lal Saraf: May I know how many officers who were arrested had gone away? How many of the arrested officers had left?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीकांत लाल बेरवा : आप मंत्रियों से दख्खीस्त कीजिये कि जो पूछा जाय वह उम का जवाब दें।

एक माननीय सदस्य : श्री सराफ ने जो पूछा है उस का जवाब दिया जाये।

Shri Sham Lal Saraf: I want to ask a very important question.

Mr. Speaker: I had not called the hon. Member. I cannot proceed in this manner. Unless I call an hon. Member he should not begin asking questions.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बतला सकती है कि जो हिन्दुस्तानी मुनाफाखोर लाखों करोड़ों रुपये पाकिस्तान को दे रहे हैं, चीनी पाकिस्तान को दे रहे हैं, कपड़ा पाकिस्तान को दे रहे हैं, यहां की इन्फार्मेशन पाकिस्तान को दे रहे हैं, वह जासूसों की श्रेणी में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो कितने हिन्दुस्तानी मुनाफाखोरों को सजा दी गई है और कितनों के चालान हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल की इजाजत नहीं दी जा सकती।

I do not allow that.

श्री प्रशापल सिंह : यह बड़ा जरूरी सवाल है कि वह लोग जामुनों की श्रेणी में आते हैं या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल यह है कि फैसला करना मेरा काम है कि इस तरह का सवाल यहाँ पर आ सकता है या नहीं ।

Shri Kapur Singh: May I know whether some information is available about any arrests having been made in Pakistan on the allegation that they are Indian spies?

Shri Hathi: I would require notice of that question.

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ।

श्रीमती सहोदराबाई राय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस तरह के माननीय सदस्य को बुलाया है ।

Shri Hem Barua: Is it a fact that Pakistani spies in India are having the active help and support, moral and financial, of certain Pakistan diplomatic missions in this country? If so, what steps have been taken to destroy and disrupt this link that has been fostered in this country between these spies and certain Pakistani diplomatic missions?

Shri Hathi: So far as this question is concerned, we have got some clues about the links. The police are trying to further look into the matter and take action against those officers.

Shri Hem Barua: My question was specific.

Mr. Speaker: And that was inadmissible. This was only about the arrests that have been made in Jullundur, not any other thing.

Shri Hem Barua: Jullundur is part of India.

Mr. Speaker: And India is part of the greater world.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय की ओर से कोई इस प्रकार का उत्तर दिया जाये जिसे हमें दूसरे राज्यों की समस्या आ जाये और उत्तर में मंत्री महोदय इस राज्य या उस राज्य की सरकार को कोई प्रमाण पत्र दे दें तो क्या माननीय सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह उस राज्य से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सवाल पर मुनहस्मर होगा। जब वह सामने आयेगा तब मैं इस का फैसला करूँगा ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : काश्मीर सरकार को उन्होंने जो प्रमाणपत्र दिया है उस के बारे में

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने काश्मीर सरकार को जो प्रमाण पत्र दिया वह भी गलत था ।

Shri Sham Lal Saraf: I seek your guidance.

Mr. Speaker: I have to decide, not to give guidance.

Shri Sham Lal Saraf: Who else is to give us guidance then?

Mr. Speaker: No, no. I cannot give guidance. If a matter comes up, I have to decide.

Shri Sham Lal Saraf: I am sorry we cannot get guidance from you. I do not know from whom we can get it then.

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका ही नहीं दिया गया ।

Mr. Speaker: The most thankless job is that of the Speaker.

Indo-U.S. Education Foundation

+

- *63. **Shri Nambiar:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri A. S. Alva:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing:
Shri Hem Barua:
Shri Nath Pai:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Renuka Ray:
Shri Harish Chandra Mathur:
Shri P. C. Borooah:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri H. N. Mukerjee:
Shri R. Barua:
Shri Yashpal Singh:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri R. S. Pandey:
Shri Utiya:
Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Hem Raj:
Shri Daljit Singh:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has recently stated that the proposal for setting up of the Indo-American Education Foundation was finalised by the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri;

(b) if so, what were the terms then proposed;

(c) whether there is any change in the new terms on the suggestions of eminent educationists; and

(d) if so, the final terms and conditions of the agreement?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a): The Prime Minister had stated that the proposal to set up an Indo-American Education foundation was approved in principle in March, 1965 when the late Shri Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister.

(b) to (d). Neither Government had committed itself to any precise terms in March, 1965 and even today, the position is fluid. The reactions of educationists to various proposals, which had been tentatively formulated, will be fully taken into account by Government when further talks with the U.S. authorities, for which no time-table has so far been fixed, take place.

Shri Nambiar: In view of the fact that a large section of Indian public opinion is against such a Foundation which will surely contribute to the growth of American domination, political and economic, in India, have Government reconsidered the matter and taken up any proposal to give up the proposed scheme?

Shri M. C. Chagla: I repudiate both the assumptions underlying the question.

Some hon. Members: Why?

Shri M. C. Chagla: I do not accept that public opinion is against the establishment of this Foundation.

Shri Vasudevan Nair: We challenge Government on this question.

Shri M. C. Chagla: May I finish? The second assumption is that the setting up of this Foundation will lead to political and economic domination by the U.S. As both the assumptions are incorrect, the rest of the question need not be answered.

Shri Nambiar: Is it not a fact that even eminent professors of universi-

ties have opposed the formation of this Foundation? Have Government considered the point of view expressed by these professors?

Shri M. C. Chagla: May I point out that I took the trouble to call a meeting of the professors of the Delhi University, for whom I have great regard and who represent some of our intellectual elite. I had a talk with them. Then we called another meeting of educationists at which the Prime Minister was present. We listened to them, and what we discovered was that although there was criticism as to the form the Foundation might take, by and large there was no serious opposition to the principles of the Foundation.

श्री विभूति मिश्र : क्या कोई ऐसा भी सुझाव प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने आया है कि यह जो रुपया है इसको शिक्षा मंत्रालय को दे दिया जाए और शिक्षा मंत्रालय इसको खर्च करे या इस रुपये को टैक्नीकल एजुकेशन पर ही खर्च किया जाए तथा किसी दूसरे कामों में खर्च न किया जाए ?

Shri M. C. Chagla: That was one of the suggestions put forward at the meeting of the educationists, that instead of starting the foundation, this amount should be given to the Ministry, and the answer was, at least, the tentative answer was, that this money belongs to the United States. It is entirely at the disposal of the United States, and it is rather difficult to ask the United States that instead of starting a Foundation, they should hand over the money. And personally I think it is not right for the Ministry of Education to accept a gift like this from a foreign country.

Shri Surendranath Dwivedy: The Minister just now stated that the terms have not yet been finalised. What is the view of the Government in this matter, whatever might be the composition of the Foundation? Is it the

view of the Government that the direction, control and management of the entire Foundation will be in the hands of the Indian Government?

Shri M. C. Chagla: Yes, Sir. I can give an assurance to this House that when the Foundation is ultimately established, Indian opinion will have a preponderating voice. The Foundation will never be permitted to formulate or implement any policy which will run counter to our national policy; nor will we permit any American influence to be injected into our culture and our way of life.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जानना चाहता हूँ कि जब पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से अनाज मंगाने का करार हुआ था तो क्या भारत और अमरीका सरकार के बीच इस प्रकार का भी कोई करार हुआ था कि यह पैसा किस रूप में खर्च किया जाएगा ? यदि हुआ था तो उसकी शर्तें क्या थीं ? और क्या यह जो फाउंडेशन बनाया जा रहा है, इसका पैसा शिक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरी मद में जैसे सिचाई है, बिजली है या सड़कों आदि का निर्माण है, भी खर्च किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो इस सुझाव पर भारत सरकार ने विचार किया है या नहीं ?

Shri M. C. Chagla: May I explain to the House—I am sure many Members know it—that under P.L. 480 the counterpart rupees that we get are to be disposed of in this manner; 80 per cent are to be spent on developmental programmes with the consent both of the Indian and American Governments; 13 per cent can be used by the United States to help American business; 7 per cent is entirely at the disposal of the United States which is called "Money for American use", and it is this 7 per cent that we are trying to immobilise. This 7 per cent represents a little more than Rs. 200 crores and the suggestion is to take this Rs. 150 crores which America can use for any purpose, over which we have no control.

Shri Bhagwat Jha Azad: You say any purpose. Is it for espionage also?

Shri Nambiar: It is being used for espionage.

Shri M. C. Chagla: Any purpose under international law and international morality, but it is at the disposal of the United States, we have no control, we cannot ask them what they are doing with it or why. Therefore, it is a good thing for our country that, instead of leaving it to the United States to spend all this money, we immobilise it. This money will be invested in Government securities. The Foundation will be an Indian foundation governed by Indian laws and carrying out Indian policies.

श्री किशन पटनायक : यह प्रतिष्ठान एक साजिश है हिन्दुस्तान में एक तो अमरीकी भाषा को स्थायी बनाये रखने की और अमरीकी भाषा के जरिये हिन्दुस्तान की संस्कृति को अमरीकी संस्कृति और सभ्यता द्वारा प्रभावित करने की। क्या यह सही है ?

Shri M. C. Chagla: I take it that my hon. friend is drawing a distinction between the English language and the American language. He is quite right. American language has become a different language now.

Shri Ram Sewak Yadav: I think you have misunderstood.

श्री किशन पटनायक : समझने की कोशिश करें।

Shri Bhagwat Jha Azad: The Pant Market has become Super Market. That is the American language.

Shri M. C. Chagla: I do not like that expression, Super Market.

श्री किशन पटनायक : अंग्रेजी भाषा ज्यादा अमरीका की है और इंग्लिस्तान की उतनी नहीं है, यह समझ लेना चाहिये।

Shri M. C. Chagla: May I point out that today we have got several Ameri-

can foundations. I will give the names: There is the US Educational Foundation in India—the Fulbright Group; There is then the US Aid Agency; there is the Ford Foundation; there is the Rockefeller Foundation; there is the Asia Foundation; these are spending lakhs of rupees for various aspects of education and other programmes in India. These are entirely American foundations over which we have no control. Surely, all these foundations have not interfered with our culture of which I am very proud. (Interruption). Why should we assume that a foundation which would be under Indian control to a large extent will do harm to our culture?

श्री किशन पटनायक : जवाब दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

Shri Harish Chandra Mathur: Is it not a fact that as a result of severe criticism of this proposal in the country, there was a reaction among the Americans themselves? What was their reaction? Is it a fact that they want to forget all about it and we want to forget all about it and nobody wants to take any initiative? If it is not so, who is now taking the initiative and at what stage does it rest?

Shri M. C. Chagla: As my hon. friend knows, there was a declaration made by the President of the United States, and our Prime Minister concurred with the idea of establishing a foundation. Shastriji, when he was the Prime Minister, brought the matter to the Cabinet and the Cabinet gave its approval to the foundation in principle, so that the principle of the foundation is accepted. The United States is fully conscious how sensitive India is and rightly so. We are very sensitive of our culture; we are very sensitive about those areas where we do not want any foreign interference. Knowing the sensitivity of this country,—(Interruption)—may I finish. please?

श्री रामेश्वरानन्द : आपकी मंस्कृति क्या है, इतना तो आप बता दें।

Shri M. C. Chagla: America knows the criticism here. It has been conveyed to the United States, what the public feeling is. Therefore, it has done good. I am glad that public opinion has asserted itself in this country. So, ultimately, when we sit down and discuss the details, the United States will take into consideration what public opinion in this country is.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, we could have a two-hour discussion on this subject, later on. (*Interruption*).

Shri M. C. Chagla: There is a letter from—(*Interruption*).

Mr. Speaker: It is the desire of hon. Members, and I also feel that—(*Interruption*)—order. order—sometime afterwards a discussion might be had on this subject, because it agitates so many hon. Members.

Shri M. C. Chagla: I am in the hands of this House. A time can be found.

Mr. Speaker: If notice is given, I will try.

Shri Hari Vishnu Kamath: We will give notice.

Media for U.P.S.C. Examination

+

*64. **Shri Sezhiyan:**

Shri Madhu Limaye:

Shri Kishen Pattanyak:

Dr. Ram Manohar Lohia:

Shri Umanath:

Shri Muthiah:

Shri Bagri:

Shri M. L. Dwivedi:

Shri S. C. Samanta:

Shri Subodh Hansda:

Shri Bhagwat Jha Azad:

Shri P. C. Borooah:

Shri P. R. Chakraverti:

Shri Linga Reddy:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Public Service Commission has finalised a formula for holding the

Central Services examinations in all the 14 languages;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) when the new formula will be adopted in the U.P.S.C. examinations?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Not yet, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Sezhiyan: May I know whether the attention of the Government has been invited to a public statement made by the Chief Minister of Madras, Shri Bhaktavatsalam, at Madurai that the Union Public Service Commission had finalised a formula for holding the Central Service examinations in all the 14 languages of India? This statement was made by the Chief Minister of Madras. I want to know whether that statement is correct or not.

Shri Vidya Charan Shukla: The Union Public Service Commission is going ahead with the finalisation of this scheme. It will take a little more time before the scheme can be implemented.

Shri Sezhiyan: May I know whether it is a fact that the Government have been giving the assurances on the floor of this House from 1954 onwards that all the principal regional languages will be the media of examination of the UPSC? I want to know whether the Government have taken the advice of the UPSC into consideration before making these solemn assurances or whether the assurances were made simply to hoodwink the non-Hindi speaking people or whether they are serious in implementing these assurances?

Shri Vidya Charan Shukla: There is no difference of opinion between the Government and the UPSC on this question.

श्री मधु लिमये : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कानून मंत्रालय ने यूनिजन पब्लिक सर्विसिज कमिशन को यह सलाह दी है कि उनके द्वारा जो इन्तहान आदि लिये जाते हैं यह कार्य केन्द्रीय सरकार का नहीं है और इसलिए उस में संविधान की हिन्दी की जो धारायें हैं वे लागू करने की कोई जरूरत नहीं है? यदि इस तरह की सलाह दी है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस पर केन्द्रीय सरकार ने मुहर लगाई है या यह केवल कानून मंत्रालय की ही सलाह है?

Shri Vidya Charan Shukla: There was a secret communication from the UPSC to the Government, which was referred to the Law Ministry and it would not be in public interest to disclose it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह खबर अखबारों में छप चुकी है और क्या सलाह दी गई है, इस का सारांश भी आ गया है। इस स्थिति में मंत्री महोदय के यह कहने का क्या अर्थ है कि हम सार्वजनिक हित में यह बात सदन को नहीं बता सकते हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह अखबार वालों को बता सकते हैं और केवल सदन को नहीं बता सकते? इस बात को ले कर काफ़ी गर्मी . . .

श्री विद्या चरण शुक्ल : अखबारों में जो बातें छपती हैं, वे हमेशा सच नहीं होती हैं। जहाँ तक सदन को बताने का प्रश्न है, जो बात सार्वजनिक हित में होगी, वह अवश्य बताई जायेगी।

श्री मधु लिमये : इस में सार्वजनिक हित की बात क्या है?

श्री हुकम चन्द कछवाय : सरकार यह बताए कि समाचार-पत्रों में जो कुछ छपा है, वह ठीक है या गलत।

अध्यक्ष महोदय : अगर समाचार-पत्रों को गवर्नमेंट के किसी स्पोक्समैन ने बताया है,

तो मैं जरूर कहूंगा कि मिनिस्टर साहब उस को यहां बतायें, लेकिन अगर किसी और तरीके से समाचारपत्रों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो मैं क्या कह सकता हूँ?

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उपगृह मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह ला मिनिस्ट्री का सीक्रेट आर्डर था।

श्री विद्या चरण शुक्ल : नहीं।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या कोई सीक्रेट आर्डर समाचारपत्रों में छप सकता है? उपगृह मंत्री यह स्पष्ट करें कि समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है, वह गलत है। अगर वह उसका खंडन नहीं करते हैं, तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन के आफिस से लीक आउट हुई है, जिस की जिम्मेदारी गृह-मंत्री पर आती है। दोनों में से एक बात तो जरूर है।

अध्यक्ष महोदय : जिम्मेदारी के मामले को अलग से डील किया जा सकता है। मैं मिनिस्टर साहब को मजबूर नहीं कर सकता हूँ कि जो कम्यूनिकेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, डिपार्टमेंट्स में आपस में जो खूबो-किताबत हो, वह उस को बतायें। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो कुछ अखबारों में आया है, वह गलत भी हो सकता है। उन्होंने गोल-मोल जवाब दिया है। उन्होंने साफ नहीं बताया है कि वह गलत है या दुरुस्त।

श्री रामेश्वरानन्द : मंत्री महोदय कह दें कि वह गलत है। (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा अफसोस है कि पांच छः मेम्बर साहबान एक साथ खड़े हो कर बोलने लग जाते हैं। मैंने बार-बार कहा है कि यह तरीका छोड़ दिया जाये। अगर एक मेम्बर खड़ा हो, तो दूसरा बैठ जाये।

Shri Ranga: How can they know that others are standing?

Mr. Speaker: If they only get up, that would be a different thing. They all get up and they begin to speak.

सम्बर साहबान कह रहे हैं कि यह खबर अखबारों में आई है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : किसी सरकारी प्रवक्ता द्वारा कोई ऐसी खबर नहीं दी गई है। ऐसी अटकलबाजियाँ अखबारों में निकलती रहती हैं।

(Interruptions)

श्री हुकम चन्द कछवाय : समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है, मंत्री महोदय उम का खंडन करें।

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय श्री भागवत झा आजाद।

श्री मधु लिमये : पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Bhagwat Jha Azad: I draw your attention to your earlier ruling that when a Minister claims that it is not in public interest to disclose something, then it will be for the Chair to decide whether it is in public interest or not. Now I claim the privilege to submit to you that the information which the Minister claims it is not in public interest to disclose, is not so. You should call for the papers and see whether it is in public interest or not, because in an important issue like language, on which questions are being put by everybody, if the Minister claims that it is not in public interest to disclose it, I say he is misusing the power. I am quoting your own ruling and request that you call for the papers and decide whether the Minister can claim this privilege or not.

Mr. Speaker: Ordinarily the Speaker has to accept the request of the Minister if he claims that it is not in public interest to disclose any information. That is the rule. But if there is some exceptional and extraordinary matter where there might be a doubt whether the privilege is being claimed bona fide, then I can go into it and see in such cases only. Otherwise, normally I have to accept it. That is the rule.

Shri Surendranath Dwivedy: So far as this question is concerned. .'.
Mr. Speaker: Then I may be given an opportunity to have a talk with him and give my decision.

श्री मधु लिमये : ठीक है। मैं आपका निर्णय मानता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का एक हिस्सा यह था कि अखबारों में जो खबर छपी है, क्या वह सही है। इतना तो वह बता सकते हैं। आप कई बार यह निर्णय दे चुके हैं कि तथ्यों के बारे में, फ्रैंक्स के बारे में, प्रश्न पूछ जा सकते हैं। सीक्रेट कम्यूनिकेशन वगैरह के बारे में आप बाद में जो फ्रैंसला देंगे, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कम से कम मंत्री महोदय इतना तो बतायें कि क्या कानून मंत्रालय ने यूनिथन पब्लिक सर्विस कमिशन को कोई इस तरह की सलाह दी है और इस सम्बन्ध में जो खबर छपी है, वह सही है या गलत।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं पूछ सकता हूँ कि कोई सलाह दी गई है या नहीं, लेकिन वह सलाह क्या है, यह मैं नहीं पूछ सकता हूँ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को समझिए। क्या सलाह दी गई है, इसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो खबर छपी है, वह सही है या गलत।

श्री विद्या चरण शुक्ल : कानून मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय को इस बारे में सलाह दी गई है। (Interruptions)

998 (A) LSD—2.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अखबारों में जो छपा है, वह मही है या गलत ?
(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : अगर छः मात, आठ मेम्बर साहबान यकलख्त खड़े हो कर बोलते चले जायें, तो कार्यवाही कैसे चल सकती है ? (Interruptions)

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गलत उत्तर दिये जाते हैं, इसीलिए सदस्य खड़े होते हैं। केवल इतनी सी बात है कि जो ख़तर छरी है, वह मही है या गलत। सरकार खुद सदन में उन्नेजना फैलाती है।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, ...
(Interruptions)

Shri Sezhiyan: Sir, this is not a mere Press report. This is a public statement made by the Chief Minister of Madras on the 19th May at Madurai. Therefore, it is a responsible person, the head of a State Government who has given that information. I want to know from the Home Minister whether it is correct or not. He can give that answer.

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय लोक-हित के नाम पर यह सूचना नहीं देना चाहते हैं, लेकिन लोक तक तो यह सूचना समाचार-पत्रों के द्वारा पहले ही आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि वह लोक-हित का नाम लेकर बात को टालना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले आ चुकी है।

श्री मधु लिमये : मैं यह जानना चाहता हूँ कि . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय . . .

Mr. Speaker: Order, order.

Some hon. Members rose —

Shri A. P. Sharma: Sir the Deputy Minister has said (Interruptions)

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय . . .

Mr. Speaker: That will not do on record (Interruptions) Order, order.

श्री हुकम चन्द कछवाय : * *

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने एक माननीय सदस्य को बुलाया है, तो किसी दूसरे को अपने आपको इस तरह थ्रस्ट नहीं करना चाहिए।

Shri Sezhiyan: What about the answer to my question?

Mr. Speaker: No, please.

Shri A. P. Sharma: Sir, the Deputy Minister has said

Mr. Speaker: If the hon. Member is just continuing that objection, then I will hear him; otherwise I will ask the Minister

Shri A. P. Sharma: It is about that only. The Deputy Minister has said that there has been a secret communication between the Home Ministry, the UPSC and the Law Ministry, and the substance of it is supposed to be published in the newspapers. Is it not the duty of the Home Minister or the Home Ministry to deny that it is not correct and not allow this misrepresentation to go round the country?

Mr. Speaker: I must ask the hon. Minister if, as Shri Sezhiyan says, even the Chief Minister of Madras has made that statement (Interruption)?

If even the Chief Minister of a State has made that statement, how can I hold that it is not in the public interest?

* **Shri Vidya Charan Shukla:** The Chief Minister has not made that statement.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): If it is so, then I will have to check it up. If it is so, it certainly goes beyond the limits which are imposed on revealing certain information.

Mr. Speaker: That he will find out, and I will give another opportunity for these questions to be asked. Next question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Question No. 65.

Shri Tyagi: Sir, on a point of order. This is full of insinuations—contact-women and all that. I suggest that this should not be permitted.

Mr. Speaker: Order, order. Why should a widower be so concerned with it?

Contactmen and Contactwomen

+

*65. **Shri Hari Vishnu Kamath:**

Shri Hem Barua:

Shri Surendranath Dwivedy:

Shri Nath Pal:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5200 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether reports have been received or called for from the various Ministries and Departments as to the nature of action taken against the undesirable contactmen and contact-women; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Hari Vishnu Kamath: Mr. Speaker, Sir, this question has been coming up in the House for the last one year—since September 1965 and we are now nearly at the end of July and the Government has adopted a hush-hush policy with regard to this matter. I do not know why they are fighting shy of contactmen and contactwomen, even their names. Here on the last occasion, on the 11th of May, in the last session.

Mr. Speaker: I am again surprised that bachelors are interested . . .

Shri Bhagwat Jha Azad: Bachelors and widowers are more concerned than married men.

Shri Hari Vishnu Kamath: I did not use the word myself; the Minister, Shri Hathi, used it. May I remind you, may I invite your attention to the fact that on the 11th of May, while answering a question on the subject, he said that the names of undesirable contactmen and contact-women—that was the first time he used that word; I do not know why Shri Hathi is fond of this word—as discovered by the CBI have been intimated to the Ministries and Departments concerned for such action as they may consider necessary. That was the previous question. As I said, for a year it has been coming up in this House. Today the question is about the follow-up with regard to that. Today he has said “No” to both questions.

Mr. Speaker: For the first “No”, and for the second “Does not arise”.

Shri Hari Vishnu Kamath: The last answer was in May and now we are at the end of July. Is the House to understand that the Departments and Ministries of the Government have taken no action whatsoever on the reports, on the names submitted by the CBI, or that they have not received the reports at all, in which

case what are the reasons for not taking such action, because these contactmen and contactwomen are doing liaison for certain big business houses and industrial Houses, the benefactors of the party in power? .

Mr. Speaker: The question should not be so long.

Shri Hathi: The question that has been asked by Shri Kamath is whether reports have been received. No report has been received. That is one part. The second question was whether they have been called for. They have not been called for. Therefore, the reply is "No". I will now explain why the reports have not been received or reports have not been called for. The reason is that we have sent these names to the various Departments and Ministries with instructions that these are the persons who are utilising their acquaintance and friendship with officers to influence them in their decisions, therefore a watch should be kept on them and that they should not be recognised as accredited agents. Now, when the question of meeting them comes, the officers should be careful that they do not associate themselves so closely as may ultimately . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: 'So closely' means what? Clarify yourself. Clarify your observation.

Shri Hathi: . . . as may lead to frequent visits by these people which may result in the decisions of the officers being influenced by these people. But they should not be allowed to meet these officers, and when the lists of accredited agents come from the firms these should be checked and these persons should not be recognised as accredited agents. These instructions we have sent. Therefore calling of reports is not necessary.

Shri Hari Vishnu Kamath: The answer on the last occasion, on the 11th May, was that the names had been sent for such action as the ministries and departments would consider necessary. Is the House to understand that the Home Ministry does not keep track of what they have been doing and just go to sleep over the matter whether the ministries and departments have taken action at all? Will the Minister lay on the Table of the House the names of these contactmen and contactwomen which have been forwarded to the ministries and departments; if not, the reasons therefor, and what limits have been prescribed for acquaintance or association?

Shri Hathi: So far as the Home Ministry is concerned, we do keep a watch on the activities of these persons and see that they do not use undue influence over officers. We also keep a watch on the officers, whether they meet them or not. That watch is being kept.

Shri Hari Vishnu Kamath: How can you keep a watch unless you get reports from the ministries? What is all this? Have you got a hundred eyes to see?

Shri Hathi: There are a few

Shri Hari Vishnu Kamath: 400 I know.

Shri Hathi: . . . and their activities can be watched.

Shri Hari Vishnu Kamath: How?

Shri Hathi: So far as the names are concerned, the disclosure of these names are concerned, the disclosure of these names would not be possible . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: In the public interest?

Shri Hathi: . . . because there are no specific charges against these people . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: Undesirable activity.

Shri Hathi: ... as having bribed or having malpractised.

Shri Tyagi: Do you take notice of them?

Shri Hathi: It is not a question of taking notice. As soon as they do certain acts, that is a different matter.

Shri Hari Vishnu Kamath: The CBI has held that they have indulged in undesirable practices. That is the CBI's finding.

Mr. Speaker: Shri Kamath cannot go on in this manner. The question was: When the Home Ministry has sent their names to the various ministries, has the Home Ministry tried to find out whether those ministries took any action on that?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): There is a system which enables us to get those names by keeping a close watch all over. We have a system of keeping a watch. It is not simply a question of a report, but we manage to see whether it is being carried out or not. It is not a question whether they say that this thing has been carried out or not; we are watching this.

Shri Hari Vishnu Kamath: Who is watching whom?

Shri Nanda: The same organisation.

Mr. Speaker: The organisation of the Home Ministry is watching it. But have the ministries also said that they have pursued the matter and they have taken action on that, whatever is required of them by the Home Ministry?

Shri Nanda: At a certain stage if that need arises, that will be done.

Shri Hari Vishnu Kamath: That is not an answer. He is shamefully evading the answer.

Shri Nanda: I am not evading it.

Mr. Speaker: He might say that the answer is not complete....

Shri Hari Vishnu Kamath: Unabashedly he is evading the answer.

Mr. Speaker: Shri Hem Barua.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let him answer. Is this the way he should conduct himself here? How can we know whether it is in the public interest, in the party interest or in his own personal interest?

Mr. Speaker: I have repeated the question.

Shri Hari Vishnu Kamath: You have repeated it, but what is the answer? He has said that what is necessary will be done. We should know what is the answer. What is this? Is it Parliament or his own house or residence? They are taking it so easy. We will not take it lying down.

Mr. Speaker: I am not asking him to lie down but to sit down at least.

Shri Nanda: There is no question of any evasion at all. These names were discovered by certain activities of our department. We have a system, an organisation, to get at this. We have an organisation to see whether the directions that we have given are being followed or violated. If we find that there is any kind of violation, when it comes to our notice, at that stage we will make further inquiries. That is a very clear answer; there is no evasion.

Mr. Speaker: There is only one thing that I might repeat. It is all right that the Home Ministry is doing all that is needed, but when it had been thought proper to send on to the ministries the list, would it not be desirable that even reports should be got from those ministries as to whether they are implementing what the Home Ministry wanted?

Shri Nanda: They are intended to be implemented.

Shri Hari Vishnu Kamath: What is this? He does not even stand properly. Let him stand up properly.

Shri Nanda: We can take further steps also. At the moment, to our satisfaction, the steps are being taken. We can take further steps also.

Mr. Speaker: The Question Hour is over. Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Wage Board for Journalists

*66. **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meema:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Wage Board for the working and non-working journalists has submitted its final report;

(b) if so, the recommendations thereof;

(c) the decision of Government thereon; and

(d) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Not yet.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Both these Wage Boards have to deal with important matters and they have to consider the view points of various interests. The work of the Boards is progressing and is now nearing its final stage.

Strike by Telephone Operators in Delhi.

*67. **Shri D. C. Sharma:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri Naval Prabhakar:

Shrimati Savitri Nigam:

Shri Bagri:

Dr. Ram Manohar Lohia:

Shri Madhu Limaye:

Shri Kishen Pattanayak:

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Shri Rameshwaranand:

Shri Raghunath Singh:

Shri Bibhuti Mishra:

Shri Subodh Hansda:

Shri S. C. Samanta:

Shri M. L. Dwivedi:

Shri Bhagwat Jha Azad:

Shri Gulshan:

Shri Onkar Lal Berwa:

Shri Basumatari:

Shri D. D. Puri:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether telephone service in Delhi was disrupted due to the strike by the Telephone Operators during May, 1966:

(b) if so, the cause of the strike;

(c) the loss suffered by the Department as a result thereof; and

(d) the action taken in the matter?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao):

(a) No. Delhi Telephone system is a fully automatic system. As such the local telephone service within the city was not affected by the strike of telephone operators on 24th and 25th May 1966. The Special Services, viz., Local Assistance and Directory Enquiry Services, were affected for 15 minutes on 25th May 1966 due to pen-down strike by operators staffing these services. In some of the local exchanges, the operators staffing the Test Desks which test subscribers' lines also resorted to pen-down strike for varying periods at different times. However, the maintenance work of telephone equipment and lines plant both indoor and outdoor was unaffected.

In respect of Trunk Service, the routes on which Subscriber Trunk Dialling is in operation were not affected. Similarly, incoming trunk traffic from major stations in the country to Delhi which are dialled by the distant trunk operators into Delhi Telephone System were not affected. Only trunk traffic originating in Delhi and traffic transited by the Delhi Trunk Exchange were affected due to pen-down strike by operators for $\frac{1}{2}$ hour on 24th and 1 hour on 25th May, 1966. However, during these periods the Supervisory staff, including the officers staffed some of the key positions to maintain the most essential services.

(b) One telephone operator was suspended in Delhi Gate Telephone Exchange on 24th May, 1966 for alleged indiscipline. The strike was in protest against that suspension.

(c) It is not possible to assess the exact loss of revenue. On trunk calls booked by Delhi subscribers the loss may be estimated as approximately Rs. 3,000/- for the total strike period.

(d) Disciplinary proceedings have been initiated against the telephone operator suspended in Delhi Gate Telephone Exchange.

Legislation to Control Private Educational Institutions

*68. **Shri H. N. Mukerjee:**
Shri Shree Narayan Das:
Shrimati Jayaben Shah:
Shri R. S. Pandey:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce legislation to control private educational institutions in the country with a view to curbing their malpractices;

(b) if so, the salient features of the proposed legislation; and

(c) when it is expected to be brought before the Parliament?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (c). A model Bill has been prepared and sent to the State Governments for necessary action and comments thereon, if any. The question of enacting this measure in respect of the Union Territories is under consideration.

(b) The Bill aims at regulating the establishment, maintenance and activities of private (unrecognised) educational institutions preparing students for recognised degrees, diplomas and certificates.

Fertilizer Plant, Mangalore

*69. **Shri A. S. Alva:**
Shri Baswant:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Dr. P. Srinivasan:
Shri Surendra Pal Singh:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shri Basappa:
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Hukam Chand
Kachhaviya:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether the FACT made a survey of Mangalore with a view to start a fertilizer factory there and whether they have submitted a feasibility report in that connection;

(b) whether Government have come to a conclusion to start a factory there by themselves or to give a licence to private parties; and

(c) when the factory is likely to be established?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes Sir.

(b) and (c). A letter of Intent has been issued to M/s International Development and Investment Co. Limited Nassau Bahamas/Duga Enterprises (P) Limited, New Delhi, on 20th June, 1966 who will submit detailed proposals within a period of six months.

राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता

* 70. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किर्शिग :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ इस उद्देश्य से बातचीत की है कि एक ऐसी आचार संहिता बनाई जाये जो मत्र को स्वीकार्य हो ;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सरकार ने ऐसी आचार संहिता बनाने के लिये राजनैतिक दलों के साथ कोई परामर्श नहीं किया, जो सभी को स्वीकार्य हो । राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन ने, जो मिनम्बर-अक्टूबर 1961 में बुलाया गया था और जिसमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, एक ऐसी संहिता बनाई थी; जिसकी एक प्रति मभा पटल पर रखी गई है । [पुस्तकालय में रखी, देखिये संख्या LT—6502 / 66] इस सम्मेलन का मत था कि विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस आचार संहिता के विकास तथा आपसी सहमति और परामर्श की कोई व्यवस्था करने का प्रयत्न जारी रखना चाहिये । राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् ने 1-2-1962 को अपनी बैठक में इस संहिता का पुनः समर्थन कर दिया और देश के विभिन्न राजनैतिक दलों पर जोर दिया कि वे इसे अपने सदस्यों के आचरण का नियंत्रण करने में प्रभावी ढंग से लागू करें ।

Automation in Industries

*71. श्री Shree Narayan Das: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made as to the extent to which automation has been introduced in institutions like L.I.C., banks, industries and other establishments causing unemployment to a large section of workers;

(b) if so, the result thereof;

(c) the number of licences issued so far for importing such automatic machines;

(d) whether Government have considered the problem of automation and consequent problems arising therefrom; and

(e) if so, the result thereof?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b). The L.I.C. are introducing electronic computers to replace their existing punched card equipment. There is no information with the Department of Labour about any workers thrown out of employment on account of the introduction of automation in L.I.C., banks, industries or other establishments; the Department has also made no assessment regarding the extent to which automation has been introduced in these institutions.

(c) The information is not available. Information obtained regarding imports of calculating, accounting and statistical machines, electrically operated during the year 1965-66 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6503/66].

(d) and (e). The question of rationalisation generally was considered at the 15th Session of the Indian Labour Conference held on the 11th-12th July, 1957. Certain conditions were accepted as *since que non* in any scheme of rationalisation. 'Automation' is one of the items on the agenda

Indian Labour Conference to be held in Delhi on 29th and 30th July, 1966.

पाटस्कर प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया

72. श्री विभूति मिश्र :
 श्री क० ना० तिवारी :
 श्री हेम बरुआ :
 श्री नाथ पाई :
 श्री हरि विष्णु कामत :
 श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
 श्री किशन पटनायक :
 श्री मधु लिमये :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्री श्रीनारायण दास :
 श्रीमती सावित्री निगम :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
 श्री रिशांग किशिंग :
 श्री कोल्ला वैक्या :
 श्री प्र० च० बरुआ :
 श्री भागवत झा आजाद :
 श्री म० ला० द्विवेदी :
 श्री स० च० सामन्त :
 श्री सुबोध हंसदा
 डा० राम मनोहर लोहिया :
 श्री बागड़ी :
 श्री उटिया :
 श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
 डा० रानेन सेन :
 श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
 श्री अशोक लाल बेरवा :
 श्री बसवन्त :
 श्री रामचन्द्र उलाका :
 श्री धुलेश्वर मीना :
 श्री वारियर :
 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
 श्री बासप्पा :
 श्री च० का० भट्टाचार्य :
 श्री बूजवासी लाल :
 श्री गोकुलानन्द महन्ती :
 श्री राम हरख यादव :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्रीमती रेणुका राय :

श्री बड़े :

श्री काशी राम गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने पाटस्कर आयोग प्रतिवेदन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बता दी है;

(ख) यदि हाँ, तो वह क्या है; और

(ग) पहाड़ी जिलों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). आसाम के पहाड़ी क्षेत्र आयोग के प्रतिवेदन राज्य सरकार तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के परामर्श से सरकार जांच कर रही है। आसाम सरकार की प्राथमिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है। उन्होंने आयोग की सिफारिशों के कुछ ममायोजन की सलाह दी है।

Infiltration by Nagas and Mizos in Manipur

- *73. Shri Hem Barua:
 Shri Hari Vishnu Kamath:
 Shri Surendranath Dwivedi:
 Shri Nath Pai:
 Shri Madhu Limaye:
 Shri Kishen Pattnayak:
 Shri Bagri:
 Dr. Ram Manohar Lohia:
 Shri Ram Sewak Yadav:
 Dr. L. M. Singhvi:
 Shrimati Renuka Barkataki:
 Shri Rishang Keishing:
 Dr. M. S. Aney:
 Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement made by the Chief Minister of Manipur to the effect that hostile Nagas

and Mizos are trying to link up and infiltrate into Manipur;

(b) whether it is also a fact that Nagas and Mizos have decided to cause widespread depredations in Assam also during the coming months; and

(c) if so, the steps taken to ensure safety and security to these States on the frontier?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No such statement has been made by the Chief Minister of Manipur.

(b) No such reports have been received.

(c) Necessary and possible security measures have been taken to ensure maintenance of law and order.

Nizam of Hyderabad's Refusal to Pay Property Tax

***74. Shri Eswara Reddy:
Shri Warrior:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Nizam of Hyderabad has refused to pay the property tax worth Rs. 40 lakhs to the Hyderabad Municipal Corporation on the ground that he has been exempted from payment of the tax under the Instruments of Accession;

(b) whether the Andhra Pradesh Government have referred this question to the Centre for advice; and

(c) if so, the advice given to the State in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). Government have no information whether H.E.H. the Nizam of Hyderabad has refused to pay the tax. However, Andhra Pradesh Government have

referred the question of reimbursement of Rs. 42.79 lakhs to the Municipal Corporation, Hyderabad on account of the property of H.E.H. the Nizam.

(c) The matter is under consideration.

Self-sufficiency in Kerosene and Light Diesel Oil

***75. Shri Linga Reddy:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing:
Shri Daljit Singh:
Shrimati Ramdulari Sinha:**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 47 on the 16th February, 1966 and state:

(a) the further steps taken to make the country self-sufficient as regards kerosene oil, diesel and petroleum; and

(b) the extent to which the demands of the States for the supply of Kerosene oil have been met?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) The Cochin refinery is to come on stream in August 1966. The 2nd-million tonne units of Koyali and Barauni Refineries are also to be commissioned by the end of this year. With the commissioning of this additional refining capacity, self-sufficiency in H.S.D. will be achieved and the gap between the demand and indigenous production of kerosene will be reduced to negligible proportions. As regards crude petroleum, exploration efforts are continuing. Government are also negotiating with certain firms for exploration in off-shore areas.

(b) The monthly State quotas of try of Home Affairs and Minister of about 10,000 tonnes since March, 1965.

Boundary Commission for Maharashtra and Mysore

- *76. Shri Bhagwat Jha Azad:
 Shri M. L. Dwivedi:
 Shri S. C. Samanta:
 Shri Subodh Hansda:
 Shri Yashpal Singh:
 Shri Prakash Vir Shastri:
 Shri Hukam Chand
 Kachhavaia:
 Shri Raghunath Singh:
 Shri Jagdev Singh
 Siddhanti:
 Shri Naval Prabhakar:
 Shri Maheshwar Naik:
 Shri R. Barua:
 Shri Liladhar Kotoki:
 Shri Utiya:
 Shri Madhu Limaye:
 Shri Kolla Venkaiah:
 Shri Sidheshwar Prasad:
 Shri Bibhuti Mishra:
 Shri K. N. Tiwary:
 Shri Vishwa Nath Pandey:
 Shri Bagri:
 Shri Ram Sewak Yadav:
 Dr. Ram Manohar Lohia:
 Shri Kishen Pattanayak:
 Dr. L. M. Singhvi:
 Shri Vasudevan Nair:
 Shrimati Renu Chakravartty:
 Shri D. C. Sharma:
 Shri Balgovind Verma:
 Shri Hari Vishnu Kamath:
 Shri Hem Barua:
 Shri Surendranath Dwivedi:
 Shri Nath Pai:
 Shri Alvares:
 Shri M. K. Kumaran:
 Shri Bade:
 Shri Basumatari:
 Shri Ramachandra Ulaka:
 Shri Dhuleshwar Meena:
 Shri P. R. Chakraverti:
 Shri Linga Reddy:
 Shri Kajrolkar:
 Shri Sivamurthi Swamy:
 Shri P. Venkatasubbaiah:
 Shri Ravindra Varma:
 Shri Kashi Ram Gupta:

Shri Basappa:
 Shrimati Savitri Nigam:
 Shri Brij Basi Lal:
 Shri H. C. Soy:
 Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether One-man Boundary Commission has been set up to go into the boundary dispute between Maharashtra and Mysore and Mysore and Kerala;

(b) if so, the terms of reference of this Commission; and .

(c) whether any time-limit has been fixed for the submission of its report?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) Government propose to set up a Commission to go into the boundary dispute between Maharashtra and Mysore.

(b) The Chief Ministers of Maharashtra and Mysore have been asked to evolve an agreed set of terms of reference for the Commission.

(c) The date by which the Commission is to report will be fixed when the Commission is set up, but the intention is that its report should be available in about a year's time.

India Office Library

- *77. Dr. L. M. Singhvi:
 Shri Sidheshwar Prasad:
 Shri Rishang Keishing:
 Shri M. L. Dwivedi:
 Shri Subodh Hansda:
 Shri S. C. Samanta:
 Shri Bhagwat Jha Azad:
 Shri Ramachandra Ulaka:
 Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the question of India Office Library and its materials has been solved; and

(b) if so, on what basis, and if not solved, the stage at which the matter stands at present?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) The Government of India have agreed to the proposal of the Government of U.K. regarding the law to be applied for the settlement of the question. The decision of the Government of Pakistan has not yet been received.

Royalty for Oil Exploration in Assam

*78. **Shri Bagri:**

Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Yashpal Singh:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shrimati Renuka Ray:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Assam Government have raised the royalty to be paid by the Oil and Natural Gas Commission and Oil India on their earnings from the oil fields in Assam; and

(b) if so, whether Government have agreed to the increase in the royalty to be paid to the Assam Government?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Statement of Chief Minister of U.P.

*79. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Hem Barua:
Shri Nath Pai:
Shri Surendranath Dwivedy:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1606 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether the authentic report of the statement made by the Chief Minister of U.P. has since been received; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Pakistani Agents in Kashmir

*80. **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri R. S. Pandey:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Kindar Lal:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani agents and gangs engaged in anti-national and subversive activities who have been traced during the last two months in Kashmir; and

(b) the steps taken to meet the situation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) It would not be in the public interest to disclose details, but two such agents were tried and convicted recently by the Sessions Judge, Srinagar.

(b) Adequate steps are in hand to deal with anti-national elements.

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

*81. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्री लिंग रेड्डी :
 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
 श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 9 मार्च, 1966 के तारंकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक अखिल

भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक योजना को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) (क) से (ग). अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के बारे में मुख्य न्यायाधीशपतियों के सम्मेलन के मुद्दाव को राज्य सरकारों के पास उनके विचार जानने के लिये भेजा गया है और उनके विचार प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायगी।

कैरों हत्याकांड

*82. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री जगदेव सिंह सिद्धाती :

क्या गृह-कार्य मंत्री 2 मार्च, 1966 के ताराकित प्रश्न संख्या 303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा, करेंगे कि :

(क) कैरों हत्या काण्ड के बारे में की जा रही जांच के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अरू तक इस बारे में किसी निर्णय पर न पहुँचने के क्या मुख्य कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा, प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जिन पांच व्यक्तियों पर मन्देह है उनमें से एक फरार है और चार गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इन चार में से एक भेदी साक्षी बन गया है और सिर्फ तीन के खिलाफ रोहतक के चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में 1-5-66 को मुकदमा दायर किया गया। मुकदमों की कार्यवाही को रोक दिया गया क्योंकि एक

अभियुक्त ने रोहतक के चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से मुकदमा बदलवाने के लिये पंजाब उच्च न्यायालय को अर्जी दी थी। उसकी अर्जी नामंजूर हो गई है। अब अन्य दोनों अभियुक्तों ने मामले को पंजाब से बाहर बदलवाने के लिये उच्चतम न्यायालय को अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी मंजूर कर ली गयी है और आशा है अगस्त, 1966 के पहले हफ्ते में यह अर्जी सुनवाई के लिये पेश होगी।

Smuggling on our Border

*83. **Shri Liladhar Kotoki:**

Shri N. R. Laskar:

Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a team of senior border police officials of India and Pakistan held a meeting at Wagah to curb the smuggling on our border; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes. Senior police officials of India and Pakistan met at Wagah on 29-6-66 for the Border officials' monthly meeting under the Ground Rules;

(b) Among others, the problem of smuggling was discussed. The two sides agreed to tighten anti-smuggling measures in the border area.

Primary Education in Calcutta

*84. **Shri Madhu Limaye:**

Shri Kishen Pattanayak:

Shri Bagri:

Dr. Ram Manohar Lohia:

Shrimati Renu Chakravartty:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5390-C on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether Government have since received the 'detailed Report'

from the State Government on the implementation of the objective of free and compulsory primary education in Calcutta and other urban areas of West Bengal;

(b) the proportion of children, of school-going age without schooling in these centres; and

(c) the steps that the State Government propose to take and the Centre proposes to recommend to the State Government?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (c). The State Government have reported that they have discussed the matter with the Calcutta Corporation authorities who have agreed to impose education cess for the purpose and are preparing a scheme for being submitted to the State Government for initiating legislation for the provision of free and compulsory education thereafter.

(b) The percentage of children in age group 6-11 not attending schools in Calcutta Corporation area is 37.91. Similar figures for other urban areas separately are not available.

दिल्ली में पाषाणों (काउंसलर) की संख्या में वृद्धि

* 85. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के पाषाणों की संख्या 80 से बढ़ा कर 100 की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अनुसूचित जातियों के पाषाणों की संख्या कितनी है; और

(ग) निगम में कितने एलडरमैन रखने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपायंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) तेरह ।

(ग) इस समय दिल्ली नगर निगम में एलडरमैन की संख्या छः है । एलडरमैन की संख्या बढ़ा कर दस करने का विचार है ।

Joint Exploration for Oil in Off-Shore Areas

*86. **Shri Vasudevan Nair:**

Shri Warrior:

Shri Kindar Lal:

Shri Vishwa Nath Pandey:

Shri Nambiar:

Shri Bhagwat Jha Azad:

Shri M. L. Dwivedi:

Shri S. C. Samanta:

Shri Subodhu Hansda:

Shri Bagri:

Shri Kishen Pattnayak:

Dr. Ram Manohar Lohia:

Shri Ram Sewak Yadav:

Shri Yashpal Singh:

Shri Madhu Limaye:

Shri R. S. Pandey:

Shrimati Renuka Barkataki:

Shri Bishwanath Roy:

Shri Bade:

Shri Kashj Ram Gupta:

Shri Jashvant Mehta:

Shri A. K. Gopalan:

Shri Dinen Bhattacharya:

Shri M. N. Swamy:

Shri Surendra Pal Singh:

Shri Dighe:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether negotiations with foreign Oil Companies for joint exploration for oil in off-shore areas have been completed; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Protected Areas in Ukhrul in Manipur

*87. **Shri N. R. Laskar:**

Shri Liladhar Kotoki:

Shri Gokulananda Mohanty:

Shri Krishna Pal Singh:

Shri Bibhuti Mishra:

Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Basumatari:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Braj Bihari Mehrotra:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Chief Commissioner of Manipur has declared 34-check posts as protected areas in Manipur in the hill sub-division of Ukhrul;

(b) whether, while adopting these measures, sufficient provision was made for the security and safety of the local people from the rebels; and

(c) whether Government propose to introduce such schemes in Nagaland areas also?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) 13 security posts in Ukhrul sub-division, 11 in Tamenglong sub-division and 11 in Mao-Sadar sub-division have been declared as protected areas under the provision of the West Bengal Security Act, 1950 with effect from the 26th May, 1966. In addition 6 security posts in Churachandpur sub-division and 1 post in Jiribam sub-division have also been declared as protected area under the said Act with effect from the 7th June, 1966. Thus, in all 42 posts have been declared as protected areas.

(b) Declaration of certain places as protected areas would not in itself call for a special provision for the security and safety of the local people from the rebels. However, necessary and possible steps have been taken for the safety of the local people.

(c) The Government of Nagaland have no such proposal at present.

Grades of University Teachers

*88. **Shri Kolla Venkaiah:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattanayak:
Shri Bagri:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing:
Shri Vasudevan Nair:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the States which have adopted the new grades of pay of University teachers as proposed by the Centre;

(b) the States which have expressed difficulties in the adoption of the new grades and the nature of the difficulties expressed by them;

(c) the opinion expressed by the various University teachers' organisations regarding the new grades of pay; and

(d) the action proposed to be taken in view of the opinion expressed by them?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Assam, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh and West Bengal have accepted in principle the revised scales of pay.

(b) No difficulties as such in the adoption of the new grades have been expressed by any State Government so far. However, most of the States, which have sent replies, have sought clarifications for taking a decision in the matter.

(c) The various University teachers' organisations have generally welcomed the new grades of pay and some of them have suggested certain modifications.

(d) The new grades of pay have been recommended by the University Grants Commission after a great deal of deliberation and it is not proposed to revise them further.

Birla Bhawan, Delhi

***89. Shri Utiya:
Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattanayak:**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question Nos, 572 and 416 on the 16th March, 1966 and 24th November, 1965 respectively and state:

(a) whether he has seen the report published in the "Patriot" regarding Government's taking over the Birla Bhawan in Delhi on the occasion of the Mahatma Gandhi's Centenary; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The report is not correct.

N.D.S. Instructors

***90. Shrimati Renu Chakravartty:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any final decision has been taken in regard to the keeping of the National Discipline Scheme Instructors on an All India cadre; and

(b) if not when a decision is likely to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir, the matter is still under examination in consultation with the State Governments.

(b) As soon as the consultation with State Governments is completed which will not take much time now.

Class I Posts for Scientific Work

265. Shri Kajrolkar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Class I and higher posts sanctioned during the

last 3 years in the Ministry of Home Affairs and its attached and subordinate offices for scientific and technical work, rank-wise;

(b) how many of these posts exist in the Junior Class I scale for which no provision has been made by the Ministry for promotion to the Senior Class I scale; and

(c) how many of the posts mentioned in part (b) above have been filled actually by direct recruitment from the open market by advertisement through the Union Public Service Commission and for how many of these selections were made more than four years ago?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The requisite information is being collected from attached and Subordinate Offices and will be laid on the table of the House as soon as possible.

यातायात नियमों का उल्लंघन

266. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में यातायात नियमों के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 59,443.

(ख) 10,59,743 रु० ।

दिल्ली प्रशासन में अष्टाचार के मामले

267. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में दिल्ली प्रशासन के सतर्कता विभाग ने दिल्ली प्रशासन के कितने

कर्मचारियों का अष्टाचार के मामलों में हाथ होने का पता लगाया है; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सजा दी गई है और कितने कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अतिरिक्त मंत्रालय में अतिरिक्त संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 284 (1-1-1965 से 30-6-1966 तक की अवधि के लिये)

(ख) सजा दी गई	10
विभागीय कार्यवाही की गई	50

Police Firing

269. **Shri Warrior:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of times the police had to resort to firing to control mobs in different parts of the country since the 15th August, 1947;

(b) the number of people killed and injured in those firings; and

(c) the amount of compensation paid to the families of those killed or injured in the firings?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Arts and Technical Colleges in India

269. **Shri Warrior:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the number of arts and technical colleges in the country at present;

(b) the number of students studying in these colleges; and

(c) the number of those colleges which are run by private parties or institutions?

269 (Ai) LSD—3.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): According to the latest available information for the year 1963-64, the position is as follows:—

(a) number of colleges teaching arts subjects—1,174, number of engineering and technological colleges—105;

(b) number of students reading in colleges for arts subject—8,08,994; number of students reading in engineering and technological colleges—63,176; and

(c) number of colleges teaching arts subjects and run by private bodies—943, and number of engineering and technological colleges run by private bodies—50.

Post Offices in Rented Buildings

270. **Shri Warrior:** Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the number of Post Offices in the country as on the 31st March, 1966;

(b) the number of those Offices which are accommodated in the private rented buildings; and

(c) the annual rent being paid for these private buildings?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) 96,936.

(b) 11,159.

(c) Rs. 86,24,784 (approx.)

Financial crises of Vikram and Saugar Universities

271. **Shri M. K. Kumaran:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the serious financial crisis faced by the Vikram and Saugar Universities;

(b) whether there is any proposal that the Union Government should take over these Universities to run them as Central Universities; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

International Hockey Tournament

**272. Shri Braj Bihari Mehrotra:
Shri Ram Harkh Yadav:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the International Hockey Tournament at Hamburg (W. Germany) has concluded;

(b) if so, India's achievements therein; and

(c) the position of Pakistan in the tournament?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):
(a) Yes, Sir. The Tournament concluded on the 22nd May, 1966.

(b) India stood first in this Tournament.

(c) Pakistan finished at the fifth position in this Tournament.

Coaching Assignment for Ghana

**273. Shri Braj Bihari Mehrotra:
Shri Ram Harkh Yadav:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Shri Sarpal Singh, the distinguished coach of the National Institute of Sports, Patiala has been offered a coaching assignment in Ghana; and

(b) if so, the details of the assignment and when he is likely to take up the job?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The assignment is for a period of six months. Shri Sarpal Singh left for Ghana on 4-6-1966.

Parcels found missing at Kerakot P.O. (U.P.)

274. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether 51 inward Parcels and other valuable materials belonging to the Postal Registration Department were found missing from the Kerakot Post Office in Jaunpur (U.P.) recently;

(b) if so, the details of the loss; and

(c) the result of the enquiry, if any, set up to investigate into the incident?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao):

(a) Actually a registered bag containing 51 insured letters and other articles despatched by Jaunpur RMS enclosed in a mail bag on 24-5-66 was not found when the mail bag was opened at Kerakot post office.

(b) The contents of the missing registered bag were 51 insured letters, 28 registered letters and some money orders. The amount of loss ascertained so far is Rs. 9648.

(c) Departmental enquiry has been concluded without yielding any clue for tracing the culprits. The police had been informed as soon as the loss was noticed and their investigations are in progress.

Plantation Labour

275. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether the Kerala Government have received the report of the high level conference held to discuss the wage demand of the plantation labour in Kerala;

(b) whether Government are aware that the plantation labour in Kerala have threatened to go on strike to get their demands fulfilled; and

(c) if so, the steps taken by Government to raise the wages of their employees and to maintain industrial peace in the plantation area?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes.

(b) There has been a partial strike since 4-7-1966 in the Rubber plantations.

(c) The recommendations of the Tea Wage Board have been accepted by the Government of India and are now before the managements of tea plantations for implementation. The Rubber Wage Board has not yet submitted its recommendations but it is understood that their recommendations will be before the Government of India very soon. The question of revision of wages for workers in plantations and maintenance of industrial peace in the plantations area have always been under the active consideration of Government. Recently the Association of Planters of Kerala issued a circular announcing an enhancement of 0.24 paise to both male and female workers effective from 1-4-1966 to be adjustable against final recommendations of the Wage Board.

Unemployed Graduates

276. Shri Sham Lal Saraf: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the recent publication, in numerical figures of the Lists of Graduate and Post-Graduate scholars in Arts and Humanities has revealed that an appreciable number of them are unemployed and their talent goes waste; and

(b) the steps under contemplation to utilise their talent and services?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The reference is presumably to the article

published in YOJANA of 29th May, 1966 on "OUR MANPOWER IN ARTS AND HUMANITIES". This gives the number of graduates at various levels in the different fields in Arts and Humanities and the comparative figures in Science. No conclusion has been drawn in regard to the unemployment of graduates in Arts and Humanities; in fact the article ends up by saying that the question of employment and utilisation of the personnel would need to be studied in depth.

Central University in Kerala

277. Shri M. K. Kumaran: Will the Minister of Education be pleased to state the stage at which the proposal to establish a Central University in Kerala stands at present?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): There is no proposal to establish a Central University in Kerala. The University Grants Commission has only accepted the proposal made by the State Government for the development of two post-graduate centres at Ernakulum and Calicut and is of the view that a beginning should be made with one centre.

'Kerala Bandh' Cases

278. Shri A. V. Raghavan: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether he would lay on the Table a statement giving the details of cases registered in the State of Kerala in connection with the 'Kerala Bandh' held on the 28th January, 1966 with reference to each police station;

(b) whether there is any proposal to withdraw any of the pending cases; and

(c) whether the recommendations of the Consultative Committee of Kerala Legislators have been fully implemented in the matter of withdrawing the cases?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) It will be difficult to do this and in view of answers to (b) and (c), it may not also be necessary.

(b) All pending cases against students have been either dropped or asked to be withdrawn.

(c) Yes, Sir.

Long Term Prisoners in Kerala

279. Shri A. V. Raghavan: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of long-term prisoners undergoing imprisonment in the State of Kerala;

(b) the number of such prisoners as have been convicted by courts which are now within the Jurisdiction of the Madras and Mysore High Courts;

(c) whether there is any proposal to release a few long term prisoners; and

(d) if so, when the decision will be taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) 1268.

(b) 18 and 13 respectively.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

N.P.O. Calicut

280. Shri A. V. Raghavan: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the progress made in establishing a night Post Office at Calicut in Kerala; and

(b) when the same will start functioning?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) and (b) During 1965-66 we have opened a night Post Office at Trivandrum. The question of opening a Night Post Office at Calicut will be examined along with other such proposals for other States to be considered during 1966-67.

Training Centre

281. Shri Vasudevan Nair: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to establish a centre at Trivandrum, for the training of Telegraph Inspectors, mechanics and telephone operators;

(b) if so, when the centre will begin functioning; and

(c) how many persons will get training every year at the centre?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes.

(b) A suitable building has been taken on rent and the training centre will start functioning in about a month's time.

(c) Approximately 250 trainees a year.

Honorary Teachers in Kerala Schools

282. Shri Vasudevan Nair: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Kerala Education Advisory Board has recommended a scheme of appointing honorary teachers in schools; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The scheme provides for allowing not more than three Honorary teachers to work in a School, after specific prior approval of the District Educational Officer. The Honorary teachers will be expected to take up specified assignments and to work under the administrative control of the Headmaster.

War service Candidates in Public Undertakings

283. Shri Pottekkatt:

Shri A. V. Raghavan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the rules framed to confer the benefit of providing an advance increment to war service candidates is not applicable to such candidates appointed in public undertakings and other statutory undertakings; and

(b) the steps taken to confer this benefit to all eligible employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) and (b): The orders conferring the benefit relate only to those war service candidates who have been appointed to Civil posts in the Government. Public undertakings and statutory bodies are not governed by these orders.

Deportation of British Planter

284. Shri Ram Sewak Yadav:

Shri Madhu Limaye:

Shri Brij Basi Lal:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a British Planter in North Bengal has been asked to leave India for his activities prejudicial to the country's security;

(b) if so, the nature of his activities; and

(c) whether similar orders are being served on foreign planters engaged in encouraging secession in North-Eastern India, including Assam and Nagaland?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence (Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). Information is being collected from the Government of West Bengal and will be laid on the Table of the House, as soon as it is received.

Firing by East Pakistan Rifles

285. Shri Hem Barua:

Shri Hari Vishnu Kamath:

Shri Surendranath Dwivedy:

Shri Nath Pai:

Shri D. C. Sharma:

Shri Hukam Chand

Kachhavaiya:

Shri Raghunath Singh:

Shri Bagri:

Shri Bhagat Jha Azad:

Shri Sonavane:

Shri Gulshan:

Shri Basumatari:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that East Pakistan Riflemen fired on Indian Border Security Forces in the Govindapur area of Cachar, Assam on the morning of the 17th May, 1966; and

(b) if so, the details of this firing and the reasons behind this action of Pakistan?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). On 17th May 1966 at 0745 hours, seven Pakistani nationals supported by an EPR patrol party intruded 30 to 40 yards into Indian territory in Govindapur village and attempted to plough the land there. When our patrol party went to apprehend the intruding Pak nationals, EPR patrol fired three rounds and our patrol had to return the fire on which the Pak nationals fled away from the area.

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान धार्मिक स्थानों को हुई क्षति

286. श्री हुकम चन्द कछड़ा :

श्री रामेश्वरानन्द :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री दंडे :

श्री काशीराम गुप्त :

श्री दे० जी० नाटक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने सात मन्दिर, दो गुरुद्वारे और एक गिरजाघर नष्ट कर दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेन्ट पाल चर्च पर बम गिरने से लगभग 5 लाख रुपये की हानि हुई है ;

(ग) मन्दिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के नष्ट होने से कितनी क्षति हुई है ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) देश के गांवों तथा धार्मिक स्थानों को पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई गई क्षति का पूरा ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) हमें प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले संघर्ष में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण कुछ मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंची। ऐसे धार्मिक पूजा स्थलों की ठीक-ठीक संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जिनको क्षति पहुंची।

(ख) जी हां।

(ग) अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 लाख रुपये के लगभग क्षति का अनुमान है।

(घ) इस बारे में भारत सरकार द्वारा किली खास कार्यवाही का विचार नहीं है।

(ङ) धार्मिक स्थानों की क्षति का अनुमान पहले ही प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दे दिया गया है। गांवों की क्षति के बारे में सूचना एकत्रित की जायगी और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पाकिस्तानी घुसपैठ

287. श्री हुकम चन्द कछड़ा :

श्री रामेश्वरानन्द :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में त्रिपुरा-कोमिला सीमा के फूल कुमारी वन में एक पाकिस्तानी दस्ता घुस आया और उसने वृक्ष काट डाले ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) वृक्ष काटने के कारण होने वाली हानि की ठीक-ठीक राशि ज्ञात नहीं। किन्तु हमारी और कोई जन हानि नहीं हुई।

(ग) पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपराधियों का पता चलाये और भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण और अपराधों की रोक थाम के लिये कदम उठाये।

पाकिस्तान के साथ तार तथा टेलीफोन सम्पर्क

289. श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौर तथा अमृतसर के बीच डाक-तार तथा टेलीफोन सम्पर्क पूरी तौर पर स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभागों में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) डाक सेवाएं फिर से चालू की जा चुकी हैं, किन्तु अमृतसर और लाहौर के बीच तार तथा टेलीफोन लाइनें आंशिक रूप से ही चालू की जा सकी हैं।

(ख) तथा (ग).

डाक-संचार :

11 फरवरी, 1966 से भारतवर्ष और पाकिस्तान के दोनों क्षेत्रों के बीच डाक सेवाएं पूरी तरह चालू की जा चुकी हैं। सितम्बर, 1965 में सेवाओं के निलम्बित होने से पूर्व पश्चिमो पाकिस्तान के चिर तथा वहां से भेजी गई डाक अमृतसर और लाहौर के बीच रेलगाड़ी द्वारा भेजी जाती थी और लाहौर पर उपरोक्त विनियम किया जाता था। अमृतसर और लाहौर के बीच रेलगाड़ियों के द्वारा चालू होना 15 डाक का विनियम फिरोजपुर के निरुद्ध दुर्घटनाओं के पुनः स्थापित हो जाने के कारण है।

दूर संचार सुविधायें

भारत और पाकिस्तान के बीच (अमृतसर लाहौर मार्ग) तार तथा टेलीफोन सम्पर्क आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो चुके हैं।

अमृतसर और लाहौर के मध्य कुल मिलाकर तांबे के तार के 4 युग्म वास्तव में मौजूद थे, लेकिन सितम्बर, 1965 के संघर्ष के दौरान उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। फरवरी, 1966 के दौरान अमृतसर-लाहौर के बीच तांबे के तार का एक युग्म पुनः चालू कर दिया गया। अमृतसर-लाहौर तथा नई दिल्ली-लाहौर के बीच 11 फरवरी, 1966 को सीधे बोलचाल परिपथ की व्यवस्था कर दी गई। नई दिल्ली तथा लाहौर के बीच 14 फरवरी, 1966 को तार निर्गम मार्ग की स्थापना कर दी गई।

दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद

290. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री रिशांग किशिंग :

श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री किशन पटनायक :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मोना :

क्या शिक्षा मंत्री 27 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1393 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा की गई मांग पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) :

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली शिक्षा निदेशक, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका तथा प्राइवेट सहायता-प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ शिकायतों और साथ ही तथाकथित कुछ तंग करने के मामलों की जांच,

अन्य बातों के साथ साथ करने के लिए एक वार्षिक आयोग नियुक्त करने की परिषद को मांग नामंजूर नहीं की गई है।

Central High Court

291. Shri D. C. Sharma:
Shri Warrior:
Shri P. C. Borooah:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether a proposal to constitute a Central High Court to eliminate delays and arrears in Courts is under the consideration of Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the stage at which the matter stands at present?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). There is no such proposal yet before the Government. The Law Minister is exploring the methods by which the High Courts may be relieved of the arrears and the cases can be decided expeditiously.

Indian Institute of Petroleum

293. Shri D. C. Sharma:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether India and UNESCO have signed a plan of operation for \$212.5 million project to strengthen the Refining Division of the Indian Institute of Petroleum and to establish a petro-chemical division at the institute; and

(b) if so, the broad features of the plan?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. A Plan of Operation for the establishment of a Refining and Petro-Chemical Division at the Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun has been signed on 17th May, 1966 between the Government of India and the United Nations Development Programme (Special Fund) at an estimated cost of US \$2,504,550. UNESCO will be the Executing Agency on behalf of the U.N. Development Programme.

(b) The broad features of the Plan are given below:—

1. The duration of the Plan of Operation is 4 years.

2. The contribution of U.N. Development Programme will be US \$1,254,550 as under:—

	US \$
(i) 3 Experts (Advisers)	33,200
(ii) Fellowship	56,000
(iii) Equipment and Supplies	4,95,000
(iv) Personal services	5,02,850
(v) Travel cost	28,8000
(vi) Other Expenditure	1,38,700
	<hr/> 12,54,550

3. The Government of India's counterpart contribution in kind will be Rs. 59,52,500.00.

Master Tara Singh's Views

294. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to Master Tara Singh's insistence on a Sikh majority area in reply to his warning;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A close watch is being kept in the matter.

Petro-Chemicals Complexes

295. Shrimati Renu Chakravartty:
Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether any offer has recently been received from foreign private companies for collaboration in setting up of petro-chemical Complexes in the country;

(b) if so, the names of those Companies;

(c) the terms of the offers; and

(d) Government's reaction thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Apart from the proposals received for collaboration in the Gujarat Petro-chemical Complex towards the end of 1964, of which the House is already aware there has been no recent offer from any foreign private companies.

(b) to (d). Do not arise.

Education Commission Report

296. Shri H. N. Mukerjee:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri E. S. Pandey:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri R. Barua:
Shri Linga Reddy:
Shri P. E. Chakraverti:
Shri Sideshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shrimati Jyotsna Chanda:
Shri Kolla Venkalah:
Shri Ramchandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri D. C. Sharma:
Shri P. C. Boreeah:

Shri C. K. Bhattacharyya:
Shri D. D. Mantri:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Basappa:
Dr. P. Srinivasan:
Shri Gulshan:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Madhu Limaye:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri Muthiah:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Lakshmu Bhawani:
Shri Jashwant Mehta:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Education Commission has submitted its report to Government;

(b) if so, the main recommendations contained in the report; and

(c) the decisions taken thereon?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6504/66]

(c) The recommendations are under consideration of Government.

सशस्त्र नागाओं द्वारा हमला

298. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र नागाओं ने 15 मई, 1966 को प्रयवा ब्लॉक के भ्रामपास मनीपुर के उसमल सब-डिवीजन में एक गांव पर हमला किया था :

(ख) क्या इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथो) : (क) जी हाँ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है। किन्तु यह सब है कि नागा विद्रोहियों को इस इलाके में घूमते देखा गया है।

(ग) उपयुक्त प्रतिरोधक उपाय किये गये हैं और किए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल

299. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये अखिल भारतीय आधार पर ऐसे स्कूल तथा कालेज खोले हैं जिनमें पाठ्यक्रम तथा शिक्षा का माध्यम एक भाषा होगा;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्थानीय स्कूलों के अलावा, स्थान उपलब्ध होने पर केन्द्रीय स्कूलों में भी (अभी तक स्थापित ऐसे स्कूलों की संख्या 100 है) उन्हें दाखिल किया जाता है। बहुत से मामलों में, सरकारी उपाय इन बच्चों के लिए स्कूल चलाने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं।

महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह

300. श्री रिशांग किशिंग :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति को गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया है;

(ख) क्या इस समिति को राज्य सरकारों/जनता से भी धन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस बारे में समिति ने अब तक क्या कार्यक्रम तैयार किया है और क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) एक लाख रुपये।

(ख) जी हाँ।

(ग) समिति द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम और उठाए गए कदम विवरण में दिए गए हैं। जो सभा पटल पर रखा गया है [पुस्तकालय में रखा। देखिये संख्य एल० टी-6505/66]

हृदिया तेल शोधन कारखाना

301. श्री दिगो :

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

श्री वारियर :

श्री हुक्म चन्द कछवाय :

श्री रामेश्वरानन्द :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

श्री किन्धर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
 श्री राम सहाय पाण्डेय :
 श्री रा० बरूआ :
 श्री श्रींकार लाल बेरवा :
 श्री च० का० भट्टाचार्य :
 श्री दिने :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस देश के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है जिस के सहयोग से इन्दिया तेल शोधन कारखाना स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अल्लमसेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Unscrupulous Contractors

302. **Shri Hem Barua:**
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Nath Pai:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government are preparing country-wide lists of unscrupulous contractors, suppliers and clearing agents; and

(b) if so, the steps taken to make the survey foolproof as also whether any follow-up action is contemplated?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) In accordance with the programme for Vigilance and Anti-Corruption work in 1966, Central Government Departments and Corporate Undertakings are preparing lists of unscrupulous

contractors, suppliers firms and Clearing Agents.

(b) The Departments and Undertakings have been instructed to exercise due care in the preparation of these lists. The following action will be taken in respect of those on the lists: (i) Copies of the lists will be circulated to all Central Government Departments and Undertakings with directions to instruct all officers to be cautious in their dealings with such parties. (ii) Closer check and scrutiny of applications received from such parties and of works or business transactions undertaken by them. (iii) Collection of specific instances of malpractices by these parties with a view to start open enquiries against them.

Naga Plan of Sabotage in Assam and Manipur

303. **Shri Hem Barua:**
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Nath Pai:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain papers recovered from the Rev. Michael Scott on the eve of his departure for London, disclosed Naga plan for sabotage in Assam and Manipur; and

(b) if so, the nature of this plan and the measures taken to prevent further hostile activities by these people in the areas concerned?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Foreign Agents in Northern Bengal

304. **Shri Hem Barua:**
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Nath Pai:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Madhu Limaye:

Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:
Shri Kishen Pattanayak:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain foreign agents are actively working at present in the hill districts of Northern Bengal to spread disaffection against Government amongst the hill people there as in Assam;

(b) if so, whether this fact has been brought to the notice of Government by the State Government; and

(c) the measures proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) and (c). The question does not arise.

Explosion of H-Bomb by China

305. **Shri Surendranath Dwivedy:**
Shri Hem Barua:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Nath Pai:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the news of the explosion of a H-Bomb by China has been hailed with great enthusiasm by a section of the Indian people, particularly by a political party; and

(b) if so, the nature of this enthusiasm and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). Government of India have received reports that the explosion of an H-Bomb by China has been welcomed by the Communist Party of India (Left). The spokesmen of that party

have justified manufacture of thermonuclear bombs by China in the face of the American threat of atomic war against her, as they put it.

Situation in Mizo Hills

306. **Shri Surendranath Dwivedy:**
Shri Hem Barua:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Nath Pai:
Shri P. C. Borooah:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Gulshan:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Yashpal Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand

Kachhavaia:

Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri H. C. Soy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri E. S. Pandey:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Kindar Lal:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Maheswar Naik:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri E. Barua:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Kajrolkar:
Shrimati Jyotsna Chanda:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Axad:
Shrimati Renu Chakravarty:
Dr. M. S. Aney:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the latest situation in the Mizo Hills district of Assam and whether the district has been brought completely under civil administration by now;

(b) whether it is a fact that the Mizo rebels are at present getting active support of Pakistan and China in their rebellion against India; and

(c) if so, the nature of the support and the steps taken by Government to meet the situation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Mizo Hills District has remained under civil control throughout. Peace has been restored in most of the areas. The MNF have, however, stepped up their activities recently and some clashes with the Police and the Army have taken place.

(b) While Mizo rebels have received assistance from Pakistan, Government are not aware of any support from China.

(c) The MNF volunteers went to Pakistan in March, 1966, to seek both refuge and aid. They have been going to Pakistan for undergoing training and for bringing arms. Protests have been lodged with the Pakistan High Commission against the supply to the MNF of arms and equipment and other facilities.

Government Officials captured by Mizo Rebels

307. **Shri Surendranath Dwivedy:**
Shri Hem Barua:
Shri Nath Pai:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. Barua:
Shri N. R. Laskar:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri C. K. Bhattacharyya:
Shri Gokulananda Mohanty:
Shrimati Renuka Barkataki:
Dr. M. S. Aney:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently Mizo rebels freed the Government Officials captured by them during the rebellion from "somewhere in Pakistan";

(b) if so, the number of Officers released and whether anybody is left behind or "missing"; and

(c) whether Government have been able to get any information about the future strategy of the Mizo rebels from the released Officers and if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) Fifty-six officials have so far been released by the Mizo rebels and twenty two officials are still missing.

(c) It will not be in public interest to disclose the information.

Exchange of Half-burnt currency notes by Mizos

308. **Shri Surendranath Dwivedi:**
Shri Hem Barua:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Nath Pai:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 12th May, 1966 some Mizos came to the Reserve Bank of India at Gauhati with bundles of half-burnt currency notes for exchange;

(b) if so, the amount involved; and

(c) the reasons why the Police at Gauhati was not informed by the Bank authorities and thus the Mizos were allowed to escape?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) Notes of the value of rupees seven hundred and fifty were exchanged.

(c) These half-burnt Government Currency Notes belonged to M/s. Pachhunga and Sons of Aijal Bazar and were reportedly burnt in March, 1966 due to MNF action. As the notes were genuine, the Agent Reserve Bank of India, Gauhati, did not think it necessary to inform the police. The police, however, interrogated the persons involved. The

result of enquiry did not call for further action.

'Officer-oriented' Scheme

**309. Shri H. C. Linga Reddy:
Shri P. B. Chakraverti:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the extent to which the Office Orientation Economy has been successful in the various Ministries and Departments of the Government of India in which it was introduced so far at the Central level; and

(b) the number of people retrenched and the alternative jobs found for them along with the amount saved thereby?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence (Shri Hathi): (a) It is presumed that reference is to reorganisation according to an 'officer-oriented'

ed' pattern. So far this has been introduced in the following offices:—

Ministry of Works, Housing and Urban Development

(i) Works division with effect from 18th October, 1965.

(ii) Estates division with effect from 1st July, 1966.

Directorate General of Supplies and Disposals

(iii) Oil, paints and chemicals directorate with effect from 1st March, 1966.

(iv) Timber, wool and leather directorate with effect from 1st April, 1966.

The reorganised system has not worked long enough for conclusive results to be evident.

(b) The number of persons rendered surplus, the manner of their absorption and the economy involved is displayed below:—

Name of division	Post	No. declared surplus	No. Absorbed identical posts	No. Absorbed as UDC.	Expected amount of saving (yearly)
(i) Works	Asstt.	19	16	3	Rs. 1,26,000
(ii) Estates	Asstt.	8	7	1	} Rs. 16,400
	UDC.	1	1	..	
	LDC.	2	2	..	
(iii) &					
(iv) DGS & D	Asstt.	19	..	19	Rs. 1,05,000

Border Security Police

**310 Shri H. C. Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri E. S. Pandey:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri R. Barua:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the extent to which the Border

Security Police has been introduced in the Border States of India; and

(b) how the same has been working since its introduction?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Border Security Force has been introduced in all States bordering Pakistan.

(b) Within the short time it has been in existence, it has built up its organisation on proper lines and is discharging its duties satisfactorily.

Red Tapism in the Administrative Machinery

311. **Shri H. C. Linga Reddy:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri R. S. Pandey:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri R. Barua:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri N. R. Laskar:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Yashpal Singh:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing:
Shrimati Renuka Ray:
Shri Bihuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Kajrolkar:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri Imbichibava:
Shri Laxmi Dass:
Shri Nambiar:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the extent to which red tapism has been cut down in the administrative machinery of the various Ministries and Departments of Government of India;

(b) whether the Administrative report pending the final report and if so, when; and

(c) when the Administrative Reforms Commission is expected to submit its final report?

The Minister for Home Affairs (Shri Nanda): (a) There is no ready measure, but the steps taken to effect improvements are outlined in the annual report of the Department of Administrative Reforms for 1965-66.

(b) The Commission has not so far come to any conclusion about submitting an interim report.

(c) As at present estimated, by September, 1967.

Purchase of barrels from M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd.

312. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Indian Oil Corporation has been placing orders with M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. for their requirements of barrels:

(b) whether this firm has been removed totally from the register of D.G.S.&D., New Delhi and has been blacklisted by the Ministries of Iron and Steel and Defence; and

(c) if so, the reasons for placing the orders with this firm by the Indian Oil Corporation?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes, until recently.

(b) Yes.

(c) The Indian Oil Corporation came to know of the blacklisting only in April 1966. The Corporation has since decided not to place any orders on the firm.

Supply of Burshane Domestic Gas

313. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Burshane Domestic Gas of Allied Gas Service Private

Limited has been causing great inconvenience and harassment to the consumers in Delhi State from March, 1966 and onwards; and

(b) whether orders for replacement of spent up containers are not attended to for hours and hours?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Government has no information to this effect.

(b) Government understands that during the working hours calls for refills are attended to promptly within 2 hours. Calls received outside the working hours are attended to as soon as possible on the following day.

Bomb explosion in Ambala Cantt.

**314. Shri Gulshan:
Shri D. C. Sharma:
Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the nature of the hand blast bomb which burst in May, 1966 in Ambala Cantt and which country's marking it bore;

(b) the number of casualties as a result thereof; and

(c) the steps taken by Government to check the recurrence of such incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). A fuse No. 233 MKI of the type used by the Indian Army accidentally exploded. There were two casualties. As it was an accidental explosion, the question of taking steps to check recurrence of such incidents does not arise.

Model Act for Universities

**315. Dr. L. M. Singhvi:
Shrimati Renuka Ray:
Shri Yashpal Singh:**

**Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing:
Shri Bibhuti Misra:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether a model act for Universities has been drawn up.

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) the steps taken for its implementation?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The 'Model Act for Universities' Committee which was set up by the Ministry of Education in December, 1961 has in its report suggested general principles that should govern the organizational structure of Universities and has not drawn up any model Act.

(c) The report of the Committee has been sent to the State Governments for suitable action. As 'Education' is a State subject, it is largely for the State Governments to implement the recommendations of the Committee.

Sheikh Abdullah

**316. Dr. L. M. Singhvi:
Shri R. S. Pandey:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri P. C. Borooah:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Surendra Pal Singh:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether there is any change in Sheikh Abdullah's attitude;

(b) whether any proposal to release him was considered recently; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) Government have no evidence of any such change.

(b) There is no proposal to release him.

(c) Does not arise.

Use of D.I.R.

317. Dr. L. M. Singhvi:
Shri Nambiar:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Yashpal Singh:
Shrimati Jayaben Shah:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the use of D.I.R. has been restricted to border areas only; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the considerations in naming the areas?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The nature and extent of restrictions on the use of Defence of India Rules have been set out clearly in Union Home Minister's statement to the Lok Sabha on 18th May 1966. Immediately following this, a new rule 3A was added to the Defence of India Rules requiring the previous approval of the Central Government for exercise by such State Governments, of powers under such rules, as may be specified in a notified order to be issued under the new rule. The notification dated 18th May, 1966 containing rule 3A and orders No. 1529, 1530 and 1531 dated 19th May, 1966 issued thereunder were published in the Gazette of India Extraordinary of the respective dates. The only consideration in allowing use of D.I. Act and Rules to certain border States and areas is that of national security and defence needs.

998 (ai) LS—4.

Rickshaw Pulling

318. Dr. L. M. Singhvi:
Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattinayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have consulted the State Governments for imposing a uniform ban on hand-pulled rickshaws and for rehabilitating those who are likely to be affected;

(b) if so, the response from the State Government in the matter; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c). The question of abolition of rickshaw pulling is primarily for the State Governments to deal with, but the Government of India have addressed the State Governments on this important matter and have made suggestions from time to time.

These are:

- (i) Drawing up a phased programme for the abolition of rickshaw-pulling, and in the meantime—
- (ii) Prescribing suitable regulations governing the conditions of work, medical examination, etc.
- (iii) Preventing exploitation by middlemen by encouraging co-operatives of rickshaw pullers.

The State Governments are taking necessary steps in the light of the conditions obtaining in each State having regard to various factors, e.g. provision of alternative employment to rickshaw pullers and arrangements for alternative conveyance to the poorer sections of community in the urban and semi-urban areas where there is a great demand for cheaper means of communication.

Mizo and Naga Rebels

319. Shri Mohammed Koya:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Mizo and Naga Rebels killed in action upto the 1st July, 1966; and

(b) the total loss incurred by Government due to the Naga and Mizo hostilities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Punjab Boundary Commission

320. Shri Yashpal Singh:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Kolla Venkaiah:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh
Siddhanti:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverfi:
Shri Jashvant Mehta:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri D. D. Mantri:
Shri Kapur Singh:
Shri Buta Singh:
Shri Narasimha Reddy:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Basumatari:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri D. C. Sharma:

Shri Hem Raj:
Shri H. C. Soy:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Punjab Boundary Commission has submitted its report;

(b) if so, when it will be laid on the Table; and

(c) the action initiated to implement it?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The Punjab Boundary Commission submitted its report to the Government on 31st May, 1966. Copies of the report were laid on the Table of the Lok Sabha on 26th July, 1966.

(c) The recommendations of the Commission have been accepted with some modifications. Necessary legislation for the reorganisation of the State of Punjab is being drawn up.

Merger of Goa with Maharashtra

321. Shri Yashpal Singh:
Shri Madhu Limaye:
Shri Bagri:
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Hem Barua:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Nath Pai:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh
Siddhanti:
Shri D. C. Sharma:
Shri C. K. Bhattacharyya:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shrimati Renuka Barkataki:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether any pro-

gress has been made for the merger of Goa with Maharashtra?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): Decisions have still to be taken regarding certain steps in connection with the determination of the future of Goa.

Unlocated Transmitter

323. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1347 on the 2nd March, 1966 and state:

(a) whether the unlocated transmitter has been indulging in frequent broadcasts around the Nagaland area in May and June 1966; and

(b) if so, the steps being taken to locate it?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No such broadcasts have been reported.

(b) Does not arise.

Relations between Legislators and Administrators

324. Shri Vishwa Nath Pandey:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri P. C. Borooah:
Shri Basappa:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri M. Rampure:
Shri R. Barua:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1608 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether Government have finalised the draft code regarding the relations between Legislators and Administrators;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) whether the draft code will be on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Defence and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The draft Code is still under consideration.

U.S.A. Loan for Technical Institutes

325. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2225 on the 16th March, 1966 and state the outcome of the negotiations for a loan from the Government of U.S.A. to meet the requirements of technical Institutes in respect of procurement of equipment manufactured in that country?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): No progress has been made in finalising the agreement.

Girls' Education in Third Plan

326. Shrimati Vimla Devi: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the target fixed for girls' education in the Third Plan and the actual achievement during that period;

(b) the total amount allotted for promotion of the girls' education during the Third Plan and the amount spent out of it; and

(c) the steps Government propose to take to promote the girls' education during the Fourth Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) As against the additional enrolment targets of 85.5 lakhs, 12.8 lakhs and 4.7 lakhs at the primary, middle and secondary

stages, the estimated achievement is expected to be 68.1 lacs, 11.7 lakhs and 5.6 lakhs, respectively.

(b) An amount of Rs. 175 crores was estimated to have been available for the education of girls during the Third Plan. However, it is not possible to indicate the amount spent as separate figures for the purpose are not given in State Annual Plans. In addition, a sum of Rs. 26.10 lakhs was allocated to States and Union Territories for the acceleration of girls' education during 1965-66.

During the Third Plan, a sum of Rs. 6,48,460 was sanctioned to Voluntary Educational Organisations working in the field of Women's Education direct, under a Central scheme. A sum of Rs. 28,122 was also sanctioned to States for holding seminars on girls' education during the Third Plan.

(c) Besides the provisions under various schemes of General Education, from which girls' education will get its due share, a provision of Rs.32.20 crores has been included in the Draft Plan for special schemes to promote girls' education at the school stage. These schemes include the following:—

1. Construction of Quarters for women teachers,
2. Hostel for girls,
3. Sanitary blocks,
4. Appointment of school mothers, and
5. Allowance for women teachers serving in rural areas.

The National Council for Women's Education has been reconstituted to make it a more effective body. The National Council and the State Councils for Women's Education will continue during the Fourth Plan to rouse wide spread interest in girls' education among governmental and non-governmental agencies in the country. For educating public opinion, films on Women's Education are being

prepared, and seminars dealing with various aspects of the problems of girls' education will be organised. The scheme of giving grants to voluntary educational organisations working in the field of Women's Education will also be continued during the Fourth Plan, for which Rs. 40 lakhs have been provided.

अध्यापकों का वेतन-क्रम

327. श्री प्रकाशवीर शारत्री :
 श्री हुकूम चन्द कछवाय :
 श्री रघुनाथ सिंह :
 श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
 श्री ही० ना० मुर्जी :
 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री दी० चं० शर्मा :
 श्री बड़े :
 श्री सुबोध हंसदा :
 श्री स० चं० सामन्त :
 श्री भागवत शा आजाव :
 श्री म० ला० द्विवेदी :
 श्री प्र० चं० बरुआ :
 श्री राजदेव सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार समूचे देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने संबंधी कार्यक्रमों पर भी विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगने की संभावना है ;

(ग) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों अथवा उन की संस्थाओं ने सरकार को कोई स्मरण पत्र प्रस्तुत किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :
(क) शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ सिफारिशों दी हुई हैं। आयोग की अन्य सिफारिशों के साथ साथ इन सिफारिशों की भी मंत्रालय में जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन और कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) स्कूल स्तर पर अध्यापकों के वेतन-मानों का संबंध राज्य सरकारों से है।

प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

328. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अपने स्तर पर इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग इस योजना से कहां तक सहमत है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर, जिसके संबंध में अक्टूबर 1962 में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने तथा उसके बाद में उच्च शिक्षा संबंधी समिति ने 1964 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी, शिक्षा आयोग ने विचार किया था और उसने अपनी राय इस प्रस्ताव के विरुद्ध

दी है। आयोग की रिपोर्ट पर अभी विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय विचार करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Whitley Council Scheme

329. Shri Madhu Limaye:

Shri Bagri:

Dr. Ram Manohar Lohia:

Shri Kishen Pattnayak:

Shri P. R. Chakraverti:

Shri Linga Reddy:

Shri A. N. Vidyalkar:

Shri A. K. Gopalan:

Shri Kolla Venkatah:

Shri Dasaratha Deb:

Shri A. P. Sharma:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Whitley Council Scheme has been implemented in any of the Central Government departments; and

(b) if not, when the scheme is expected to start functioning?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathl): (a) No.

(b) The Joint Councils under the Scheme are expected to start functioning very shortly.

Primary Education in States

330. Shri Madhu Limaye:

Shri Bagri:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5137 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether Government have drawn the attention of the States, where primary education is not free, to the relevant Directive Principles of State Policy.

(b) if so, their response to the Centre's advice; and

(c) the assistance they propose to give?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) In so far as the primary stage of education (age-group 6—11) is concerned, barring special schools and some schools of Urban areas of West Bengal, education is imparted free of charge throughout the country.

Attention of the Government of West Bengal has been drawn to the need to make primary education free in the Urban areas also.

(b) The Government of West Bengal in cooperation with the Corporation authorities, are working out a scheme to make primary education free in Urban areas too.

(c) No special Central assistance is proposed for this purpose.

Voluntary Migrants

**331. Shri Madhu Limaye:
Shri Bagri:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1622 on 11th May, 1966 and state:

(a) whether Government have made any study of the impact of the new D.I.R. policy in regard to the return of the 12411 persons who "voluntarily migrated" to Pakistan during the September conflict last year;

(b) whether these persons include many *sarpanches* and members of the *gram panchayats*;

(c) whether these persons will be allowed to return to India; and

(d) the legal position in respect of their citizenship rights?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan

Shukla): (a) The impact of the amendment of the provisions of D.I.R. vis-a-vis voluntary migrants is under constant review.

(b) Yes, a few.

(c) The return of these persons is governed by the notification No. G.S.R. 1893 of 25th December, 1965 published in the Gazette Extraordinary dated 27-12-1965.

(d) Their citizenship rights have not been affected by the amendment referred to above.

Labour Laws

**332. Shri Madhu Limaye:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattayak:
Shri Dinen Bhattacharya:**

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether he made a statement that certain labour laws passed during his previous tenure of office and some other beneficial labour laws are not being implemented;

(b) if so, the reasons for this non-implementation;

(c) whether Government intend re-considering their decision about issuing notification under the law relating to the recognition of the Trade Unions which is still on the statute book but remains unimplemented; and

(d) the steps Government propose to take to secure proper implementation of the Labour Laws?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) No. The Hon'ble Member is presumably referring to the observations made by the Minister of Labour and Employment in the course of his reply to the Debate in the Lok

Sabha on the Ministry's Demand for Grants for 1966-67. What the Minister stated was that the state of implementation had not progressed much. He also referred to the need for retouching the Acts here and there in the light of the economic and technological progress and he also referred to the need for a social consciousness to see that whatever was provided for labour was honestly and effectively implemented.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Improving the effectiveness of implementation is a continuing process. Government will continue to take such steps as are appropriate having regard to the circumstances of each case including, where necessary, the amendment of the Acts, strengthening of the enforcement machinery and building up the requisite social consciousness. It may also be pointed out that the State Governments are responsible for the implementation of a number of labour laws.

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये रोजगार

333. श्री नवल प्रभाकर : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों के रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों की सूची बहुत लम्बी है;

(ख) वे लोग किन श्रेणियों के व्यवसायों में रोजगार चाहते हैं; और

(ग) वे लोग कब से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) :-

प्रमुख व्यावसायिक वर्ग	30 जून, 1966 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में दर्ज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार
पेशेवर, तकनीकी और इनसे सम्बन्धित कामगर	692
प्रशासनिक, कार्यकारी, और इनसे सम्बन्धित कामगर	4
क्लर्की करने वाले	182
कृषि कामगर	60
यातायात और संचार व्यवसायों के कामगर	37
दस्तकार और उत्पादन कार्य में लगे कामगर	204
निजी सेवा, खेल और आमोद-प्रमोद के कार्यों में कामगर	54
अकुशल कामगर	4,380
ऐसे कामगर जिन्हें कार्य का पूर्व अनुभव नहीं है :-	
(क) ग्रेजुएट	110
(ख) मैट्रिकुलेट्स	1,723
(ग) मिडिल स्तर तक पढ़े-लिखे	758
(घ) मिडिल स्तर से कम पढ़े-लिखे	640
कुल	8,844

(ग) —

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में नाम दर्ज रहने की अवधि	उम्मीदवारों की संख्या
6 मास से कम	4,655
6 मास से अधिक पर एक साल से कम	2,009
एक साल से अधिक पर दो साल से कम	1,103
दो साल से अधिक पर तीन साल से कम	748
तीन साल से अधिक	329
कुल	8,844

दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन सेट

334. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सरकारी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में टेलीविजन सेटों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) शेष स्कूलों में उनकी कब तक व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) 132।

(ख) 39 और स्कूलों में इस वर्ष मैन टेलीविजन सेटों की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है। मैन-सेट उपलब्ध होने पर शेष स्कूलों में भी इनकी सुविधा प्रदान कर दी जायेगी

Port and Dock Workers

335. **Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the demands of the Port and Dock workers for immediate payment of bonus and an interim relief of 25 per cent of the gross wages by the Central Board for Port and Dock workers have been considered by Government; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b). The position is as follows:

Bonus

The demand of port workers for payment of bonus is under consideration. As regards dock workers, bonus schemes are in force in the ports of Bombay, Calcutta, Cochin and Madras.

Interim Relief

The Wage Board for Port and Dock Workers made recommendations for grant of interim relief and these were accepted by Government in April, 1965. It is understood that the All India Port and Dock Workers' Federation has since raised the question of second interim relief before the Wage Board.

Creation of Selection Grade Posts

336. **Shri Ram Harkh Yadav:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his Ministry have received representations from the Employees' Union to create posts of Selection Grade Assistants and Lower Division Clerks in the Central Secretariat Clerical Service; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been considered more than once but it has not been possible to agree to the creation of selection grades for Assistants and Lower Division Clerks.

Commission of Enquiry Act

339. Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5176 on the 11th May, 1966 regarding the stampede at a meeting addressed by the Prime Minister and state:

(a) whether the Commission of Inquiry has since been set up under the Commission of Enquiry Act; and

(b) if so, whether the Commission has made any report to Government and, if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Government of Assam have not yet set up the Commission of Enquiry.

(b) Does not arise.

Gandhi Murder Case

340. Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Sonavane:
Shri Raghunath Singh:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given

to Unstarred Question No. 5181 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether Government have since taken a decision to appoint a new Commission to inquire into the circumstances of Mahatma Gandhi's Murder;

(b) if so, the names of the Members of the Commission; and

(c) when, it will start its work?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The matter is still under consideration.

Charges against a Kanpur Businessman

341. Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5235 on the 11th May, 1966 regarding the charges against the Kanpur businessman and state:

(a) whether the legal scrutiny into the charges of supplying corrugated sheets to Pakistan by the said businessman has since been completed; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). After completing the investigation legal opinion has been obtained. During the course of investigation, no evidence could be had to suggest that any of the corrugated sheets booked from Kanpur to Naroda (Ahmedabad) had been smuggled to Pakistan. It has been decided to file a charge-sheet against, 8 accused persons under Section 120(B) I.P.C. read with Section 7 of the Essential Commodities Act

and Clause 4 of the Iron and Steel (Control) Order.

Health Services in Universities

342. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Bagri:
Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1611 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether the Education Commission has submitted its report regarding the health services in the Universities; and

(b) if so, the recommendations of the Commission and Government's reaction thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-6506/66.*]

Misuse of Residential Telephones of P. and T. Officers

343. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the telephone bills in respect of the residential telephones of the officers and staff of the P. and T. Department are dealt with merely by book adjustment;

(b) whether any machinery has been devised to check that these telephones are not used by the P. and T. Department officers for trunk dialing where S.T.D. facilities are available; and

(c) whether it is proposed to provide any meters for such telephone

connections to prevent such misuse of telephones for private purpose under the cover of service calls?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) In regard to local calls emanating from residential service-telephone connections of P. and T. officers, no bill is prepared. In regard to trunk calls, the relevant trunk call bills are certified by the officers if the calls were on administrative work, if not, they have to pay for the calls.

(b) No.

(c) Does not arise.

CARE and USAID (Aid for the ravaged Areas in Andhra Pradesh)

344. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the C.A.R.E. and U.S.A.I.D. have rushed aid for the relief of fire ravaged areas in Eastern districts of Andhra Pradesh;

(b) if so, the quantum and nature thereof;

(c) whether Government have at any stage conducted any inquiry through the C.I.B. to investigate the causes of such large-scale fires in Vijayawada; and

(d) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) Only C.A.R.E. have given some aid.

(b) Milk Powder	10,135 lbs.
Wheat	3,515 lbs.
Oil	705 lbs.

(c) and (d). No investigations have been conducted through the C.I.B. The State Government have, however, appointed a Commission of Enquiry under a District and Sessions Judge to enquire into the cause of fires and to suggest the measures for the prevention of recurrence of such fires. The report of the Commission is awaited.

Telephones to P. and T. Officers

345. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the Officers in the P. and T. Department who are entitled to be provided with telephone connections at their residences during their temporary stay in the capital while on duty-cum-leave;

(b) whether such facilities are also provided to the touring officers of other Ministries/Departments of the Central Government when they come to Delhi on similar assignment;

(c) if not, the reasons for allowing these facilities to the officers of the P. and T. Department only; and

(d) the details of such telephone connections provided to such officers during the period from 1st July, 1965 to 30th April, 1966 and total expenditure incurred in that connection?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) Officers not below the rank of Divisional Engineers are provided with telephone connections at the place of their stay while on tour in the Capital.

(b) Casual telephone connection are provided to other touring officers when asked for under the usual rental terms of the Department.

(c) Does not arise.

(d) List of service connections provided to P&T Officers during the period 1st July, 1965 to 30th April, 1966 is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6507/66]. The connections were provided in the normal course without incurring any appreciable expenditure.

राज्यों तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार

346. श्री ए० ला० द्विवेदी :
 श्री सुबोध हंसदा :
 श्री स० चं० सामन्त :
 श्री भागवत झा अजाद :
 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
 श्री रिशांग किशिंग :
 श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर कि हिन्दी-भाषी राज्यों की सरकारों को परिपत्र द्वारा सूचित किया जायेगा कि वे केन्द्र को भेजे जाने वाले पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा करें क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने हिन्दी भाषी राज्यों से आने वाले पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने की व्यवस्था कर ली है, ताकि उन पर कार्यवाही करने में देरी न होने पाये; और

(ग) हिन्दी-भाषी राज्यों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्री द्वारा हिन्दी-भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गये पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या LT—6508/66]

(ख) विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी-भाषी राज्यों से प्राप्त हिन्दी पत्रव्यवहार के अंग्रेजी

अनुवाद की व्यवस्था है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस व्यवस्था को और मजबूत किया जायेगा।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी हिन्दी में आने वाले पत्रव्यवहार के उत्तर में देर हुई।

New Antibiotics for controlling Plant Diseases

347. Shri C K. Bhattacharyya:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Sham Lal Saraf:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether new antibiotics have been discovered at H.A.L. Factory, Pimpri which can control plant diseases; and

(b) whether their effect has been tested?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b). As a result of research done in the Research Laboratory Pimpri, two new antibiotics which would be used for plant protection have been found. These are:

1. Aureofungin.—This is a new anti-fungal antibiotic found to be highly active against plant pathogenic fungi. Its action is said to be both fungicidal and fungistatic depending upon the concentration used. In its activity against paddy blast diseases Aureofungin has been found to be better than Blastomycin discovered in Japan. Aureofungin could also be used against fruit crop diseases as well, and it is expected that it might replace copper based and organic fungicides presently used in the country and which are produced mainly from imported materials like copper.

2. Streptocycline.—The Department of Agriculture (Ministry of F. A. C. D. & C) have launched a wide scale programme for cultivation of Taichung

Native-1 variety of paddy. Streptocycline has been found to be very effective in the treatment of seeds and control of bacterial blight of paddy.

It is proposed to meet the requirement of the Ministry of F.A.C.D. & C. (Department of Agriculture) in respect of Aureofungin and Streptocycline. Interest has also been shown by some foreign firms in USA.

History of Freedom Movement

348. Shri A. N. Vidyalkar: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) The progress so far made in the project of writing the history of freedom movement and 'who's who' of the freedom fighters;

(b) the reasons for the slow progress of the project;

(c) the expenditure incurred so far by the Centre and States separately; and

(d) the names of the volumes published so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Volume I of the History of the Freedom Movement in India was published in 1961; Volume II is in the press; and Volume III is under preparation. A statement showing the progress of work in each State, regarding the compilation of the Freedom Fighters' 'Who's Who' is placed on the Table of the House

(b) In view of the wide range of source materials—Government records, private papers, memoirs, contemporary newspapers, etc.—available on the subject and the need to give an objective account of the Freedom Struggle, the progress of work is not considered slow. The need is, however, felt for expediting it.

(c) A sum of Rs. 810,050 was spent by the Centre on the compilation of the History of the Freedom Movement till March, 1966. A statement

showing the expenditure incurred by the State Governments on the compilation of the Freedom Fighters' 'Who's Who' and the Cental subsidy given to them for this purpose is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6509/66].

(d) History of the Freedom Movement in India, Volume I, has been published.

Standard History Text-books

349. Shri A. N. Vidyalkar:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the progress made in the scheme of writing standard History Text-Books so far;

(b) the names of the Text-Books so far prepared and published and the standards for which the same are meant;

(c) the administrative machinery set up for this task and the names of the scholars associated; and

(d) the time likely to be taken to complete the whole scheme?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). A text-book of Indian History for middle schools has been prepared and is in press. Another text-book for middle schools is expected to be ready this year. A text-book for secondary schools is also under preparation.

(c) The project is being carried out under the direction of an Editorial Board, consisting of Dr. S. Gopal as Chief Editor and Prof. S. Nurul Hasan, Prof. Satish Chandra and Dr. Romila Thapar as Editors.

(d) The whole project is expected to be completed in the next three years.

Goonda Menace in Delhi

350. Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:

Shri Kishen Pattanayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether complaints have been received and also reports have appeared in the press about the deteriorating law and order situation in the Capital; and

(b) if so, the steps taken to meet the goonda menace in the Capital?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Complaints and press reports regarding law and order situation in the Capital appear to be exaggerated as the total number of crimes reported in the Capital during the last six months has come down as compared to the corresponding period of the last year.

(b) Steps taken to meet the goonda menace in the Capital are mentioned in the statement below:

Statement

- (i) Activities of goondas and other anti-social elements are kept under check by stringent surveillance.
- (ii) Beat patrolling has been strengthened. It is also proposed to increase the number of beats in the existing police Stations so that beat constables can cover their areas effectively.
- (iii) Surprise checks by senior officers, including the I.G.P. and D.I.G. have been done with a view to keep the Police Station Staff on the alert.
- (iv) A short course of training in modern methods of investigation has been recently organized in the Crime Branch of the Delhi Police. Upper Subordinates who have to deal with investigation work are put through this course.

- (v) A second post of D.I.G. Police has been created to ensure closer supervision and direction from the higher level.
- (vi) In order to increase the mobility of the Delhi Police, more vehicles have been allotted to them.
- (vii) Certain provisions of Bombay Police Act have been extended to the Union Territory of Delhi thus enabling the district Magistrate and District Superintendent of Police to extenuate goondas and gangs of criminals from specified jurisdiction.

Relief to Political Sufferers in Delhi

351. Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bagri:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5144 on the 11th May, 1966, regarding the relief to Political Sufferers and state:

(a) whether the Delhi Development Authority has since considered the scheme for the allotment of residential plots to the political sufferers of Low-Income group; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Delhi Development Authority has put into effect a scheme of allotment of residential plots of below 200 square yards size by draw of lots at fixed rates to individuals in the low-income group (i.e., those whose income is less than Rs. 6,000 per annum) and who do not own any other residential plot or house in Delhi and have been residing in Delhi continuously for the last five years. In this scheme some plots are reserved for political sufferers who satisfy the prescribed conditions. The number of plots reserved

for the political sufferers is fixed on the total number of applications received from the political sufferers as against the total number of applications received.

Any person who has suffered in the freedom movement is deemed a political sufferer. So far only one plot has been allotted to a political sufferer.

Workers' Education Programme

352. Shri Warrior: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the progress of workers' education programme;

(b) if so, the result thereof;

(c) Governments' proposals for further improving the Workers' Education Programme; and

(d) the total amount so far spent by the Centre on this programme?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Government have not yet carried out any review of the Workers' Education Programme which is being implemented and administered through the Central Board for Workers' Education—an autonomous body registered as a Society under the Societies Registration Act, 1881. Close watch has, however, been kept on the progress made.

(b) Does not arise.

(c) The question of reviewing the functioning of the scheme as a whole is under examination of Government. On completion of the review, the question of further improving the Workers' Education Programme will be considered.

(d) A sum of Rs. 1,69,52,940 was spent by Government on the programme upto the end of March, 1966.

Employees' State Insurance Scheme

353. **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Yashraj Singh:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the tripartite Committee to review the working of the Employees State Insurance Scheme has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations of the Committee; and

(c) the decision taken by Government thereon?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir.

(b) A summary of conclusions and recommendations is contained in the Report of the Committee, which has been published.

(c) No decision has yet been taken by Government. Comments called for from the Corporation, State Governments etc. are still awaited.

Inter-State Living by Students of Nagaland, Manipur etc.

354. **Shri Raghunath Singh:**
Shri D. D. Puri:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether 89 students of Nagaland, Manipur, NEFA, Assam and Tripura have spent some days in Bombay to get experience of Inter-State living; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Bombay under the "Students Experi-

ence in Inter-State Living programme, arranged the visit of 78 students from Nagaland, Manipur, NEFA, and Assam for one month's stay in Bombay with Indian families. As a result of the tour, personal contact and affinity between guests and host families was created.

दिल्ली की बस्तियों में मकानों की बिक्री

355. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 में दिल्ली में राजेन्द्र नगर, पटेल नगर तथा अन्य बस्तियों में इस शर्त पर मकान बेचे गये थे कि उन मकानों में रहने वाले व्यक्तियों के डिफेंस कालोनी में मकान बन कर तैयार हो जाने पर मकान खरीदने वालों को मकानों का खाली कब्जा दे दिया जायेगा ;

(ख) क्या इन मकानों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में मकान बनवा लिये जाने पर भी मकान खाली नहीं किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन मकानों को खरीदने वाले व्यक्तियों को मकानों का खाली कब्जा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चहलान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नागा विद्रोहियों द्वारा व्यक्तियों का अपहरण

356. **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1966 में नागा विद्रोही जिन 10 व्यक्तियों को उठा

ले गये थे बाद में उन्हें 3,200 रुपये की फिरोती पर रिहा कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौनसी घटनाओं की ओर संकेत है। अस्तु अप्रैल, की उन दो घटनाओं का व्यौरा नीचे दिया जा रहा है जो हमारे ध्यान में आई।

15 अप्रैल, 1966 को 25 नागा विद्रोहियों के एक दल द्वारा मनीपुर के उखल सब-डिवीजन, में दो ग्रामीणों का अपहरण किया गया। उन्हें 3,000 रुपये की फिरोती प्राप्त होने पर छोड़ दिया गया।

20 अप्रैल, 1966 को 25 नागा विद्रोहियों के एक दल ने मनापुर के सदर सब-डिवीजन में 11 ग्रामीणों का अपहरण किया। उन में से प्रत्येक को 100 रुपये की फिरोती लेकर छोड़ा गया।

(ख) पुलिस द्वारा मामले दर्ज कर लिए गये हैं और उनकी जांच हो रही है।

विदेशी शराब का पकड़ा जाना

357. श्री रामेश्वरानन्द :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि अष्टाचार निरोधक विभाग ने 27 अप्रैल, 1966 को लगभग छः हजार रुपये की लागत की विदेशी शराब पकड़ी थी जैसा कि दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) 30 अप्रैल, 1966 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार का सम्बन्ध एक ऐसे मामले से है जिसका मुख्यतः महाराष्ट्र सरकार से सम्बन्ध है, और भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली में हौज काजी के डाकघर में जालसाजी

358. श्री रामेश्वरानन्द :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या संचार मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हौज काजी डाकघर से 9,600 रुपये की गायब राशि के मामले में चल रही जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) तथा (ख) विभागीय पूछताछ का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। विभागीय पूछताछ के दौरान अपराधी का कोई सुरास नहीं मिल सका है।

(ग) जिस क्लर्क के संरक्षण से नकदी गुम हुई थी, अनुशासनिक कार्रवाई होने तक उसकी सेवायें निलम्बित कर दी गई हैं।

कास्टिक सोडे का दाम

359. श्री रामेश्वरानन्द :

श्री हुकूम चन्द कछवाय :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धलेश्वर मीना :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कास्टिक सोडे और साबुन के दाम दुगने हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अल्लनेसन) : (क) जी नहीं । उत्पादन-मूल्यों के बढ़ने के कारण दिसम्बर, 1963 से कास्टिक सोडा के दामों में लगभग 25 प्रतिशत और साबुनों के दामों में 22 से 45 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(ख) मूल्यों पर अवरोध करने के प्रश्न पर उत्पादन करने वालों से बातचीत हुई है । कास्टिक सोडा की तैयार करने वालों ने विश्वास दिलाया है कि बिना सरकार के परामर्श से और वृद्धि नहीं की जायेगी और साबुन निर्माताओं ने भी मूल्यों पर नियंत्रण रखने में सहयोग देने के लिए विश्वास दिलाया है ।

मंदसौर में प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का पाया जाना

360. श्री रामेश्वरानन्द :

श्री हुकूम चन्द कछवाय :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंदसौर जिले में 35 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष पाये गये हैं ;

996 A; LS-5

(ख) यदि हां, तो इन अवशेषों पर किन भाषाओं में लिखा हुआ है ; और

(ग) क्या इन अवशेषों का संबंध भारत के साथ है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार को ऐसी किसी खोज का पता नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग कालेज

361. श्री रघुनाथ सिंह :

श्री हुकूम चन्द कछवाय :

श्री रामेश्वरानन्द :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1965 में लगभग 500 इंजीनियरों ने दिल्ली से अपनी परीक्षा पास की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन इंजीनियरों में से 50 प्रतिशत इंजीनियर 100 रुपये प्रति मास पर काम कर रहे हैं और शेष लोग बेरोजगार हैं ;

(ग) यदि हां, तो देश में और इंजीनियरिंग कालेज खोलने के क्या कारण हैं ; और

(घ) 1965 में कितने इंजीनियरों ने परीक्षा पास की तथा उन में से कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). दिल्ली में, इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली और दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज, नामक दो कालेज हैं ।

इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालोजी से 1965 में किसी विद्यार्थी ने स्नातक की उपाधि नहीं ली। केवल 20 विद्यार्थियों ने दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज से 1965 में हुई बी० ई० परीक्षा पास की। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में 12 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय डिप्लोमा परीक्षा पास की। सभी 32 व्यक्ति 300 रु० प्रतिमास से अधिक वेतन पर रोजगार में हैं।

(ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान कोई नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई इरादा नहीं है। केवल वही इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किए जा रहे हैं जिन्हें तीसरी पंच वर्षीय आयोजना के दौरान अनुमोदित किया गया है।

(घ) 1965 में भारत के कालेजों से परीक्षा पास करने वाले इंजीनियरी विद्यार्थियों की कुल संख्या 10,282 है। इनमें से रोजगार प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है।

सोने के डाक पासलों में पत्थर

362. श्री रघुनाथ सिंह :

श्री नृकम चन्व कश्यप :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर से जबलपुर को डाक द्वारा भेजे गये सोने के आभूषणों के एक पासल में से 22 मई, 1966 को सोने के कजन के बराबर पत्थर के टुकड़े निकले ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्ति को चेवरों के लिए प्रतिकर दिया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :
(क) जयपुर से भेजा गया एक बीमाघृत पासल जबलपुर में 22 मई, 1966 को नहीं बल्कि 16 मई, 1966 को वितरित किया गया। इस पासल के वितरण करने पर यह पता चला कि इसमें दो पत्थर, एक शीशे का टुकड़ा, एक जवाहरात की पेंटी और दो सोने के कंगन थे जबकि पासल भेजने वाले व्यक्ति के अनुसार उसमें एक मोतियों का नेकलेस, मोतियों के टास की एक जोड़ी, एक सोने की झगड़ी तथा सोने के कंगनों की एक जोड़ी होनी चाहिए थी।

(ख) विभाग तथा पुलिस द्वारा पूछ-ताछ की जा रही है।

(ग) पूछताछ का काम पूरा होने पर बाबे पर विचार किया जाएगा।

Hill Areas Development Institute

363. Shri Gokulananda Mohanty: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have decided to establish a Hill Areas Development Institute in Khasi and Jaintia Hill Districts, as recommended by the Pataskar Commission; and

(b) the special features of the Institute?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) The Pataskar Commission in its report on the Hill Areas of Assam has not recommended the establishment of Hill Areas Development Institute in Khasi and Jaintia Hills District.

(b) Does not arise.

D.I.R. in Border States

- 364. Shri P. C. Borooah:**
Shri E. S. Pandey:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Bibhuti Mishra:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri A. K. Gopalan:
Shri Imbichibava:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the border States have been asked to repromulgate, under normal laws, all orders issued under the Defence of India Rules, to arm themselves with powers enough to deal with any abnormal exigencies;

(b) if so, the State Governments response thereto; and

(c) whether other State Governments have also been asked to promulgate orders for continuation of any restrictive action, they might have taken under D.I.R., even after the abrogation of D.I.R., and if so, their response to it?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). Although the Governments of Assam, Nagaland, Jammu and Kashmir, Manipur and Tripura are as per present policy exempted from restriction on the use of Defence of India Act and Rules, a suggestion has nevertheless been made to these Governments to change over to the normal laws, with such amendments as may be required, to the maximum extent possible relying on the Defence of India Act and Rules only for those purposes connected with Defence, security, etc., for which the existing normal laws even with amendments may not be adequate. The other State Governments have also been advised that in view of the restriction on the use of Defence of India Act and Rules to certain States and for certain purposes connected with defence, they should devise suitable arrangements whereby for the vari-

ous purposes for which the Defence of India Act and Rules are at present being used, action can be taken under normal laws with any amendments that may be necessary. There is broad agreement with these suggestions.

Goa Fertilizer Project in collaboration with U.S.A.

365. Shri Kolla Venkaiah: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether any agreement was reached between the Birla Gwalior (Private) Limited and Armour & Co. (U.S.) regarding Goa Fertilizer Project;

(b) if so, the terms of collaboration;

(c) the aid sought for the project from the International Finance Corporation; and

(d) the foreign exchange required and the production programme for the project?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) The main features of the collaboration agreement are as follows:—

(1) The foreign collaborators shall subscribe \$3.38 million of the equity capital of the Indian Company—\$2.91 million in cash and \$.97 million for know-how.

(2) The foreign collaborators shall make available to the Indian Company the following:—

- (i) the engineering, manufacturing and marketing data,
- (ii) skills needed to design, construct and operate the plant as to market products,
- (iii) their secret formula when necessary to produce compound fertilizers,
- (iv) the secret process and technology which they now use in the United States,

(v) technical personnel to supervise the operation of the plant, if required by the Indian Company.

(3) The foreign collaborators will obtain with the assistance of Indian party the rupee and foreign exchange loans required for the project.

(4) The foreign collaborator will provide facilities for training Indian personnel.

(c) A long-term loan \$13.5 million (pre-devaluation figures) is proposed to be sought from the International Finance Corporation.

(d) The foreign exchange required for the project is estimated at Rs. 11.03 crores (\$23.17 million) (pre-devaluation figures) and the project is expected to produce 340,000 tonnes of urea per year.

Death of Shri Nand Lal, a Punjabi Poet

366. Shri Daljit Singh:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a famous Punjabi poet, Shri Nand Lal Noorpuri, whose poems are well known in the country is reported to have committed suicide at Jullundur following the long spell of poverty, illness and neglect; and

(b) if so, the assistance if any, given to him and to his family after his death?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) The Government of India learnt of his death through newspapers.

(b) He had been receiving a pension of Rs. 75 p.m. under the Government of India's scheme of financial assistance to writers, artists etc. in indigent circumstances since September, 1957. Application for monthly pen-

sion from his family has not yet been received.

Refinery in Northern India

367. Shri Daljit Singh:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great demand for the setting up of a refinery plant in Northern India; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No, not for the present, but possibly after a few years.

(b) Studies are being carried out to help determine the need in due course.

Wastage at Elementary Stage

368. Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the steps proposed by Government to stop the wastage and stagnation at the elementary stage of education;

(b) whether this wastage and stagnation is very high among the backward classes; and

(c) if so, the measures taken to do away the stagnation and wastage problem among the children of these backward classes?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). Although no nation-wide study has been conducted so far to assess the incidence of wastage and stagnation among pupils at the elementary stage of education, it is generally known that the degree of wastage and stagnation especially from classes I to III is high.

Among the remedial measures which have been adopted to deal with this problem which include children of backward classes also, are the following:—

- (i) Starting of Pre-primary Schools.
- (ii) Provision of Mid-day Meals.
- (iii) Supply of free or subsidised text-books.
- (iv) Improvement of the professional competence of teachers.
- (v) Improvement in the teacher-pupil ratio.
- (vi) Construction of adequate and attractive school buildings and equipping them with necessary teaching aids.
- (vii) Granting of stipends.
- (viii) Putting up of more and more schools so as to be within walking distance of children.
- (ix) Giving special assistance after school hours to slow learners.

Hindustan Organic Chemical Project

**369. Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Asad:
Shri M. L. Dwivedi:**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Organic Chemicals Project has made any progress in procuring Plant and Machinery;

(b) if so, with whom the order has been placed; and

(c) when it is likely to be obtained?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Scrutiny of tenders received for the supply of all chemical plants included in the Hindustan Organic Chemicals project has been completed and negotiations are at present being held by the Company with the selected parties before final choice is made in respect of each plant. Orders are expected to be placed in the next few months.

(b) No order has been placed with any party so far.

(c) Plants are expected to be delivered approximately ten to fourteen months from the date of entering into supply agreements with the parties concerned.

Rehabilitation of Squatters

370. Dr. Ranen Sen: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a few displaced persons are squatting on lands belonging to Government and some private individuals on the northern side of the Calcutta Lake area; and

(b) if so, Government's plan to rehabilitate them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) Yes, Sir, there are 317 families of displaced persons from East Pakistan who are still squatting on certain plots of lands which were acquired or taken on lease by the Ministry of Health in 1947 for starting a Medical College and Hospital.

(b) Out of 317 families, only 29 families are protected by the judgement of Competent Authority under West Bengal Act, XVI of 1951 and entitled to alternative accommodation before eviction. The Government of West Bengal are giving rehabilitation assistance to these 29 families under the additional financial powers delegated to them in 1966, which includes the grant of rehabilitation loans to protected squatters. The remaining families are not eligible for any rehabilitation assistance.

Books of Poet Nazrul Islam

371. Shrimati Renu Chakravarty: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether any steps are proposed to be taken to procure the copyright of the books of Poet Nazrul Islam and to publish them; and

(b) whether Government propose to introduce new legislation to facilitate such measures being taken by the West Bengal Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) No special legislation is necessary in this regard, since, under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), State Government or individuals are at liberty to acquire Copyrights in specific books.

आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों की रिहाई

372. श्री भागवत झा आजाद :

श्री हुसैन चन्द कछवाय :

श्री सोनावने :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 अप्रैल, 1966 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 4551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कैदियों की रिहाई के बारे में अब जानकारी एकत्र कर ली गई है जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस का व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब एकत्रित कर ली जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्युत्तरण शुक्ल) : (क) से (ग). अभी 4 राज्य सरकारों से सूचना आने की प्रतीक्षा है और एकत्रित होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Re-Imbursement of Medical Expenses

373. Shri Achal Singh: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that false claims are being made annually for

reimbursement of medical expenses by employees of Posts and Telegraphs, especially at Agra which have increased expenditure of the Department;

(b) whether Government have received any report in this matter; and

(c) if so, the action taken to stop this rising trend and wastage of lakhs of rupees every year in the reimbursement of medical expenses?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). Expenditure on medical reimbursement in Agra has registered an abnormal increase. It is suspected that some bogus or false claims might have been preferred; some cases have been reported to the Special Police Estt. for check on this but no false claim has so far been established.

(c) Both as a preventive measure against such abuse and to make the medical help easily available it has been decided to open a departmental dispensary for P&T employees at Agra and this is being implemented.

Conference of Book Experts in Tokyo

**374. Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Braj Bihari Mehrotra:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether a Conference of Book Experts was held in Tokyo in the last week of May, 1966;

(b) if so, the countries which participated in the Conference; and the main features of its deliberations; and

(c) India's stand in the Conference?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. A conference of Experts on Book Production and Distribution in Asia was

organized by UNESCO in Tokyo from the 25th to the 31st May, 1966.

(b) Experts from the following 20 countries participated in the Conference:—

1. Afghanistan,
2. Burma,
3. Cambodia,
4. Ceylon,
5. Taiwan (Formosa),
6. Hong Kong,
7. India,
8. Indonesia,
9. Iran,
10. Israel,
11. Japan,
12. South Korea,
13. Laos,
14. Malaysia,
15. Nepal,
16. Pakistan,
17. Philippines,
18. Singapore,
19. Thailand, and
20. South Viet-Nam.

The conference reviewed the Problems of Book Development in Asia and recommended the adoption of a programme to develop publishing and the promotion of books in Asian countries. It was recommended that each country may draw up a book development plan, set up national textbooks institutes and establish graphic arts organizations. Long-term low-interest loans by the World Bank were recommended in order to expand publishing in Asia. UNESCO was urged to press for lower postal rates on books, reduction of tariffs on publications and the grant of copyrights at nominal fees in order to promote the wider distribution of books.

(c) The experts to the conference from different countries including India had been invited in their

personal capacity. As such, the question of India's stand in the conference does not arise.

Dacoities by Pakistanis

- 375. Shri Ram Harkh Yadav:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Braj Bihari Mehrotra:
Shri Hukam Chand
Kachhavalaya:
Shri. Bhagwat Jha Azad:
Shri Sonavane:
Shri Raghunath Singh:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether, within the last two weeks of May, 1966, half a dozen dacoities were committed by Pakistani criminals in West Bengal border villages;

(b) whether several groups of Pakistani nationals armed with guns and other deadly weapons made a series of raids during the same period in Goalpara and Garo Hills districts of Assam on the Assam East Pak border;

(c) if so, the details of the outrageous acts of violence by Pakistanis; and

(d) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Seven dacoities were committed by Pak criminals in West Bengal border villages.

(b) Three dacoities were committed.

(c) Details are given in the statement below:

STATEMENT

I. West Bengal Border:

- (i) 15 Pak nationals raided the Indian Village Biwwaguri on 17th May 1966 and de-

camped with cash and ornaments after assaulting the inmates and firing four rounds. Three empty cases with Pak markings were found at the place of occurrence.

- (ii) Indian patrol encountered about 15 armed Pak criminals on 21st May, '66 in Thakurpara area and drove them away.
- (iii) Indian patrol party encountered 6 cattle lifters on 23rd May 1966 in KHAYERBARI and drove them away.
- (iv) About 30 Pak nationals raided a house in Village Nehmanpara in the early hours of 25-5-66, fired three rounds and decamped with cash and ornaments. Two pistols with Pak markings were recovered from the place of occurrence.
- (v) A dacoity was committed in Village Bolta on 25th May, 1966.
- (vi) About 25 Pak nationals committed dacoity in a house in Village Jamrail in the early hours of 26th May, 1966.
- (vii) 9 Pak criminals committed dacoity in the early hours of 27th May 1966 in Village Netlapur.

II. Assam Border:

- (i) 20 armed Pak nationals trespassed into Indian territory and committed dacoity in the early hours of 23rd May, 1966 in Village Namdaspara.
- (ii) Pak nationals committed a dacoity in the early hours of 23rd May, 1966 in Village Moslabari.
- (iii) Pak nationals committed dacoity in the early hours of

23rd May 1966 in Village Ghokaoahra.

(d) Patrolling and Vigilance have been stepped up.

Telephone Connections in Bombay

376. Shri Indrajit Gupta: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a large number of complaints by telephone subscribers in Bombay City regarding the discrimination in the matter of giving new connections;

(b) whether it is a fact that better-off people in the Gamdevi Exchange area have been getting connections applied for in 1963, while less influential applicants are kept waiting since 1956; and

(c) if so, whether any enquiry has been ordered into such complaints?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) There have been some complaints.

(b) In general, requests for OYT connections received upto the beginning of 1963, have been met with. Connections are normally offered in order of the dates of registration in the waiting list. Cases here and there do, however, get delayed, due to cable and other difficulties in particular areas and locations. While special efforts are made in these cases to provide the connections as early as possible, it is not always feasible to give connections in such cases in their turn. Some connections have also been provided on out-of-turn basis under the recommendations of the Telephone Advisory Committee or at the discretion of the Government.

(c) No. A Committee has, however, been set up for studying the procedure adoption in regard to

allotment of telephone connections at Bombay, Ahmedabad and Kanpur.

फँजाबाद डाकघर से धन का गायब हो जाना

377. श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री तुला राम :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जून, 1966 को फँजाबाद (उत्तर प्रदेश) के मुख्य डाकघर से एक थैला, जिसमें 2,500 रुपये थे, गायब पाया गया ;

(ख) यह थैला किन परिस्थितियों में गायब हुआ ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) फँजाबाद के प्रधान डाकघर के खजान्ची तथा उपलेखा क्लर्क द्वारा 1 जून, 1966 को विभिन्न डाकघरों के लिए 19 थैले बन्द किये गये और उन थैलों को बाहर भेजने के लिए चौथी श्रेणी के एक कर्मचारी द्वारा डाकबाबू के पास भेजा गया । डाकबाबू ने चौथी श्रेणी के कर्मचारी को सभी थैलों की रसीद दे दी, लेकिन कुछ समय बाद जब उसने थैलों को भेजने के लिए उनकी छंटाई की, एक थैला गुम पाया । इन थैलों में 2,500 रुपये की भुगतान रकम थी ।

(ग) फँजाबाद के डाकपास द्वारा प्रधान डाकघर की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला । इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई और उसकी जांच का काम जारी है ।

गंगानगर में तस्करों की गिरफ्तारी

378. श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जून, 1966 के 'वीर भ्रजन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्थान सीमा पर गंगानगर में आठ तस्कर गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से एक व्यक्ति पाकिस्तानी था ;

(ग) क्या उनसे तीन हजार रुपये तथा एक राइफल बरामद हुई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 27-5-66 को 4 तस्कर गिरफ्तार किये गए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एक राइफल, उनके पास से 30 राउंड और लगभग 1,330 रु० के मूल्य का माल बरामद हुआ ; और

(घ) पकड़ा गया सामान श्री करनपुर के आई/सी, लैंड कस्टम्स के सिपुर्द कर दिये गए थे । राउंड सहित राइफल श्री करनपुर के स्टेशन हाउस आफिसर को सौंप दी गई थी ।

Sale of Fort of Tipu Sultan

379. **Shri Mohammed Koya:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fort made by Tippu Sultan in Manantody, Kerala was sold for Rs. 17 to an individual;

(b) whether this action of the P.W.D. was approved by the Revenue Department; and

(c) the action taken by the Archaeological Department in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) to (c). Government of India is not aware of any such sale and information is being called for from the State Government.

Delegation of Financial Control

380. **Shri Tridib Kumar**

Chaudhury:

Shri Indrajit Gupta:

Shri Dinen Bhattacharya:

Dr. Ranen Sen:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government have decided to delegate to the West Bengal Government complete financial control and power of disbursement in regard to an amount of Rs. 22 crores required to meet the cost of residuary problems of the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan;

(b) whether this will mean making an out-right grant of the said amount of Rs. 22 crores to the West Bengal Government or the money will be tied to specific rehabilitation projects approved by the Centre;

(c) whether the West Bengal Government have submitted any concrete scheme for meeting the residuary problems of rehabilitation for the displaced persons coming from East Pakistan on the basis of which the amount of Rs. 22 crores has been sanctioned; and

(d) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6510/66].

विदेशों से स्वदेश लौटने वाले भारतीय

381. श्री रामसेवक यादव :

डा० श्रीनिवासन :

श्री घुलेस्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री सरजू पाण्डेय :

क्या अमर, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की वृत्ता करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1965-66 में कितने भारतीय राष्ट्रजन विदेशों से से भारत वापस आये ;

(ख) श्रीलंका, बर्मा तथा अफ्रीका से कुल कितने भारतीय राष्ट्रजन भारत वापस आये ;

(ग) सरकार ने उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिलाया ; और

(घ) क्या शरणार्थियों का स्वदेश वापस भेजा जाना अभी बन्द नहीं हुआ है ?

अमर, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपसंज्ञी (श्री दा० रा० चह्वान) :

(क) इस मंत्रालय का सम्बन्ध केवल बर्मा, श्रीलंका तथा मोजैम्बिक से स्वदेश लौटने वालों से है तथा 1965-66 के वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विदेश से सभी भारतीय राष्ट्रजनों के वापस लौटने के आंकड़े नहीं हैं। 1965-66 के बीच बर्मा से भारत लौटने वाले भारतीयों की संख्या 56,004 है।

(ख) 10-7-1966 तक बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की कुल संख्या 1,49,114 है। मोजैम्बिक से जो स्वदेश लौटे हैं उनकी कुल संख्या 2,300 है। भारत श्रीलंका करार

1964 के अधीन श्रीलंका से भारतीयों का स्वदेश लौटना अभी तक शरंभ नहीं हुआ है।

(ग) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों में से 14,089 परिवारों को तथा मोजैम्बिक से लौटने वालों में से 113 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी गई है—जैसे, ऋण, रोजगार आदि। मोजैम्बिक से स्वदेश लौटने वाले कुल 500 परिवारों का लग-भग पुनर्वास हो चुका है। बर्मा से लौटने वाले भारतीयों में से 3,305 व्यक्तियों को और मोजैम्बिक से लौटने वालों में से 6 व्यक्तियों को सरकारी या गैर-सरकारी रोजगार पर लगाया जा चुका है। यह क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत बनती है।

(घ) जी, नहीं।

Higher Education

382. Dr. M. S. Aney:
 Shri Utliya:
 Shri Madhu Limaye:
 Shri Subodh Hansda:
 Shri S. C. Samanta:
 Shri Bhagwat Jha Azad:
 Shri M. L. Dwivedi:
 Shri Vasudevan Nair:
 Shrimati Renu Chakravarty:
 Shrimati Renuka Barkataki:
 Shri Vishwa Nath Pandey:
 Shri Daljit Singh:
 Shri H. C. Linga Reddy:
 Shri P. R. Chakraverti:
 Shri Kapur Singh:
 Shri Narasimha Reddy:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is proposed to bring the higher education on the concurrent list of the Constitution in view of the opposition of the States;

(b) the grounds of opposition by each of the States that opposed it; and

(c) the proposals of the Sapru Committee in this regard?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) A decision in the matter will be taken on receipt of replies from all the State Governments.

(b) Of the ten State Governments from whom replies have been received so far, nine have opposed the recommendation of the Sapru Committee mainly on the ground of Constitutional complications, administrative convenience, maintenance of standards and impracticability.

(c) The Sapru Committee recommended that University and higher education should be transferred from the State List to the Concurrent List, retaining intact Entry 66 in the Union List.

Study of Parliamentary Democracy by the Whips in Parliament

383. Shri Ram Harkh Yadav:
 Shri Tula Ram:
 Shri Vishwa Nath Pandey:
 Shri Basappa:

Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state:

(a) whether the Whips of all the Political Parties in Parliament approached the Prime Minister with the request that they be sent abroad to study the working of the Parliamentary democracy in the various foreign countries; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): (a) Yes.

(b) In view of the present critical Foreign Exchange position, the Prime Minister regretted her inability to consider the proposal for the time being.

Arrest of Naga Youth

384. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether a Naga youth with some explosive material in his possession was arrested at a Bus Stop in Tinsukhia (Assam) on the 31st May, 1966;

(b) if so, the details of his arrest and the suspicious circumstances in which he was caught; and

(c) the nature of the explosive material in his possession?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The information is being collected from the Government of Assam and will be laid on the Table of the House.

Border Belt along Cease-fire line

385. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have been recently approached with the Demand to create a 10-kilometer Border Belt along the Cease-fire Line from Poonch to Chhamb by vacating the civil population in order to check infiltration along the cease-fire line; and

(b) if so, the Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

West Bengal Rehabilitation Dues

386. Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased

to state:

(a) whether Government have not paid up the dues of the Government of West Bengal amounting to Rs. 13 crores for the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan who reside outside the camp in West Bengal;

(b) if so, the reasons for the delay; and

(c) how long this amount is pending with the Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) According to an assessment made jointly by the Government of India and the Government of West Bengal in 1960-61, it was estimated that a sum of Rs. 21.88 crores would be required for the liquidation of Residuary Problem relating to rehabilitation of old migrants in West Bengal. Of this amount of Rs. 21.88 crores, a sum of Rs. 14.20 crores has been sanctioned up to 30th June, 1966. Further, with a view to speeding up the processing of certain categories of schemes involving compliance with legal formalities and time-consuming procedures, the Government of West Bengal have been delegated full powers for the sanction of such schemes totalling about Rs. 5.15 crores.

Hence the total value of schemes sanctioned and delegated in favour of the Government of West Bengal is of the order of Rs. 19.35 crores, leaving a balance of Rs. 2.53 crores to be sanctioned by the Government of India for further schemes to be submitted and/or finalised by the Government of West Bengal.

It will be seen therefore that the Government of India have not withheld any "dues" of the Government of West Bengal. In actuality, the Government of India have released funds to the Government of West Bengal from time to time according to specific requisitions received from the latter

and progress made in the implementation of sanctioned schemes.

(b) and (c). Do not arise.

Additional Discount on Imports of Crude Oil

387. **Shri P. C. Borooah:**
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Kapur Singh:
Shri Buta Singh:
Shri Narasimha Reddy:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have asked the foreign Oil Companies for additional discounts on imports of crude oil to offset the affect of devaluation of the rupee; and

(b) if so, the Companies' reaction thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No, but Government has crude oil prices constantly under review and seeks reductions when market conditions justify.

(b) Does not arise.

Conference of Asian-African Scientists

388. **Shri Hari Vishnu Kamath:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Alvares:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Scientists from several Asian and African countries met in conclave in Delhi in April-May last;

(b) if so, the names of the countries represented at the meeting or conference;

(c) the names of all the scientists who attended together with their designations and other essential vita; and

(d) an assessment of the achievements of the Conference?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6511/66].

(d) The recommendations of the Conference covered such aspects of Afro-Asian collaboration as exchange of literature, scientists, joint programmes, visits by eminent scientists, training of technical personnel etc. The most note-worthy achievement was the realisation of the visiting scientists that out of mutual collaboration, science and technology could be instrumental in the economic development of the countries.

E.S.I. Dispensaries in Madurai

389. **Shri Umanath:** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a dearth of doctors in the various E.S.I. Dispensaries in Maudrai City in Madras State;

(b) whether it is also a fact that consequently a large portion of the new buildings remain unused as also the staff quarters constructed for them; and

(c) if so, the action taken to rectify the position?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) There is a shortage of two doctors only. Eight out of ten doctors sanctioned for the E.S.I. dispensaries are in position.

(b) A portion of one dispensary and some Staff Quarters are not being used. This dispensary has been constructed to cater to the needs of insured persons and their families, but medical care has not yet been extended to the families for want of doctors and some other staff.

(c) The State Government is taking action to appoint more doctors and other necessary staff. Medical care will be extended to the families as soon as the doctors and the other requisite staff are available.

Import of Technical and Scientific Books

390. Shri Umanath: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a delay on the part of Government in announcing their policy in relation to the import of technical and scientific books from abroad and if so the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that teachers, students and institutions relying on such books are handicapped due to the delay; and

(c) the reasons for not taking steps so as to have the books available at the beginning of the academic year itself?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir, The import policy for Books was announced on 1st April, 1966.

(b) and (c). Do not arise.

Explosion in Lumding

391. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have received any expert opinion regarding testing of the explosives found in Lumding; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Government of India have not received any expert opinion about this.

(b) Does not arise.

Age of Superannuation

**392. Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have been approached to raise the age of superannuation in the present circumstances

of longevity and high prices prevailing in the country;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) if not, the reasons for brushing aside the demands of the services?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Report on Training Colleges in Kerala

**293. Shri A. K. Gopalan:
Shri Imbichibava:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the A. N. Thampy Enquiry Commission on training colleges of Kerala have submitted their report;

(b) if so, when and the main recommendations thereof;

(c) whether it has been recommended that the tuition fee in private training colleges should be Rs. 300; and

(d) if so, the steps taken to implement the same?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (d). The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

गाजीपुर का मुख्य डाकघर

394. श्री सरजू पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजीपुर में मुख्य डाकघर के लिये नई इमारत बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो इमारत कब तक पूरी हो जायेगी और उस पर कितना खर्च होगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) भवन के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का कामलगभग पूरा हो चुका है । टेण्डर मंगाने का नोटिस अगस्त, 1966 में जारी किया जायेगा । आशा है कि काम संपि जाने की तारीख के बाद 15 महोने के भीतर समाप्त हो जायेगा । अनुमान है कि इस काम पर भूमि की लागत महित कुल लागत 3,14,600 रुपये होगी ।

आसाम सीमा पर पाकिस्तानी द्वारा घुसपैठ

395. श्री श्रींकार लाल बेरवा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सीमा पर 180 और पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि पाकिस्तानी घुसपैठ को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो वहां पर रखे गये पुलिस कर्मचारियों का वेतन-क्रम क्या है और क्या उनको स्थानीय वेतन-क्रम दिया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि तीन क्षेत्रों के बारे में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था और इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसको मुख्य बातें क्या हैं और क्या राज्य सरकारों ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सीमा पर 180 चौकियां स्थापित है ।

(ख) इन चौकियों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के वेतन-क्रम आसाम राज्य पुलिस अधिकारियों के समान ही हैं जैसा कि संलग्न सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया

गया है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्य. एन० टी०—6512/66]

(ग) किसी जांच आयोग की स्थापना नहीं की गई ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Increase in Price of Scientific Books after Devaluation

396. Shri D. D. Mantri:
Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Yashpal Singh:
Shri A. V. Raghavan:
Dr. Mahadeva Prasad:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of the devaluation of the Indian rupee the prices of scientific and other imported books and materials in the country have increased; and

(b) if so, the steps taken to check this price line?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is receiving the attention of the Government. As one of the measures to check the price line it has been decided that import licences for books will be issued on the condition that the importers should charge no more than the regular retail price expressed in rupees at the revised official rate of exchange.

Infiltration in Andamans

397. Shrimati Jyotsna Chanda:
Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether any infiltration is going on from nearby countries to Andaman and Nicobar Islands;

(b) if so, whether Government feel the need of protecting the Islands from such infiltrators; and .

(c) whether Government have any proposal to build up a strong navy in that Island for protection due to its strategic importance?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government recognise the strategic importance of the Islands and are taking appropriate steps for their security.

Staff of Government Colleges in Kerala

398. Shri A. V. Raghavan: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Departments in the various Government Colleges in Kerala functioned without any staff or inadequate staff during 1965-66;

(b) whether a statement containing the names of Government colleges in the State, the subjects taught in each college, the sanctioned strength of teaching staff and the number of days when such posts remained vacant during 1965-68 will be laid on the Table; and

(c) the steps taken to post adequate staff in the colleges?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. There was, however, shortage of staff in a few subjects in certain colleges.

(b) A statement which indicates the position prior to the review of the staffing position recently undertaken by the State Government as a result of which a reduction of surplus posts has been effected in all the Departments is laid on the Table.

(c) The Kerala Public Service Commission has been approached at the beginning of the academic year to

recommend qualified persons for all the vacant posts; the Principals have been authorised to provisionally fill up the vacancies and steps are being taken to transfer suitably qualified school teachers to Government Colleges of the House. [Placed in Library. See No. LT-6513/66].

रेडियो लाइसेंस

399. डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री किशन पटनायक :

श्री रामसेवक यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि लोगों को अपने रेडियो लाइसेंस बनवाने तथा उन्हें फिर से नया बनवाने में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस की शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दो दैनिक समाचार पत्रों और एक साप्ताहिक पत्र में सम्पादक के नाम भेजे गये पत्र और एक मासिक पत्र में सम्पादकीय टिप्पणी भी मेरे ध्यान में लाई गई है।

(ख) ये शिकायतें जनवरी के अन्तिम कार्य-दिवसों में लाइसेंस नवीकरण की भीड़ के कारण कुछ विशेष डाकघरों में लाइसेंस पुस्तकों की तथा विशेष टिकटों की समय पर कम सप्लाई के कारण या डाकघर कर्मचारियों की असफलता के कारण उत्पन्न हुई।

लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से दो महीने पहले नवीकरण की सुविधा उपलब्ध रहती है और यह सुविधा एक महीने बाद तक रहती है। अतः नवीकरण

के लिए लम्बी लाइनों का उपचार स्वयम् लाइसेंस धारकों के पास होता है और विभाग तो केवल रेस, आकाशवाणी तथा विभागीय विज्ञापनों के माध्यम से लाइसेंस धारकों को जल्दी नवीकरण कराने की अपील कर सकता है। विज्ञापन मन्वन्त्री कार्यों को और बढ़ाया जाएगा।

खजानों में कुछ विशेष मूल्यवर्गों के लाइसेंस शुल्क टिकटों के उपलब्ध न होने तथा कुछ डाइरेक्टरों में लाइसेंस पुस्तकों की कमी का तुरन्त पूरा किया गया। ये कमियां आंशिक रूप से इसलिए थी क्योंकि टिकट और पुस्तकें पहली बार लागू की गई हैं और भविष्य में इन कमी की पुनरावृत्ति की सम्भावना नहीं है।

जिन स्थानों पर डाइरेक्टर कर्मचारियों द्वारा नियमों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के कारण या उनके द्वारा किसी गन्ध गलती से लाइसेंस जारी करने और उनके नवीकरण में देरी हुई उन सभी मामलों में सुधार लाने की कार्रवाई की जा रही है।

Teleprinter Service

400. Shri Rishang Keishing: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether the Teleprinter which was installed at Imphal, Manipur, has been removed under the orders of the Post-Master General, Shillong;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the arrangement being made to meet the need of a Teleprinter at Imphal?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao):
(a) Yes.

(b) Since the existing landline system available between Gauhati and Imphal did not suit Teleprinter working, the terminal Teleprinter machines have been temporarily removed and utilised for some other work.

998 (Ai) LS—6

(c) Action has been taken for retransposition of the landline which is likely to be completed by 1967-68, after which a suitable system to permit Teleprinter working will be installed. The questions of introducing Radio Teleprinter working between Imphal & Gauhati and providing microwave link on the route Jorhat-Kohima-Imphal are also under consideration.

NEFA Administration

401. Shri Rishang Keishing: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of officers under NEFA administration whose retirement dates are already due but which have been re-extended;

(b) the reasons which have prompted the Government to do so; and

(c) how long this practice is likely to continue?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Only one officer due for retirement has been granted extension for one year upto 31-12-66.

(b) No suitable substitute of younger age in the line of succession was available to shoulder the special responsibilities attached to the post.

(c) The question of continuing the practice does not arise now. Only in exceptional circumstances extension is allowed in the public interest.

Telephone connections in Srinagar

402. Shri Basumatari: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Srinagar's present 2,000 telephone connections would be increased to 4,500 by April-May, 1967; and

(b) if so, the extent of expenditure involved?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao):

(a) The present 2000 line Exch. at Srinagar will be extended to 3300 lines by the end of 1966. Its further expansion to 4500 lines is likely to be completed during 1968.

(b) The expenditure for the works mentioned above will be Rs. 30.18 lakhs (approx.)

Aligarh University Bill

403. Dr. M. S. Aney: Will the Minister of Education be pleased to state the time by which the Aligarh University Amendment Bill be introduced?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): Long term legislative proposals to amend the Aligarh Muslim University Act and Statutes are expected to be introduced in the Parliament as soon as the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, 1965, which is pending before the Lok Sabha, is passed.

Attack by East Pakistan Riflemen across Haridaspur Border

404. Shri Baswant:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Hukam Chand
Kachhavaitya:
Shri Bade:
Shri Basumatari:
Shri Gulshan:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 1000 Pakistanis backed by a contingent of 20 men of the East Pakistan rifles attacked Indian nationals across the Haridaspur border in the Chapra Police Station of the Nadia district on the 12th June, 1966 as a result of which several persons were wounded and injured; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya

Charan Shukla): (a) A number of Pak nationals accompanied by about 20 men of the East Pakistan Rifles trespassed into Indian territory and hurled brickbats on Indian nationals. Five Indian nationals received injuries.

(b) A protest has been lodged by the District Magistrate, Nadia, with the Deputy Commissioner, Kushtia, East Pakistan.

Bastar Incident

405. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in May last a memorandum signed by several M.Ps. and M.L.As. was submitted to the President, embodying certain demands in connection with the tragic incidents that took place in Bastar in March last and the inquiry commission set up by the Madhya Pradesh Government; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). Shri A. B. Vajpayee, M.P. accompanied by certain other M.Ps. and M.L.As. met the President on 2-4-1966 and presented to him a petition signed by 75 Members of Legislative Assembly of Madhya Pradesh. Since a Commission of Inquiry had already been set up by the State Government, no action on the demands was considered necessary.

Kidnapping of a Policeman in Delhi

406. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3980 on the 20th April, 1966 regarding the abduction of a Head Constable of the Delhi Police from a Check Post on Rohtak Road, Delhi and state:

(a) whether the investigation in this regard has since been completed; and

(b) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Investigations have been completed and three persons will be set up for trial shortly.

Central Economic Pool

**407. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 871 on the 30th March, 1966 and state:

(a) whether the various aspects connected with the Central Economic Pool for staffing various management positions in the Public Sector Undertakings have since been considered; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The various aspects connected with the Central Economic Pool for staffing various management positions in the Public Sector Undertakings are still under consideration.

Deputation Quota of Orissa in I.A.S. Cadre in Central Service

**408. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of vacancies in the Deputation Quota of the I.A.S. Cadre in Central Service from Orissa State at present; and

(b) the reasons for not filling these vacancies and the steps proposed to be taken to fill up the quota?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The Central deputation quota in the

I.A.S. Cadre of Orissa is 33, in a sanctioned strength of 170. There are at present 31 officers serving against this quota. The actual Cadre strength in the State is, however, only 141, on which the Central Deputation quota works out proportionately at on 28.

General Strike in Agartala

409. Shri Biren Dutta: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a complete general strike took place at Agartala on the 17th June, 1966;

(b) the names of Government offices that were closed due to the strike;

(c) the demands of the people; and

(d) the measures Government propose to take to meet the demands of the people?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, there was a general hartal.

(b) No Government offices were closed.

(c) (i) Opening of more fair price shops;

(ii) Increase in the scale of ration from existing rate of 2 kgs. per head per week to 4 kgs. per head for labour class and 3 kgs. for others;

(iii) Starting of test-relief works throughout Tripura and distribution of gratuitous relief etc.

(d) Government of Tripura have already started test relief works and undertaken distribution of gratuitous relief in the affected areas. A large number of fair price shops have also been opened. The demands in this regard have, therefore, been largely met. Demand for increase in the scale of rations is not feasible.

Central Kajora Colliery

410. Shrimati Renu Chakravartty:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken on the mass representation received from the workers of Datta's Central Kajora Colliery; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) The complaints have been enquired into. Legal action is being considered against the management wherever necessary.

(b) Does not arise.

Citizenship of Displaced Persons in Tripura

411. Shri Biren Dutta: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of displaced persons in Tripura are not getting citizenship;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the number of petitions for citizenship still pending for disposal?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir. Out of the 1,37,753 applications received up to 30th June, 1966, 1,22,137 have been accepted.

(b) Does not arise.

(c) 2,280 as on the 30th June, 1966. Out of these 1,131 applications are incomplete and the remaining 1,149 are under various stages of processing.

Building for Agartala P.O.

412. Shri Biren Dutta: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether land for the construction of departmental building for Agar-

tala Central Post Office and staff quarters has been acquired;

(b) when the construction work will start; and

(c) the reasons for delay in this matter?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) A departmental post office building already exists and adequate land is available for its extension. Land for staff quarters measuring 184'X 60' has been acquired and possession taken over.

(b) Construction may be expected to be taken up in 1967-68 after completion of all procedural formalities.

(c) The preliminary estimate for extension of the Head Post Office building is under scrutiny. So far as construction of quarters is concerned the delay is due to existence of ban till recently on the construction of quarters.

Government Employees in Tripura

413. Shri Biren Dutta: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of employees in all Departments of Tripura who continued to be temporary after serving for five years continuously; and

(b) the number out of them who were made quasi-permanent and the number of those to be confirmed?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) 6,571.

(b) 1,997 employees of the Government of Tripura have been declared quasi-permanent. 1,565 employees have still to be confirmed.

उत्तर प्रदेश के उपकुलपतियों का सम्मेलन

414. श्री सरजू पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विश्व-विद्यालयों के उपकुलपतियों के नैनीताल में हुए सम्मेलन में किये गये प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य-मुख्य मुद्दाव दिये गये हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) :

(क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन ने निम्नलिखित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है :

(i) प्राचीन भारतीय विज्ञानों और टेक्नोलोजी का नवीकरण; और

(ii) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के संदर्भ में पुरानी कृतियों के ठीक-ठीक सम्पादन के लिए पाण्डुलिपियों के साधनों का सामंजस्य और एकत्रीकरण ।

(ग) मुद्दाव विचाराधीन हैं ।

Capitation Fee

415. **Shri Kajrolkar:**

Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in certain States some private technical institutions have been collecting capitation fee from students seeking admission; and

(b) if so, the steps taken to prevent this practice?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. As far

as we are aware, there are 7 private Engineering Colleges all located in Mysore State which are charging capitation fee from students seeking admission.

(b) A Joint Committee of the University Grants Commission and the All India Council for Technical Education appointed in 1964 to examine the conditions of work, admissions and standards of education in these colleges recommended that the question of bringing these colleges within the purview of the "Open Door" policy of the Government of India may be considered provided they are willing to discontinue collection of capitation fees and the sponsors are prepared to contribute their share of expenditure for the remaining developmental cost of the colleges.

The State Government has informed that the Education Minister, Mysore State, had a meeting on 28th April, 1966 with the Managements and the Principals of these Colleges and on the basis of the discussions in the meeting the State Government is formulating proposals to discontinue the collection of capitation fees and to improve the standards. The final proposals of the State Government are awaited.

Education Abroad

416. **Shri Kajrolkar:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the cost of education abroad is going to be increased due to devaluation of the Rupee;

(b) the number of students studying abroad and the total additional cost involved; and

(c) whether Government are contemplating to give loans to students studying abroad, to meet the increased cost of education?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) Yes, Sir.

(b) According to information available there are about 14,500 students studying abroad. It is not possible to indicate the additional expenditure because:

- (i) the exact period of study of each student is not known; and
- (ii) remittances are not sent for every student as some of them are in receipt of foreign scholarships or are earning side by side with their studies.

(c) Yes, Sir. Government are already implementing a scheme under which loans are given to parents and guardians of students studying abroad.

Central Government Employees on Deputation

417. Dr. Chandrabhan Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of Central Government employees who are on deputation from one Department to another, or to States or to Corporations;

(b) the number of such officers who are actually posted in Delhi and are on deputation from the Department of Government to the other; and

(c) the number of deputation allowance paid to persons referred to in parts (a) and (b) above separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Special Postal Stamps

418. Shri Sivamurthi Swamy: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the social reformers whose commemorative Postal stamps are

proposed to be issued during 1966-67 and 1967-68;

(b) whether any representations from Karnatak have been received regarding Mahatma Basaweshwar of 12th Century who was the first man to remove untouchability; and

(c) if so, when it is to be issued?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) Gopal Krishna Gokhale in 1966.

For 1967 and 1968 the proposals are still to be finalised.

(b) and (c). The proposal was received for the issue of a stamp in 1965 but could not be accepted owing to the limited capacity of Security Printing Press, Nasik.

Bhopal Telephone Exchange

419. Shrimati Maimoona Sultan: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work for the provision of an automatic telephone exchange for new Bhopal is going on too slow;

(b) the progress so far made and when it is likely to be completed; and

(c) the reasons for the slow progress?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) No.

(b) Building design has already been finalised. The building is likely to be completed by the middle of 68. After completion of equipment installation exchange is likely to be put into service in 69-70.

(c) Does not arise.

"Choose Your Career" Campaign

420. Shrimati Maimoona Sultan: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether in June last, the Directorate of Employment and Training Delhi launched a campaign entitled "Choose Your Career";

(b) if so, the salient features thereof;

(c) the success achieved; and

(d) whether similar campaigns are also to be launched in other parts of the country?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes.

(b) The Directorate of Employment, Training and Technical Education had launched the "Choose your Career" campaign from 6th June to 15th June, 1966 in Delhi. The campaign was conducted at 7 centres in Delhi, at Employment Exchange, New Delhi; Employment Exchange, Pusa; Industrial Training Institute, Arab-ki-Sarai; Employment Exchange, Daryaganj; Employment Exchange, Subzi-mandi; University Employment Information and Assistance Bureau, Delhi and Gandhi Memorial Multipurpose Higher Secondary School, Shahdara. The timings were 9.30 to 12.30 in the morning and 5.00 p.m. to 7 p.m. in the afternoon. Detailed information on careers, course open to the students in India and particularly in Delhi was provided at each of the centres.

(c) Nearly 5,000 persons visited the centres and availed of the careers' counselling facilities provided.

(d) This programme is arranged annually in the States of Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. The programme has been recommended to other States. It is for them to organise similar programmes.

Pak. Bombs

421. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand
Kachhavalya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian border patrols recovered some highly explosive Pakistani bombs from a Pillar in Utia Village under Chapra Police Station in Nadia District (West Bengal) on the 22nd June, 1966 and if so, the number thereof;

(b) the time for which they had been lying there; and

(c) the number of persons arrested in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) There is no village called Utia in Chapra Police Station. However, on 22nd February, 1966 at 14.30 hours, a person of the locality found a ration bag containing 8 ordinary country-made crackers near a boundary pillar in village Sutia, Police Station Chapra and informed the Police Station authorities about it. These crackers were taken over by the police.

(b) They are presumed to have been left there by criminals the previous night.

(c) No person has been apprehended in this case.

Retirement Age

422. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether there was a proposal to bring down the age of retirement for Government servants from 58 years to 55 years with a view to tackling the problem of surplus staff; and

(b) if so, Government's decision in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) There is no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

Shifting of Central Circle, Nagpur

423. Shri Balkrishna Wasnik: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether an assurance was given to the employees of P. & T. and the people of Nagpur that on shifting of the Office of the Post-Master General, Central Circle, Nagpur, some P. & T. offices from other places will be brought to Nagpur to utilise the accommodation there and to avoid hardships to the employees, who will have to be uprooted from Nagpur; and

(b) if so, the progress made in the matter?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) No, Sir. A suggestion to shift Adchen's office at Jabalpur and D.D.P.L.'s office at Calcutta to Nagpur was considered but had to be given up for administrative reasons. However a new Telecom, Training Centre has been opened at Nagpur.

(b) Does not arise.

R.M.S. Building, Patna

424. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether the construction of R.M.S. building, Patna is included in the work plan for 1966-67; and

(b) if so, the reason for not taking up the work?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and

Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) No, Sir.

(b) The work had not been included by the Railways in the works programme for 1966-67 due to difficulty in providing funds.

Treatment of Onkar Nath Thakur

425. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether any help has been given for the treatment of well known musician of India, Shri Onkar Nath Thakur who is suffering from stroke of partial paralysis; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No application for financial assistance has been received so far and hence no help could be rendered to Shri Onkar Nath Thakur.

(b) Does not arise.

University for Hill Districts of Assam

426. Shri P. C. Borooah:
Shrimati Jyotsna Chanda:
Shri Kajrolkar:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to the constitution of a separate new university for the Hill districts of Assam; and

(b) if so, the salient features of this university?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The proposal to set up a new university for the North Eastern Region of India including the hill districts of Assam is still under the consideration of the Government.

Pak. Infiltrators

427. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the latest position about Pakistani Infiltrators in Assam, West Bengal and other areas in the East; and

(b) the number of infiltrators deported during the last year and this year upto-date?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence (Shri Hathi): (a) The latest position about Pakistani infiltrators in Assam, West Bengal and Tripura is:

State	No. estimated to have infiltrated	No. who have left for Pakistan
Assam	2,50,000	1,68,438
West Bengal	1,16,000 (Provisional)	15,932
Tripura	50,000	49,000

(b) The number of infiltrators deported is :

State	No. deported in 1965	No. deported in 1966
Assam	26,998	5075 (Till March)
West Bengal	825	20 (Till April)
Tripura	454	..

Survey for Oil Deposits in Guntur

428. Shri M. N. Swamy: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether any survey was carried out in Guntur District recently to find out oil deposits; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) The surveys carried out so far have not indicated the presence of structures favourable for the accumulation of oil and gas.

Walcott's Attempt to escape

429. Shri Kajrolkar:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Daniel Walcott an American National and his French Associate Jean Claude Donze made an attempt to escape from the jail custody in Madras recently;

(b) whether these persons had any outside help in their attempt; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) There are no indications that any outside help was given.

(c) Does not arise.

बरोनी तेल शोधक कारखाना

430. डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाली टिन न मिलने के कारण गत जून में बरोनी तेल शोधक कारखाने में मिट्टी के तेल का उत्पादन बन्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हा, तो खाली टिन न मिलने के क्या कारण हैं ?

पेंडेंटिज्म और रसायन मंत्री (श्री अल्लगेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Textile Wage Board

431. **Shri Dinen Bhattacharya:**

Shri A. K. Gopalan:

Shri Kolla Venkaiah:

Shri Dasaratha Deb:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Textile Wage Board has completed its work; and

(b) if so, when it is expected to give its award?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Not yet.

(b) It is not possible to say precisely at this stage as to when the work of the Wage Board would be completed. The Board is, however, making every effort to complete its work as expeditiously as possible.

Uniform Academic Year for Universities

433. **Shrimati Renuka Barkataki:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.G.C. has prescribed Uniform Academic year for all Universities; and

(b) if so, the reaction of the Universities thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. The University Grants Commission has, however, suggested a uniform calendar of terms to the Universities.

(b) Only nine Universities have sent their replies and their reaction is generally favourable to the suggestions of the Commission.

All India Council of Sports

434. **Shri Basappa:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the main decisions taken by the All India Council of Sports have been received in his Ministry; and

(b) if so, the nature thereof and whether the Ministry has approved the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darsan): (a) The recommendations made by the All India Council of Sports at its last meeting held on the 7th and 8th July, 1966 have been received.

(b) The main recommendations are as under:—

1. grant of financial assistance to the Indian Olympic Association for sending a contingent of 32 athletes/players and officials to Jamaica for participation in the Commonwealth Games;
2. grant of financial assistance to State Sports Councils/National Federations etc. for holding Coaching Camps;
3. release of foreign exchange for participation of an Indian team in the World Amateur Golf Championship;
4. grant of permission to the Indian Hockey Federation for holding International Hockey Tournament in India;
5. grant of permission for visits abroad of Indian Hockey teams;
6. withdrawal of recognition from the All India Deaf and Dumb Sports Association; and
7. grant of facilities for providing new play-fields and improving existing play-fields.

All the above recommendations have been accepted by the Ministry of Education.

Special Information Service

435. Shri Basappa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether any "Special Information Service" has been recently inaugurated at Bangalore by the Post Master General in the telephone systems; and

(b) if so, what will be the advantages accruing to the people?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications . (Shri Jaganatha Rao): (a) Special Information Service (Code 176) has been inaugurated in Bangalore on 1-7-1966.

(b) By dialling 176 subscribers in Bangalore can obtain information about—

- (i) Scheduled timings of Trains, buses and Air Services;
- (ii) timings and rates of pictures being exhibited in cinema theatres in Bangalore;
- (iii) Places of tourist interest, prominent land marks, streets etc.;
- (iv) weather reports;
- (v) results of sports events being held in the city;
- (vi) Postal, Telegraph and Telephone facilities and rates;

and several other items which evoke local interest.

The same facility is available in other cities such is Bombay, Delhi, Calcutta, Madras etc.

Reservation for S. Cs. and S. Ts.

436. Shri Basappa: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) why the percentage of appointments guaranteed to the Scheduled

Castes and Scheduled Tribes under the Constitution have not been kept up and fulfilled; and

(b) whether any State Government and particularly Mysore Government are taking any steps to increase the absorption of more Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in government service?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) The percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in appointments to the posts and services under the Government of India have been fixed by the Government of India, in pursuance of the provisions of Articles 16(4) and 335 of the Constitution. The Constitution does not lay down the percentages of reservation for members of these communities.

The main reason for the shortfall in the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is that suitable Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates are not available to fill all the posts reserved for them, particularly those posts for which technical or special qualifications are required.

(b) Reservation in state services is the concern of the respective State Governments, *vide* Article 335, read with Articles 16(4) and 12, of the Constitution.

Foreign Exchange Earnings from Postal Stamps

437. Shri Surendra Pal Singh: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether any proper assessment has been made to find out the extent and quantum of foreign exchange India earns each year from the sale of Postal Stamps to philatelists all over the World; and

(b) if so, the figures for such earnings for 1964-65 and 1965-66?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jagannatha Rao): (a) The India mint postage stamps are sold through the authorised agent in USA and also by the Philatelic Bureau, Bombay against the direct orders of the foreign customers. In addition to this, various stamp dealers in India export Indian mint stamps. No proper assessment has been made as to the extent of foreign exchange earned by sale of stamps through such stamp dealers in India.

(b) Figures for the sale of stamps through stamp dealers to foreign countries have not been assessed but the figures of the foreign exchange earned by sale of stamps through the authorised agent and Philatelic Bureau, Bombay are shown below:

1964-65	Rs. 28,629.00
1965-66	Rs. 35,386.00

Admission in Colleges in Madras

438. Dr. P. Srinivasan: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great rush for admission in Arts Colleges, especially in Madras city;

(b) if so, whether Government propose to give advice or directions to work the Arts Colleges in shift system to enable students to get admission and thereby relieve anxiety of the parents and students; and

(c) if not, the alternative methods to satisfy them?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Admission to colleges in States is the responsibility of the States concerned and the Central Government has no information regarding the great rush for admission in Arts colleges, especially in Madras city.

(b) and (c). The question of pressure of regular students for admissions to colleges was discussed at the meeting of the Central Advisory

Board of Education held in October, 1965, and the Board recommended that colleges with suitable educational facilities should have about 10 working hours, in a single or a double shift as may be feasible in the light of local conditions, so that besides solving the problem of increased demand for admissions the maximum utilisation of facilities is secured. The recommendations of the Board have been brought to the notice of all State Governments.

Barauni Refinery

439. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether the lay-out of some units of the Barauni Oil Refinery has not been completed according to schedule;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken against the contractor?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) There have been some delays in the arrival of equipment and materials and certain difficulties over the work of the contractors.

(c) the Indian Oil Corporation is considering what action is called for.

चौथी योजना में नये विश्वविद्यालय

440. श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में नये विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में दो नये विश्व-विद्यालय खोलने का विचार है ;

(ग) क्या कुछ अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) क्या सम्बलपुर उड़ीसा में एक विश्वविद्यालय तथा एक ऐसा विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) से (घ) चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि में नये विश्वविद्यालय खोलने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यों में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय केन्द्र खोलने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि में अब तक केवल नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है।

जहाँ तक उड़ीसा का संबंध है, उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के अपने प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह मांगी है। प्रस्ताव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

Female Education

441. **Shri Jedhe:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government are considering some proposals for the uplift of the females in all walks of life;

(b) if so, whether it is a fact that as an incentive to higher education to females, Government propose to reimburse the tuition fee upto B.A. standard in case of females, instead of up to Higher Secondary Examination as at present;

(c) if so, when the decision is likely to be taken; and

(d) the details of other concessions likely to be granted to females under the scheme?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) In so far as the Ministry of Education is concerned Government have created special machinery in the States and at the Centre to promote education of girls and women. Special Schemes for girls' education were included in the Third Five Year Plan as an incentive to bring more and more girls to schools and similar schemes are also included in the Fourth Plan.

(b) to (d). No specific proposals are under consideration of the Government.

Tuition Fees of Girls

443. **Shri Jedhe:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Delhi the college tuition fee of male and female students is the same while the tuition fee for female students up to the Higher Secondary Examination is less;

(b) if so, whether Government propose to reduce the tuition fee in case of female students upto B.A. standard as an incentive to higher education; and

(c) if so, when the matter is likely to be finalised?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes.

(b) No such proposal is under consideration of Government.

(c) Does not arise.

Desertions by Refugees

444. **Shri R. Barua:**

Shri D. D. Mantri:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 4000 refugees from East Pakistan recently

deserted their camps in Betul District (M.P.); and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan):

(a) About 800 families comprising about 4,000 persons had left Patuapura and Temru camps in Betul District on the 25th June, 1966 and squatted near Barbatpur Railway Station close by. They were, however, persuaded to return to the camps on the 3rd July, 1966.

(b) Their grievances were:—

- (i) lands selected for their rehabilitation were not fit for paddy cultivation;
- (ii) lack of irrigation facilities; and
- (iii) reduction in the rice quota made by the State Government.

The cut in the rice quota has been partially restored.

Drilling in Jwalamukhi

**445. Shri Hem Raj:
Shri Daljit Singh:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the progress made in the drilling operation in the Jwalamukhi area; and

(b) the number of wells dug so far in the area and the results obtained from each of them?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b). A total of five structural wells and one deep well have been completed in the area. Two deep wells, one at Jwalamukhi and the other at Balh, are presently under drilling. The results of the tests carried out so far do not indicate the presence of oil or gas in significant quantities.

Three Language Formula

**446. Shrimati Maimoona Sultan:
Shri P. Muthiah:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Education Commission for the implementation of the Three Language Formula;

(b) Government's decisions in the matter; and

(c) whether the opinions of the State Governments were sought in this connection and if so, their response thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The following is the summary of the Recommendations of the Education Commission on the Three-Language Formula:

Classes I—IV: The study of only one language should be compulsory. It will naturally be mother tongue.

Classes V—VII: The study of two languages should be compulsory at this stage. The second language may be either the official language of the Union (Hindi) or the Associate official language of the Union (English), so long as it is thus recognized.

Classes VIII—X: The study of three languages should be obligatory at this stage and one of these three languages should be the official language of the Union or the Associate official language whichever was not taken up in Classes V—VII.

Classes XI—XII: The study of only two languages should be compulsory at this stage.

Higher Education: The study of no language should be compulsory.

(b) The matter is under consideration.

(c) The Report of the Commission is being circulated to State Governments for their comments.

Use of Non-coking Coal

447. Shri Raghunath Singh: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 881 on the 30th March, 1966 and state:

(a) whether Government have completed the investigation regarding the use of non-coking coal as coking coal on the basis of the process developed by the Central Fuel Research Institute; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Investigation on the project has not yet been completed.

(b) Does not arise.

Theft of Maps from Nicobar Islands Secretariat

**448. Shri A. K. Gopalan:
Shri M. N. Swamy:
Shri Dinen Bhattacharya:
Shri Dasaratha Deb:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some secret maps were stolen from the Secretariat of the Chief Commissioner of Andaman and Nicobar Islands during 1964;

(b) whether any enquiry was conducted in the matter; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) One Shri Austin Paul son of late Shri Paul

Leong of Port Blair while working as stationery clerk in the Chief Commissioner's Secretariat was alleged to have been found in illegal possession of certain "Restricted" maps and confidential documents in December 1963 after his resignation from the Andaman and Nicobar Administration.

(b) and (c). Shri Paul was prosecuted for the alleged stealing of Government stationery articles under section 381 of Penal Code in the court of Additional District Magistrate, Port Blair in December, 1964. The court acquitted Shri Paul. A prosecution against Shri Paul was thereafter launched in May, 1965 under Indian Official Secrets Act, 1923. The case is sub-judice.

Corruption in the Andaman & Nicobar Islands

**449. Shri A. K. Gopalan:
Shri Dasaratha Deb:
Shri M. N. Swamy:
Shri Dinen Bhattacharya:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Central Vigilance Commissioner visited Andaman and Nicobar Islands during 1965;

(b) if so, whether he received a memorandum from the Non-Gazetted Officers' Association, Port Blair giving instances of serious corrupt practices prevailing in the Islands; and

(c) the steps taken by the Central Vigilance Commissioner in the matter and the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, sir.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

Refusal by Pakistan to accept Postal Bags for Afghanistan

450. **Shri Jashvant Mehta:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has refused to accept Postal bags for Afghanistan at Hussainiwala point;

(b) if so, whether Government have informed the Government of Afghanistan regarding this; and

(c) the steps taken by Government for this breach of International Law by Pakistan?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) The Pakistan Postal authorities were refusing postal bags for Afghanistan at Hussainiwala Bridge on the plea that they were not properly closed.

(b) Yes.

(c) The matter was taken up with the Pakistan Postal authorities and also at the diplomatic level. The mails for Afghanistan are now being accepted by the Pakistan Postal staff. Instructions have also been issued to our staff to ensure that the bags for Afghanistan are properly closed so that there is no scope for raising objection even on the flimsiest grounds.

Lightning Strike by Telegraph Staff Delhi

451. **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri D. C. Sharma:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether telegraph services were paralysed for 6 hours in New Delhi and most of the north Indian towns by a lightning strike by several hundred Operators of the Central Telegraph Office, New Delhi, on the 13th July, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to ensure that such essential services are not disrupted?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jagantha Rao):

(a) Yes.

(b) and (c). An enquiry by a Senior Officer of the Department to ascertain the reasons has been instituted. Further steps will be taken after the enquiry report is received.

Promotion of Government Servants

452. **Shri Brij Basi Lal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to replace the present system of seniority by merit for giving promotions to their staff;

(b) if so, whether Government have started the implementation of this new scheme; and

(c) whether there have been any protests against the introduction of this new scheme?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Under the present system promotions to selection posts are made on the basis of merit with due regard to seniority; promotion to other posts which are not selection posts are made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit and in certain cases promotions are made on the basis of competitive examination and/or selection through interview limited to departmental candidates in the lower grade. There is also a scheme of merit promotion and advance increments for certain scientific and technical staff. Government do not propose to replace the present system of promotions. However, a closer scrutiny of merit of officers has been undertaken to ascertain their suitability for higher posts.

(b) In view of answer to (a) that no new scheme has been started, the question does not arise.

(c) Does not arise.

Paper Plant at Indravati Basin

453. **Shri Wadiwa:**
Shri Chandak:
Dr. Chandrabhan Singh:
Shri Hukam Chand
Kachhavaiya:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1838 on the 9th March, 1966 and state:

(a) whether the Paper Corporation of India has now been entrusted with the work of detailed investigation for the establishment of pulp and paper plant in the Indravati Basin in Dandakaranya; and

(b) if so, the progress made so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) The proposed Paper Corporation has not yet been set up.

(b) Does not arise.

Spinning Mill at Jagdalpur

454. **Shri Wadiwa:**
Shri Chandak:
Dr. Chandrabhan Singh:
Shri Hukam Chand
Kachhavaiya:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 165 on the 16th February, 1966 and state:

(a) the progress so far made on the establishment of spinning mill at Jagdalpur under the Rehabilitation Industries Corporation in Dandakaranya;

(b) whether the progress made is according to schedule; and

(c) if not, the steps Government propose to take for establishing the spinning mill?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) to (c). The scheme for the establish-

998 (A1) LSD—7.

ment of a Spinning Mill in Dandakaranya has to be implemented by the Rehabilitation Industries Corporation. The Corporation is reconsidering the question of the location of the mill and has decided that the economics of alternative sites *vis-a-vis* Jagdalpur should be examined. A Sub-Committee has been appointed for the purpose and the report is to be submitted to the Board of Directors at its next meeting. A fresh target for commencement of production will be fixed after a final decision is taken about the location and a Project Report has been prepared. Meanwhile, orders already placed for machinery are being pursued.

Scientific Posts in the Ministry of Home Affairs

455. **Shri Kajrolkar:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of posts/cadres recommended by the respective Heads of Departments to be declared "Scientific" in the Ministry of Home Affairs and its attached and subordinate offices under the recommendations of the Second Pay Commission;

(b) the number of cases still awaiting a final decision of Government; and

(c) when a decision is proposed to be taken in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

12 hrs.

RE: CALLING ATTENTION
 NOTICES (Query)

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) :
 अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसके बाद लिया जायगा। कौन सा ध्यान आकर्षण है ?

श्री रामसेवक यादव : भागवत ज्ञा आजाद के नाम पर। एक हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न भी है, जो मैंने ता० 25 को दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने होम मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। उसका जवाब आ लेने दीजिये।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरी गुजारिश है, अध्यक्ष महोदय। मैंने आपको पूर्वी बंगाल में जो जनतान्त्रिक विद्रोह हो रहा है, उसके सम्बन्ध में.....

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे लिखा है कि उसे कन्सीडर किया जाय ?

श्री मधु लिमये : क्या आप उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने पुनर्विचार करने को लिखा है, आज ही मुझे पहुंचा है।

श्री मधु लिमये : उसके साथ पत्र भी लिखा है, आप उस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : आपका पत्र भी पहुंचा है।

Shri Hem Barua (Gauhati) : I submitted a Call Attention notice on the acute food situation in Assam, Kerala and West Bengal. I was told by your office that that was under consideration. But just now I have been informed that that has been disallowed. Whenever there is an acute food situation in any part of the country, I think, a Member has the right to demand a reply or some sort of a statement from the Government. I do not understand why you have pushed it out altogether.

Mr. Speaker : Because there were so many questions yesterday that had been answered and there might be further replies also. I will again look into it.

Shri Hem Barua : I went through the questions put yesterday. The questions do not clarify anything.

Mr. Speaker : Then, a separate discussion can be asked for.

Shrimati Renu Chakravartty (Barackpore) : I just wanted to point out that the price of rice in our parts is beyond Rs. 80 a maund.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक ओर आपकी आज्ञा है कि खड़े हो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ जो खड़ा होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, आज इन पांच प्रश्नों के दौरान पचास बार खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े हुए थे, लेकिन मैंने आपका नाम कहीं नहीं देखा।

श्री काशी राम गुप्त : अगर कोई सदस्य खड़ा हो, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान तो जरूर जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वह खड़े हों और मैं देख न सकूं। मैं जरूर देखता हूं, लेकिन बाज वक्त मजबूरी होती है, बोल नहीं सकता। मैं हर वक्त आपकी तरफ देखता हूं।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : मैं आपकी इजाजत से गुजारिश करूंगा कि लोक सभा की बुक्स में ऐसा प्राविजन है कि अगर कोई प्रश्न सूची में ऐसा महत्वपूर्ण हो, जो समय समाप्त होने के कारण रह गया हो, लेकिन उसके बारे में जवाब देने के लिये मंत्री महोदय तैयार हों, तो आपकी अनुमति से वह जवाब दे सकते हैं। आज जो अगला प्रश्न आने वाला था, वेज बोर्ड जर्नलिस्ट्स के बारे में, आपको मालूम है.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है। अगर मिनिस्टर साहब चाहें और रिक्वेस्ट करें तो मैं इजाजत देने के लिये तैयार हूं।

श्री बूटा सिंह : मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह रिक्वेस्ट मिनिस्टर साहब की तरफ से आनी चाहिये, अगर वह चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मिनिस्टर साहब चाहते हैं जवाब देना, तो दें, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

12.03 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT ON FLOOD SITUATION

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): I beg to lay on the Table a statement on the flood situation in the country. [Placed in Library. See No. LT-6482/66].

ANNUAL ACCOUNTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, ETC.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): On behalf of Shri M. C. Chagla, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Annual Accounts of the University Grants Commission for the year 1964-65 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 19 of the University Grants Commission Act, 1956. [Placed in Library. See No. LT-6483/66].

(2) A copy of the Annual Report of the Council of Scientific and Industrial Research for the year 1965-66 along with the Audited Statement of Accounts for the year 1964-65. [Placed in Library. See No. LT-6484/66].

GOVERNMENT RESOLUTION CONSTITUTING WAGE BOARDS

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): Sir, on behalf of Shri Jagjivan Ram, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(1) Government Resolution No. WB-14(1)/64 dated the 28th May, 1966 constituting the Wage Board for Road Transport Industry.

(2) Government Resolution No. WB-15(1)/64 dated the 28th May, 1966, constituting the Wage Board for Electricity Undertakings.

(3) Government Resolution No. WB-3(4)/66 dated the 4th June, 1966 announcing acceptance of the final recommendations made by the Wage Board for Tea Plantation Industry.

(4) The main conclusions of the Fifth Session of the Industrial Committee on Cement held at New Delhi on 22nd April, 1966.

(5) Notification No. S.O. 1444 published in Gazette of India dated the 14th May, 1966 adding certain industries to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947, under sub-section (3) of section 40 of the said Act.

[Placed in Library. See Nos. LT-6485 to LT-6489/66].

UPSC (EXEMPTION FROM CONSULTATION) SECOND AMENDMENT REGULATIONS ETC.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): Sir, I beg:

(1) to re-lay on the Table a copy of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Second Amendment Regulations, 1966, published in Notification No. G.S.R. 622 in Gazette of India dated the 30th April, 1966, under clause (5) of article 320 of the Constitution, together with an explanatory note. [Placed in Library. See No. LT-6330/66].

(2) to lay on the Table—

(i) A copy of the Defence of India (Third Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 771 in

[Shri Hathi]

Gazette of India dated the 18th May, 1966, under section 41 of the Defence of India Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT-6490/66].

(ii) A copy of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Second Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 772 in Gazette of India dated the 18th May, 1966, under sub-section (2) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952. [Placed in Library. See No. LT-6491/66].

(iii) The High Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 943 in Gazette of India dated the 18th June, 1966, under sub-section (3) of section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954. [Placed in Library. See No. LT-6492/66].

(iv) A copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1952:—

(a) GSR 829 published in Gazette of India dated the 4th June, 1966 containing corrigendum to G.S.R. 194 published in Gazette of India dated the 5th February, 1966.

(b) The All India Services (Conduct) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. GSR 830 in Gazette of India dated the 4th June, 1966.

(c) GSR 891 published in Gazette of India dated the 11th June, 1966 containing corrigendum to GSR 1475 published in Gazette of India dated the 9th October, 1965.

(d) The Indian Police Service (Probation) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. GSR 945 in

Gazette of India dated the 18th June, 1966.

(e) GSR 976 published in Gazette of India dated the 25th June, 1966, making certain amendment to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(f) G.S.R. 1035 published in Gazette of India dated the 2nd July, 1966, making certain amendment to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(g) The Indian Police Service (Recruitment) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. GSR 1075 in Gazette of India dated the 9th July, 1966.

(h) The Indian Administrative Service (Recruitment) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1076 in Gazette of India dated the 9th July, 1966.

[Placed in Library. See No. LT-6493/66].

(v) A copy of the Delhi Municipal Corporation (Allowances of Councillors and Aldermen) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. 1/67/64-Delhi in Delhi Gazette dated the 25th May, 1966, under sub-section (2) of Section 479 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957. [Placed in Library. See No. LT-6494/66].

(vi) A copy of the Kerala High Court (Amendment) Act, 1966, (President's Act No. 6 of 1966) under sub-section (3) of section 3 of the Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1965. [Placed in Library. See No. LT-6495/66].

THE DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) RULES

Shri D. R. Chavan: Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (3) of section 40 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954:

- (1) The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Second Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1017 in Gazette of India dated the 2nd July, 1966.
- (2) The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) (First Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1081 in Gazette of India dated the 9th July, 1966.

[Placed in Library. See No. LT-6496/66].

AMENDMENTS TO KERALA INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL AND FESTIVAL HOLIDAYS) RULES ETC.

Shri D. R. Chavan: On behalf of Shri Shahnawaz Khan, I beg:

- (1) to re-lay on the Table a copy of Notification No. S.R.O. 72/66 published in Kerala Gazette dated the 22nd February, 1966, making certain amendment to the Kerala Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Rules, 1959, under sub-section (3) of section 12 of the Kerala Industrial Establishments (National and Festivals Holidays) Act, 1958 read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [Placed in Library. See No. LT-6280/66].

(2) to lay on the Table—

- (i) A copy each of the following Notifications under section 24 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963:

(a) The Personal Injuries (Compensation Insurance) Third Amendment Scheme, 1966, published in Notification No. S.O. 1583 in Gazette of India dated the 28th May, 1966.

(b) The Personal Injuries (Compensation Insurance) Third Amendment Rules, 1966, published in Notification No. S.O. 1584 in Gazette of India dated the 28th May, 1966.

[Placed in Library. See No. LT-6497/66].

- (ii) (a) A copy of the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1966, published in Notification No. G.S.R. 515 in Gazette of India dated the 9th April, 1966, under sub-section (7) of section 59 of the Mines Act, 1952.

(b) A statement showing the reasons for delay in laying the above Notification.

[Placed in Library. See No. LT-6498/66].

- (iii) A copy of the Annual Accounts of the Employees' Provident Fund Organisation along with the Audit Report thereon for the year 1963-64. [Placed in Library. See No. LT-6499/66].

(iv) A copy of Report of Enquiry on the fatal accident at Katras Choitodih Colliery, Dhanbad occurred on the 17th May, 1966. [Placed in Library. See No. LT-6500/66].

SEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER
FOR LINGUISTIC MINORITIES

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Seventh Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period 1st January to 31st December, 1964 (Hindi version). [Placed in Library. See No. LT-6501/66].

12.05 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINETIETH REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I present the Ninetieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.05 hrs.

PETITION

RE. ENQUIRY COMMISSION ON
MAHARASHTRA-MYSORE BOUNDARY QUESTION

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): I beg to present a petition signed by 63 petitioners regarding the proposed One Man Commission to enquire into the boundary question between Maharashtra and Mysore.

12.05½ hrs.

RE. RECENT RAILWAY ACCIDENTS

Mr. Speaker: Questions on the Statement regarding railway accidents. Are the members ready?

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): We should have a two-hour discussion on this. Mere questions will not satisfy us.

Mr. Speaker: I have received the notice. I have yet to see. If the mem-

bers want me to postpone it till I have taken a decision....

Shri Nambiar: That is better.

Mr. Speaker: If I decide that a discussion would be held for two hours, then I would not allow any questions.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : क्या उस वक्त प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर उसको नामन्जूर किया तो फिर और मिल जायेगा ।

12.05¾ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-EIGHTH REPORT

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): I move:

"That this House agrees with the Forty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 26th July, 1966."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Forty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 26th July, 1966."

The motion was adopted.

12.06 hrs.

COTTON FABRICS (ADDITIONAL
EXCISE DUTY) (REPEAL) BILL*

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2 dated 27th July, 1966.

Rao: On behalf of Shri Manubhai Shah I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the repeal of the Cotton Fabrics (Additional Excise Duty) Act, 1957.

Mr. Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the repeal of the Cotton Fabrics (Additional Excise Duty) Act, 1957.”

The motion was adopted.

Shri Jaganatha Rao: I introduce† the Bill.

12.07 hrs.

MOTION RE: PRESENT ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY—contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Sachindra Chaudhuri on on the 26th July, 1966, namely:—

“That the present economic situation in the country be taken into consideration.”

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): May I point out one thing? Yesterday when we were not here, you had suspended the rules and allowed an amendment to be introduced saying that there were precedents to that in the House. I have been a Member of all the three Parliaments and as far as I remember, on every occasion whenever we had allowed suspension of rules, it was accompanied by some reason: either the papers had not been given in time or for some other reason. The House may be told as to why you are suspending the rules.

Mr. Speaker: I might correct the hon. Member here that no rule was suspended nor was any suspension required.

Shrimati Renu Chakravartty: Do I take it that you have taken it in your discretion to allow the Government to move....

Mr. Speaker: That is in the rule itself.

Shrimati Renu Chakravartty: Normally you have never done it in the past.

Mr. Speaker: It has been done so many times.

Shrimati Renu Chakravartty: It has been done, but with an explanation. You have always explained to us as to why it was necessary. So we would like to know what was the reason that prompted you to do this.

Mr. Speaker: I have seen one case where Mr. Kamath requested me after the debate had begun. Mr. Kamath made a request that because it had to go on for two more days, even amendments that are brought after one day, should be allowed to be moved. And I had allowed that.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): May I submit to you in all humility that this is not on all fours with that because this amendment which was allowed yesterday is identical with an amendment given by a member who was not present in the House and which you therefore, rejected.

Mr. Speaker: This is not the same.

Shri Hari Vishnu Kamath: This is identical with that.

Shri Tyagi (Dehra Dun): When the motion is of the nature that a particular policy be considered, it is not possible for anybody to give an amendment in advance that it approves of it. The House should first know what the policy is. It is only when the

†Introduced with the recommendation of the President.

[Shri Tyagi]

House knows what the policy is that an amendment seeking approval can be tabled. Therefore, on any such motion, such amendments are permissible even at the late hour.

Shri Hari Vishnu Kamath: After the Tashkent Agreement, he is not himself.

Mr. Speaker: Does the hon. Prime Minister want to say anything?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indra Gandhi): Not on this. But I find that hon. Members opposite are raising some points....

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Yesterday, I had made a request to the House for creating conditions for the normal functioning and the normal carrying on of the business of the House. The Minister of Parliamentary Affairs and the Leader of the House has agreed that in future if there is a no-confidence motion, a substantial motion on policy matters will not be taken up and he has said that he will examine this question. At the end he had also said: "We shall see that such things do not recur in future." Even after that, we have continued the discussion on the economic situation. But some of our Members are not prepared to participate in it....

An hon. Member: Not some, but most of the Members.

Shri Surendranath Dwivedy: ..and they have boycotted this debate. The main demand is that this debate may be postponed and taken up after the no-confidence motion is disposed of; then, probably, those Members will not have any objection to participate in the discussion, and this important matter can be discussed with all sections of the House participating in the discussion.

Therefore, I would reiterate my appeal again, and request the Government, through you, Sir, to agree to this request. We have already debated this matter for a day. Now let us postpone it till the no-confidence motion is disposed of. Let us postpone it to a suitable day which Government and you, Sir, may decide later.

Shri Mohammed Koya (Kozhikode): It is a question of wits and counter-wits.

Shri Hari Vishnu Kamath: Wit and outwit.

Shrimati Indira Gandhi: It has been a well recognised and honoured principle of parliamentary democracy that important policy decisions taken during the period when Parliament is not in session should be put before Parliament on the very first day that Parliament assembles. It was in pursuance of this principle and its practice, and not to forestall the debate on the no-confidence motion that Government made their motion before the Lok Sabha.

श्री बागड़ी (हिसार): प्रधान मंत्री जी ने यह भी पढ़ना शुरू कर दिया।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, इसे यह लिख कर लाई है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे उस से कोई मतलब नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया: अभी एक सुझाव दिया गया। मैं खाली एक सवाल पूछ रहा हूँ.....

अध्यक्ष महोदय: अभी आप जरा बैठ जाय।

डा० राम मनोहर लोहिया: मेरा एक सवाल है कि द्विवेदी जी ने अपना सुझाव दिया तो वह इसे कैसे दे रहे हैं? मैं व्यक्त्या का प्रश्न उठा रहा हूँ। द्विवेदी जी ने सवाल उठाया तो क्या पहले से बातचीत हो चुकी थी?

श्री सोलंकी (करा) : जी हां, पहले से बातचीत हो चुकी थी ।

Shri Surendranath Dwivedy: So far as I am concerned, I did not know whether she had written it or not; I did not know what Government were going to decide.

अध्यक्ष महोदय : एक इधर से अपील आई है मैंने गवर्नमेंट का रिएक्शन पूछा है, बाकी कोई बात हुई है या नहीं हुई है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): We cannot allow this kind of command performance. It is reducing Parliament proceeding to a farce.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह लिख कर कहां से ले आई ? क्या इन को इल्लाम हुआ करता है अल्लाह मियां से ?

Shrimati Indira Gandhi: I am glad that Shri Surendranath Dwivedy has made an appeal, but actually we had come to this decision on our own. I did not know that he was going to speak about it this morning. As I was saying, we did not make our motion to forestall in any way the no-confidence motion.

Shrimati Renu Chakravarty: They have done it.

Shrimati Indira Gandhi: Government have always respected the Opposition and have tried to seek their co-operation. At the same time, Government cannot make a positive response to protests which take the shape of holding up the business of the House. But after the debate was resumed, we thought about the matter again. Government would now be prepared, should the Speaker and the House wish, to postpone the discussion on the Finance Minister's motion is after the no-confidence motion is debated and disposed of.

But I should like to take this opportunity to appeal to all sections of

the House to co-operate with the Chair in maintaining the highest traditions of democracy for which our Parliament has earned a reputation throughout its career.

श्री मधु लिमबे (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक भ्रज करना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

Shri Solanki: Now they have realised their mistake. They have been behaving like mad people so far and remained silent while the Chair stood insulted.

Shri Ranga (Chittoor): I am glad that wisdom has dawned on this Government even at such a late hour, and the Prime Minister now expresses the hope that all sections would cooperate with the Speaker. I should have thought that the Government should have thought many times before they chose to exercise their fullest possible rights and thus create all that embarrassment to the Speaker and to various sections in the House during those two days when we were going through that searing experience.

Ordinarily, it should have been understood by anyone who has any instinct for parliamentary democracy that a no-confidence motion should be given precedence. That should have been understood by them. Immediately they knew that that point would be pressed. Therefore, the Leader brought the whole House to such a level of tricks that he chose to lead you and us into a wrong path by Government themselves giving notice of a substantive motion. The gravamen of my charge is against the manner in which this House is being led, or rather misled, by this Government, and what is more, to being led into such a pass, where the Speaker himself is not only embarrassed but put into agony so much so that he was obliged to appeal to the House, on grounds of his own health, to obey him.

[Shri Ranga]

Who was responsible? True, all those friends who created that trouble, from which all of us dissociated ourselves, were also responsible. But more was the responsibility of this Government. They should have apologised to the House and to the Speaker. If they have not got that decency, I do not know when a sense of decency would descend upon them. I have nothing more to say.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) :
अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार किया जाय ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जरा
धन्यवाद के साथ एक जुमला कहना चाहता
हूँ.....

Mr. Speaker: I do not allow a debate on this.

Shrimati Renu Chakravartty: We are not asking for a debate.

Shri Surendranath Dwivedy: I formally move:

"That further debate on the Government motion regarding Economic Situation be adjourned."

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुन लीजिये । आपने रंगा साहब व अन्य लोगों की बात सुनी तो फिर आप हमें आखिर क्यों नहीं सुनते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या सुनूँ ? अब जाहिर है कि 500 माननीय सदस्यों को तो मैं नहीं सुन सकता हूँ ।

What does Shrimati Renu Chakravartty want to say?

Shrimati Renu Chakravartty: All that I would like to say is this that I am glad that the Government have at last seen sense, and better late than never, I would also say that whatever has happened in this House and we have really held up the debate—there is no doubt about it—I want to tell my hon. friends opposite that we normally

never take things to this pitch. But the reason for doing it was an extremely serious one. We tried to plead with Government again and again to realise that what they were doing was against the tents of parliamentary democracy, about which the Prime Minister spoke just now. (*Interruptions*). They talk about parliamentary democracy, but they do not want to hear about it.

Here were we trying to uphold a very healthy convention, and I am very glad that my hon. friend Shri Ranga has also agreed that in the circumstances in which devaluation has taken place behind the back of Parliament when a no-confidence motion was also outstanding, the Government should not have asked for a vote of confidence prior to the no-confidence motion being disposed of.

Anyway, I would plead with you further that you should re-examine rule 198. I know you have given your ruling that you are helpless in the matter, but I would request you once again to see that we by our rules have given you overriding powers in this particular clause on the question of no-confidence motion, to advise Government, as you have always advised us, on keeping parliamentary decorum to consider the importance of the no-confidence motion. Therefore, on both these points I would say that if we had been able to use the powers and the intelligence which we should have brought to bear on this matter, much of the unfortunate scenes that took place could have been avoided and I hope that in future we shall be able to avoid it with the co-operation, willing co-operation, of the ruling party who have got such a huge majority.

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सही कहना है कि जो भी हल्ला पिछले दो दिनों से यहाँ हो रहा है उसके लिए मेरी पार्टी भी तैयार नहीं थी । लेकिन जब

हम ने देखा कि डिमाक्रेसी के खिलाफ बात यहाँ हो रही है और पार्लियामेन्ट से अधिकार मांगे जा रहे हैं तब हम बोलें। आप ने कहा कि आप का अपमान हुआ। लेकिन इस सम्बन्ध में जो आप का अपमान हुआ और जो हल्ला यहाँ पर हुआ इस की जवाबदेही शासन पर है। पले अगर इस बात को लीडर आफ दि हाउस मान लें तो इतना हल्ला यहाँ पर न होता। लेकिन देर आयद दुस्त आयद। आज ही सही। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हल्ला हुआ और जो आप का अपमान हुआ है उस की जिम्मेदारी शासन पर होते हुए भी माफी उसने नहीं मांगी है। फिर भी मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ हुआ उस में फारगेट और फारगिव की भावना से काम करना चाहिए।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): The acceptance of the suggestion which I made day before yesterday is very welcome, but it is all the same surprising that this suggestion should have been accepted after all this indecision and vacillation lasting for nearly two days and contributing to all that happened in this House, all the unpleasantness that was generated in the House. This seems to be a case really of psychopathological schizophrenia. I besought the Minister of Parliamentary Affairs and the Prime Minister to accept it.

Mr. Speaker: Why go into this?

Dr. L. M. Singhvi: How is it that such a decision was delayed so long? Yesterday Mr. Chatterjee requested the Government to reconsider the whole matter. Does it take all this time to come to a positive decision like this?

Shri Hem Barua (Gauhati): It seems the Prime Minister has very generously accepted the suggestion made by the Opposition. She has done it very gracefully. My submission is that all these Members on whom the suspension order....

Mr. Speaker: That is a separate thing. This must be finished.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, कोई काम चाहे वह कम अच्छा हो, चाहे पूरा अच्छा हो, चाहे देर से हो चाहे समय पर हो और चाहे खाली सतह पर हो, अगर अच्छा हो तो मैं उसे स्वीकारता हूँ और आज प्रधान मंत्री जी को थोड़ा सा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस के साथ साथ जब वह सदन की शोभा की बात करती हैं तब उन को एक सलाह देना चाहता हूँ। आज देश में दो औरतें हैं, एक दिल्ली वाली और एक लखनऊ वाली। इन दोनों... (व्यवधान)। ... अभी मेरा वाक्य तो पूरा होने दो...

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, अगर आप को कोई सलाह देनी हो तो वैसे ही दीजिये तब ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि आप हाउस में दें।

डा० राम मनोहर लोहिया : वैसे वह मुझे कहां मौका देगी। इसी लिये मैं आप के जरिये सलाह देना चाहता हूँ। जब वह शोभा की बात कह रही हैं, तब हिन्दुस्तान में दो औरतें हैं... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उन्हें बाहर निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से नहीं बोल सकते। डाक्टर साहब, जो एटमास्फियर पैदा हो रहा है उसमें ऐसी बात न उठाइये।... (व्यवधान)। आप बैठ जायें।

डा० राम मनोहर लोहिया : : आप मुझ को अपना वाक्य तो पूरा करने दें। अगर किसी चीज से उन को एतराज है....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें और मुझे सुन लें

Shri Raghunath Singh (Varanasi)
He should not be allowed.

अध्यक्ष महोदय : यह मौका ऐसा नहीं है कि हम यू० पी० के चीफ मिनिस्टर को यहां लायें। अब आप ऐसा ऐटमास्फियर पैदा होने दें जो हो रहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक जहरी चीज है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप लोग शोर मचाना चाहते हैं

श्री मधु लिमये : मैं आप से पूछना चाहता हूँ। आखिर आप विरोधी दल को ही क्यों बार बार कहते हैं? यह कांग्रेसी हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप उन को नहीं रोक रहे हैं। . . . (व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह : उन्होंने "दो औरतें" शब्दों का जो प्रयोग किया है वह बहुत खराब है। . . (व्यवधान) . . . वह हिन्दी जानते हैं, हिन्दी के पंडित बनते हैं, फिर भी "दो औरतें" कह रहे हैं, एक लखनऊ वाली और एक दिल्ली वाली। इस का अर्थ हम समझते हैं। उन में कुछ फर्कसी होनी चाहिए। चाहे श्रीमती कहें या महिला कहें।

डा० राम मनोहर लोहिया : दिल्ली के अन्दर रहने वाली औरत में क्या बात है। मुझे हिन्दी सिखाने चले हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का अफसोस है

श्री म० प्र० मिश्र (बेगूसराय) : वह बाजारू भाषा बोल रहे हैं।

श्री रामसेवक श्रावण (बाराबंकी) : क्या बाजारू भाषा है। आप सीखिये पढ़ें। बैठ जाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : अपनी मां, बहन, बेटियां क्या औरतें नहीं होती हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आता। महल में रहने वाली महिला को पसन्द करते हो। कैसा पागलपन!

Shri Raghunath Singh: There is the Prime Minister here.

Shri Kandappan (Tiruchengode): Let all these Members better speak in English to avoid all this confusion.

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० लोहिया से कहना चाहता हूँ, और बड़े दुःख से, कि इन सब चीजों के बाद बाकी सब चीजें तो शायद रिकवर हो जायेंगी लेकिन स्पीकर की प्रेस्टिज का जो डैमेज हुआ है वह रिकवर नहीं हो सकता।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या हो गया, बतलाइये साहब।

अध्यक्ष महोदय : वही हो गया जो आप कर रहे हैं। जो कुछ बात पिछले तीन दिनों में होती रही है उसे आप भी सुनते रहे हैं और मैं भी सुनता रहा हूँ। उस को आप मद्सूस नहीं करते, यही तो हो गया है। . . (व्यवधान) . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या आप मेरा वाक्य भी पूरा नहीं होने देंगे। उस को पूरा होने दीजिये। अगर यहां पर औरतें शब्द पर ऐतराज है तो मैं महिलायें कह देता हूँ। जो दिल्ली वाली महिला है उस ने फैसला कर रक्खा है . . (व्यवधान) . . . क्या वाहि-यात बात कर रहे हो। क्या इसी लिये आये हो लोक सभा में। मुझे अपनी वाक्य तो पूरा करने दो। मुझे इतनी अपेक्षा थी कि वह देश की राजनीति में कसणा और दया के पुट को इस्तेमाल करेगी, लेकिन मालूम होता है कि उन्होंने फैसला कर रक्खा है कि

वह साबित करेगी देश में कि वह मर्द से भी ज्यादा मर्द है। इसलिये अगर वह इस लोक सभा की शोभा को बढ़ाना चाहती है तो आज यहां पर संकल्प करें कि इस देश की राजनीति में इतनी गोली, इतनी लाठी, इतनी सारी मनमानी उच्छृंखलता खत्म हो कर एक दूसरी चीज कहना आयेगी। इतना ही मुझे कहना है।

Mr. Speaker: The proposal before the House is that further discussion on this be adjourned. Yesterday we had already taken a decision on the motion of Shrimati Renu Chakravartty. So, Rule 338 should be suspended.

Shri Hari Vishnu Kamath: Rule 340 has to be suspended for that.

Mr. Speaker: No, it is Rule 338.

Shri Surendranath Dwivedy: Sir, I beg to move:

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for adjournment of further debate on the Government motion regarding economic situation be suspended."

Mr. Speaker: The question is:

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for adjournment of further debate on the Government motion regarding economic situation be suspended."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: Now I will put the substantive motion of Mr. Dwivedy to the House. The question is:

"That further debate on the Government motion regarding economic situation be adjourned."

The motion was adopted.

12.32 hrs.

RE: REVOCATION OF SUSPENSION OF MEMBERS

श्री मधु लिमये (मुंजर) : अब जब कि इन नियमों को स्थगित कर दिया गया है, मैं आपकी मार्फत प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि जिन लोगों को निकाला गया है उनको वापिस बुला लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह अलहदा सवाल है।

Shri Hema Barua (Gauhati): May I repeat that since the situation has improved....

Mr. Speaker: He may give it in writing and I will put it to the House.

श्री बागड़ी (हिसार) : श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का क्या हुआ है, अध्यक्ष महोदय ?

12.33 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER (Shri Khadilkar)

Mr. Speaker: Mr. Khadilkar wants to give a personal explanation. He has given me advance notice and I have permitted him.

Shri Khadilkar (Khed): Yesterday, while speaking after Mr. Masani, I made some reference to the statements made by Mr. Masani and they were challenged. I had said that if they are found to be incorrect or certain modifications are called for, I will make those modifications on the floor of the House. Yesterday I said:

"He had advised publicly our creditors in America—American creditors—not to advance a cent to India unless Indian Government toes a particular economic line."

I had quoted from memory what I had said during the debate on the no-confidence motion last August.

[Shri Khadilkar]

I will read one more sentence from my yesterday's speech. I said:

"I ask whether it is open to the Member of this Parliament to advise the foreign Government which happens to be the creditor...."

In this connection, the actual statement of Mr. Masani which I quoted then and which was not contradicted runs like this: This is from his speech which was reproduced in the *March of the Nation*, a Bombay paper then—I do not know whether it is published now. He had said that:

"We are going bankrupt, that TTK is going to lead this country to bankruptcy...."

It has no relevance here. The next is important. I said that he has advised other countries this way:

"He welcomed the West German Government's recent decision not to give any more government loans to India and other developing countries except for the legitimate purpose of building roads, bridges, dams and power stations. For everything else, those who wanted capital must go to the money market and raise foreign equity capital".

There is one more sentence which is more important. It is:

"Mr. Masani hoped the US Government would also impose similar economic discipline on the Indian Government by withholding further economic aid unless inflationary policies were abandoned, the proposed Fourth Plan was scrapped, the bias towards heavy industry eliminated and agriculture given the priority that it badly needed."

This is the quotation. Except for one word it is substantially correct. I have used here: "He has appealed to the Government" and at one place: "He advised." Instead of that it

should be: "He hoped." That is a minor correction in what I said yesterday, and I am making it here now.

12.37 hrs.

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

Mr. Speaker: We shall now take up the Merchant Shipping (Amendment) Bill. I might inform the House that we have on the Agenda only two Bills. If they are finished earlier, we will have to take up the Calling Attention Notice.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): When will the No-confidence Motion come up?

Mr. Speaker: He might settle it with the Leader.

Shri Hari Vishnu Kamath: Major Bills should not be moved before that is disposed of (*Interruption*).

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.."

While moving the motion for consideration, I beg to submit that the Merchant Shipping Act, 1958, prescribes certain minimum standards which Merchant ships should comply with in the interest of safety of life and property at sea. These provisions are based on the International Convention or the Saety of Life at Sea, 1948, which was ratified by India in 1954. This Convention requires cargo ships of 1600 tons gross to have radio telegraphy installation on board the ship. Both cargo and passenger ships are also required to maintain certain life saving and fire fighting appliances which should be open to inspection by the concerned Government authorities. Passenger vessels are required further to comply with additional measures relating to structural safety, stability, safety of navigation, etc.

The 1948 Convention was considered at the 4th International Conference on Safety of Life at Sea in London in 1960 under the aegis of Inter-governmental Maritime Consultative Organisation, one of the specialised agencies of the United Nations. The working of the 1948 Convention was reviewed and it was modified in the light of the experience gained and it was decided to replace the Old Convention by a new Convention of 1960. The provisions of the new Convention would necessitate a number of amendments to the Merchant Shipping Act. As the Indian ships were facing difficulties in having their Safety Convention Certificates renewed in the countries which have accepted the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, India has deposited the instrument of acceptance of the above Convention with effect from the 28th February, 1966, after consultation with the Ministry of Law. The Convention will come into force for India with effect from the 28th May, 1966, three months after the date of acceptance.

But, as stated earlier, it is necessary to amend the Merchant Shipping Act to provide for the various changes brought about by the Convention of 1960. The present Bill has been introduced to effect these amendments.

Some of the more important requirements of the 1960 Convention are briefly as follows:—

(1) Under the 1960 Convention, the scope of survey of cargo ships has been extended to cover the survey of hull, machinery and other equipment of cargo ships. Further, all cargo ships of over 500 tons gross will be required to carry in addition to the existing certificates a safety construction certificate issued by or under the authority of a contracting Government. It is, therefore, necessary to make suitable provisions in the Act for survey of cargo ships and

for the issue of safety construction certificates to cargo ships.

(2) In contrast to the 1948 Convention, the 1960 Convention requires that every ship must carry on board sufficient data to enable the master, by rapid and simple processes, to obtain accurate guidance as to the stability of a ship under varying conditions of service.

(3) The most important deviation made by the 1960 Convention in regard to life-saving appliances relates to the removal of the restriction imposed by the 1948 Convention on the use of inflatable and other rafts which depend on air for their buoyancy. Inflatable life-rafts as well as rigid life-rafts as an alternative are now acceptable, provided these comply with certain conditions.

(4) Under the 1948 Convention, cargo ships below 500 tons gross were not required to be fitted with radio installations but under the 1960 Convention even cargo ships of less than 500 but not less than 300 tons gross are required to be fitted with such installations.

(5) The 1960 Convention contains a number of new requirements relating to the carriage of grain in ships. Emphasis is laid on the need for giving trimming and on the fundamental importance of preserving the stability of the ship. Duly approved grain-loading plans are required to be carried on board by ships carrying grain and such plans are required to be accepted by the other contracting Governments as evidence of compliance with the requirements of the Convention.

(6) The 1960 Convention contains a number of new regulations relating to the classification, packing, labelling, documentation and stowage of dangerous goods on board ships.

(7) The 1948 Convention does not contain any special provisions relating to nuclear ships. Having regard to the new problems in the

[Shri C. M. Poonacha]

field of safety owing to the advent of nuclear power as one of the means of propulsion for merchant ships, it is necessary to have special provisions relating to nuclear ships. The 1960 Convention contains a special Chapter for this purpose. A number of requirements are provided for in this Chapter for the purpose of ensuring that nuclear ships do not become a source of danger to life, not only at sea but also at ports and other places and that such ships do not become a source of contamination of food and water resources.

This Bill was introduced in Rajya Sabha on 7-4-66 and it was passed by the Rajya Sabha. But, due to some other pressing work, this august House was not able to find time to spare for the passing of this Bill during the last session. As the measure had to be brought into force under the International Convention three months after the date of acceptance, we had to issue an Ordinance to bring it into force.

Shri Hari Vishnu Kamath: The House could have sat a day longer and passed it.

Shri C. M. Poonacha: The last session was extended by three days and I was here till the last minute. Still, I could not get the time. As such, this Bill could not be brought before this House, because the time at the disposal of the House was taken away by other more important and pressing work.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, I rise on a point of order. I am not speaking on the Bill but on this misrepresentation. The House was willing to sit but the Government did not want to sit. Because of that they had to pass an Ordinance.

Shri C. M. Poonacha: Therefore, we were forced to bring the measure into force through the Ordinance-making power, and an Ordinance has been

duly issued. With these words I move that the Bill may be taken into consideration.

Mr. Speaker: As no hon. Member wants to speak on this Bill, I will straightway put it to the vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: We will now take up clause by clause consideration.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): We have not got copies of the Bill.

Mr. Speaker: I am not to be blamed for that.

Shri U. M. Trivedi: In the agenda it was mentioned that some other item was going to come up for discussion for today and tomorrow. Now this item has come without notice.

Mr. Speaker: But it was in the agenda.

Shri U. M. Trivedi: According to the agenda it was to come up only after the earlier item was over.

Mr. Speaker: It is always possible that the earlier item is disposed of soon, earlier than expected.

Shri U. M. Trivedi: We must be given time to prepare ourselves. Sir, you are a lawyer and you must understand this thing.

Mr. Speaker: Sometimes lawyers do not understand things. It is just possible.

Shri U. M. Trivedi: If you do not understand, it does not mean that I should not understand it. You can forget it; but I cannot forget it.

Mr. Speaker: I am not blaming him. I am blaming myself. Every lawyer might not have the same comprehension. I am not blaming him.

Shri U. M. Trivedi: In any case, let copies of the Bill be supplied to us.

Mr. Speaker: It has been in the agenda for the last so many days.

Shri U. M. Trivedi: But it was to have come up after the consideration of the motion.

Mr. Speaker: Now that we have no other work on hand, it is taken up.

Shri U. M. Trivedi: How can one speak or take part in the debate without seeing the Bill?

Mr. Speaker: What can I do? It is on the agenda for the last two or three days.

Shri U. M. Trivedi: I am not finding fault with you. But I want to plead with you one thing. The question is this. Every day we bring with us here only such papers and Bills as are likely to be taken up that day. We do not bring all the paraphernalia, all the papers and copies of Bills that are supplied to us. Because we have not brought the papers relating to this particular Bill today, we are not able to participate in this debate. I do not think we should be deprived of that opportunity.

Mr. Speaker: Copies of the Bill have been circulated to Members. This Bill has been on the agenda for the last two days as well. There is always the possibility of the previous item collapsing.

Shri U. M. Trivedi: We never expected that.

Mr. Speaker: A motion for adjournment of the debate can be moved at any time.

Shri U. M. Trivedi: A motion on the same point was lost yesterday. How could we anticipate that it will be taken up and adopted today?

Mr. Speaker: I am sorry, I cannot help it. Now, the question is:

"That clauses 2 to 39 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 39 were added to the Bill.

Mr. Speaker: There are two amendments by Government. Amendment No. 2 is for insertion of new clauses.

Shri C. M. Poonacha: Sir, I beg to move:

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order, Sir. I invite your attention to rule 76. You had already rebuked the Treasury Benches once on an earlier occasion but they have not learnt a lesson and they seem to be incorrigible. Rule 76 says:—

"No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member in charge of the Bill".

Then, there is a proviso which reads:—

"Provided that if the member in charge of a Bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker."

On the previous occasion also you had rebuked a senior Minister, because without stating reasons somebody else came, got up and started moving that the Bill be taken into consideration. It is very unfair to the House and to you; it is contempt of the House and of yourself also. They do not learn a lesson. Why do they not give reasons why Shri Sanjiva Reddy is absent today? Let them give the reasons.

Mr. Speaker: It is appropriate that in the beginning some statement should be made in order to satisfy the House that such has been the case and the Minister has not been able to

[Mr. Speaker]

come. But the word "minister" includes other ministers also. Therefore there is no bar and he could take it up. But in the beginning he ought to have made the statement that the minister in charge could not come to take up and move the motion, and therefore he is moving it. Then there would not have been any objection.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let him state the reasons now before he proceeds further.

Mr. Speaker: Not now when I have allowed it and the motion has been moved. It will be taken care of in future.

Shri Hari Vishnu Kamath: Your allowing also is not in order, I am sorry to say. Why should you give such easy, facile approval to these ministers? It whets their appetite, and the appetite grows by what it feeds on. It makes matters worse.

Clauses 40 and 41 (New).

Amendment made:

Page 23,—

after line 8, insert—

"[Certain contraventions etc. not to be offences.]

40. Notwithstanding the retrospective operation of this Act, no contravention of, or no failure to comply with, any of the provisions of the principal Act, as amended by this Act, shall render any person guilty of any offence if such contravention or failure—

(i) relates either to any provision inserted in the principal Act by this Act, or to any existing provision thereof as amended by this Act, and

(ii) occurred on or after the 28th day of May, 1966 and before the 6th day of June, 1966.

[*Repeal and saving.*]

41. (1) The Merchant Shipping (Amendment) Ordinance, 1966 (No. 3 of 1966) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act." (2)

(*Shri C. M. Poonacha*)

Mr. Speaker: The question is:

"That clauses 40 and 41 be added to the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 40 and 41 were added to the Bill.

Clause 1.— (*Short title and commencement.*)

Amendment made:

Page 1,—

for lines 5 and 6, substitute—

"(2) It shall be deemed to have come into force on the 28th day of May, 1966." (1)

(*Shri C. M. Poonacha*)

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri C. M. Poonacha: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

12.55 hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, be taken into consideration."

12.56 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Sir, the Electricity (Supply) Act of 1948 was passed with a view to developing electricity in this country. In 1951 electricity was only under six thousand million kilowatt hours; today, it is 36 thousand million kilowatt hours; that is, electricity has multiplied very greatly. Therefore, it is very necessary for us, from the experience that we have had in these years, to introduce some amendments in the interest of better performance under this Act.

This Act serves two purposes. One is to render more efficiently the services rendered by the State Electricity Boards and the other is about private licences. There are a few amendments which have been suggested, of which I shall mention only the most important for the hon. House.

In regard to the State Electricity Boards the most important amendment is in respect of the uniformity of rates. The hon. House has unanimously been stressing that the rates for electricity must be the same all over India for any particular type of load. The Ministry has always submitted that while it is our ideal object to achieve, it will not be possible to do so because we have not got an all-India grid and that we shall try to get the uniformity of rates for the same type of load at least in each State.

Accordingly, we gave advice to the various State Electricity Boards to in-

roduce uniformity of rates in their respective areas and most of the States have done that. But, unfortunately, under the present Act this does not seem to be legal; the present Act does not seem to permit it. A municipality of Maharashtra has filed a suit against the Maharashtra Board that the rates cannot be fixed on a uniform basis and that the rates for a concentrated area like the towns should not be fixed in such a way as to finance the rural areas. The High Court has also said that the present Act is defective and they allowed what that particular municipality wanted. Now the Maharashtra Board had to appeal to the Supreme Court.

Similarly, there have been some cases also brought out in the States of Bihar and Punjab. All these complaints are happening because our Act is defective. Therefore, one of the amendments that we are suggesting is to ensure that the Government and the State Electricity Boards can introduce uniform electricity rates whenever it is possible and desirable to introduce them. That is the most important amendment actually that we are introducing in respect of the State Electricity Boards.

Then, we have taken this opportunity to introduce some more desirable changes. For example, Members of Parliament and members of Panchayat Boards or local authorities cannot be members of the State Electricity Boards for a period of twelve months from the date on which they cease to be such members. We thought that it was too long a period and it is really not necessary. As soon as a member ceases to be a Member of Parliament he can be taken into the Electricity Board. Therefore we have said that this limitation of twelve months is not necessary and it can be reduced.

Then, in order to have some amount of reserve and to be able to finance electricity development, we had said that every year there shall be a contribution of half a per cent. of the fixed assets to the general reserve up

[Dr. K. L. Rao]

to a maximum of 8 per cent. Now we are raising that limit of 8 per cent to 15 per cent. so that we can accumulate more amount of money and we will be able to take up the developmental projects and projects of electricity extensions by self-financing them out of the reserves as much as possible.

The amendment about depreciation is a matter of smaller detail. There has been depreciation of this machinery on a very complex formula. We have now reduced it to a straightline method of depreciation, which will take up more of depreciation in the earlier period. That is really the correct way of doing things.

Coming to limitation, electricity was under the management of Government before, and under the Act the Government could recover money due from a consumer for a period of 60 years. When money is due from a particular consumer, Government can file a suit even for a period of 60 years. Under the Limitations Act, unfortunately, when this amount was transferred to the State Electricity Board, the limitation period was only three years, with the result that the sums of money due to the State Electricity Board, earlier due to the Government, could not be recovered because the period of three years was already over by the time the Electricity Board, in some cases, took over the charge. Therefore, we are introducing an amendment in the Act that the three-year period will be from now so that they can recover their dues.

13.00 hrs.

Under the present Act, we have got the provision for publication of schemes. It is done twice, once at the draft stage and the other when the project has been sanctioned irrespective of the cost of the project, whether it is a small one or a big one. What we are trying to do is to ensure that for projects costing Rs. 25 lakhs there is no necessity of any publication, that for projects

costing Rs. 25 lakhs to Rs. 1 crore the publication need be done only after the project is sanctioned, and that only for projects costing more than Rs. 1 crore the publication need be done twice. These are some of the provisions we are trying to introduce in the Act in order to improve the efficiency of the State Electricity Board.

Similarly, with respect to licensees, there are 214 licensees in this country. They have an investment of Rs. 120 crores. They have got an installed capacity of 1½ million KW. At the moment, quite an appreciable amount of power is being generated and supplied by these private licensees. It is, of course, the aim of the Government to see that these licensees are gradually taken over when our finances permit so that the electricity may be controlled by a public undertaking. But that will take some time because the question of finance is involved in this. Except in the States of Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir and Orissa, there are private licensees all over the country. It is, therefore, necessary for us to ensure that these electricity undertakings are run on an efficient style and that they render a proper service to the consumer without, at the same time, making any extra profits or extra charges.

With this end in view, we have introduced a few amendments. The first and the most important is in respect of the standard rate, that is, the rate which they can charge is dependent upon what we call the standard rate which has got to be taken on the fixed assets, and that it shall not exceed the standard rate. The standard rate has been defined in the original Act as the bank rate plus 2 per cent. There has been a change in the bank rate. Now we want to ensure that this increased bank rate shall not apply to the entire amount. There is a large amount of money which has already been invited, prior to 1965, and we have provided that it has to earn only at 7 per cent and that the increased bank rate will

apply to amounts, which will be invested, hereafter. That is to say, we do not want to allow the private licensees to earn 8 per cent return on the whole amount with retrospective effect. We want to safeguard this.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On a point of order, Sir. I am sure you will agree that the Minister moving this Electricity (Supply) Amendment Bill has not so far succeeded in electrifying the atmosphere here. Let us have quorum for a change. That might help him.

Mr. Deputy-Speaker: Quorum has been challenged. The bell is being rung. . . . Now there is quorum.

Dr. K. L. Rao: Then, there is one other amendment. There is a certain amount of clear profit that they get every year. We have provided that it shall not exceed a reasonable return by more than 15 per cent, that is, the rate is so adjusted that the clear profit shall not exceed 15 per cent. Now we are raising it to 20 per cent, but it has been ensured that out of that, one-third only upto the maximum of 5 per cent goes to the licensee, that one-third goes as a rebate to the consumer and one-third is kept as a reserve. By increasing 15 per cent to 20 per cent, we are not benefiting the licensee at all. We are only giving the benefit, if any, to the consumer and there will be a reserve fund.

Then, there is another minor amendment. Wherever we supply electricity, we allow the State Electricity Board to charge a certain minimum whenever they give a connection to ensure that the amount invested by them is not wasted and that the man to whom the connection is given does take the power and does pay for it. That kind of minimum charge is not provided for the private licensees. The licensees have been pressing that there should be a minimum charge provided for them. That is what we are trying

to do. An amendment has been introduced here to the effect that minimum charges as approved by the State Government may be allowed for the licensees.

I have described in brief the important amendments made. I submit that this amending Bill may be taken into consideration by the House. Sir, I move.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948 be taken into consideration.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): I move that this Bill may be referred to the Select Committee. This is an important Bill.

Mr. Deputy-Speaker: There is no such amendment tabled.

Shri Nambiar: This has come up all of a sudden. I could not give notice of this.

Mr. Deputy-Speaker: This Bill has been on the agenda for the last two days.

Shri Nambiar: The coming up of this Bill today was not known to us. It was not anticipated at all that this Bill would come up today. You may kindly waive the rule.

Shri Hari Vishnu Kamath: You can waive it at your discretion.

Shri Warior (Trichur): It takes time to get ready for the Bill. All of a sudden, this has happened. Nobody could anticipate it at all.

Shri C. K. Bhattacharyya (Rai-ganj): The Bill has been on the Order Paper for the last two days.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): That is no argument. I know that has been on the agenda for the last two days.

Shri N. Dandekar (Gonda): Sir, this Bill is one in the discussion of

[Shri N. Dandekar]

which I definitely intended to participate. Naturally, everybody, including the hon. Members in this House, makes calculations about the time required for a particular item of business to be reached and all sorts of things depend on this. It is perfectly clear that until this morning there was no question at all of the Electricity (Supply) Amendment Bill coming up today. Certainly, I am not prepared for it and I do not think anybody else would be prepared for the Bill. Indeed, I did not think it would come up during the whole of this week having regard to the time allotted for the other business. I do not, therefore, think it will be really proper to proceed with this Bill today when so many Members are interested in it and certainly I am very much interested in the Bill. But none of us are prepared to debate it today. It is not adequate to say that because this other debate has collapsed,—the government has collapsed,—we have to take the consequence of that kind of collapse. I am sorry to use somewhat strong language, but I do feel very strongly about it. I hope, Sir, you will agree that the earliest this Bill may be taken up would be tomorrow.

Shri Warior: We are all very much interested in this Bill. In the last session I had put in so many questions (*Interruptions*).

Shri Nambiar rose—

Shri Hari Vishnu Kamath: I support Mr. Dandekar and I move.... (*Interruptions*)

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Nambiar, please give the names also.

Shri U. M. Trivedi: This Bill should not be taken up like this. We all calculated the time. We may be told that the agenda was there; the agenda has been there since 1965. The same

trouble arose when the Merchant Shipping Bill came up and there was nobody even to say 'yes' or 'no'. Even without a proper quorum, the Merchant Shipping Bill was passed. Now the Electricity Bill has come. Mr. Kamath moved a motion that the House has to be electrified—that there was no quorum. Now the quorum is there. We feel that this is a very important Bill. We generally apply our mind to the Bill when the business comes up before the House. This has come up all of a sudden. I was in the Railway Reservation office and I was told that the resistance of the Government had broken down and the Government had yielded and, therefore, the whole picture has changed. So from there I have come here straight. As I said, the Merchant Shipping Bill was passed even without a quorum. Now the Electricity Bill has come. This is a very important Bill. Many important points are involved in it: the question of Articles 14 and 15 is there; the application of the equality before law is there; then you want to make the provisions with retrospective effect. So many things are there. How are we to speak on this Bill? It is not a casual bill that can be taken up like this.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): My humble submission is that, in the extraordinary circumstances in which we have to operate today, there seems to be no other reasonable proposition than adjourning the House for the day. You cannot possibly have such a serious piece of legislation enacted without any consideration. If the Government wants merely to bring forward a piece of legislation and wants to have it passed without even being scrutinised properly by the House, then all the necessary incidents of democratic legislation are lost. This is a situation not of our making. This is a situation which is of the making of the Government because of the foolhardy and intransigent attitude taken by it. What can we do?

Shri Hari Vishnu Kamath: I move:

"That, under Rule 340, the debate on the motion be adjourned."

Mr. Deputy-Speaker: The time of the House is very valuable. (*Interruptions*).

Shri U. M. Trivedi: It is valuable for us also.

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): We can have this Bill as the first item tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: Is that the sense of the House?

Several hon. Members: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: All right. The Bill will be taken up tomorrow as the first item.

13.15 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as further discussion on the Motion of the Finance Minister regarding Economic Situation has been postponed, it has become essential to include some additional legislative items in the programme of the Lok Sabha for the current week. I would, therefore, like to inform the House that we propose to bring up before the House the following business for tomorrow and day-after. Of course, the first item will be consideration and passing of the Electricity (Supply) Amendment Bill.

(2) Consideration and passing of the Coal Mines Labour Welfare Fund Bill, 1965.

(3) Consideration and passing of the Delhi High Court Bill, 1965, as reported by the Select Committee.

(4) Consideration and passing of the Companies (Second Amendment) Bill, 1965.

(5) Consideration and passing of the All India Services (Amendment) Bill, 1965.

(6) Consideration and passing of Registration of Births and Deaths Bill, as passed by the Rajya Sabha.

(7) Consideration and passing of Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1966.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Arising out of this, may I at the outset say how concerned I was to notice that voice of the Leader of the House is noticeably subdued and contrite. I do not know why it is so.

He has given us a list of the business for the current week. May I remind him of the fact that on the last day of the last session there were at least three or four items which were on the agenda and which could not be taken up at all—the Rules Committee's report and one or two other motions. Does he want to put them off to the last day of this session also, so that they may automatically get postponed to the next session? So let him keep these in mind and bring these up early in this session.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में कि हिन्दू यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल जो पिछले दिनों कई बार पोस्टपोन हुआ है उसको अगले सप्ताह में ले लिया जाये क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी का कारोबार खत्म हो रहा है।

Shri Satya Narayan Sinha: We are going to take it up during this session.

Mr. Deputy-Speaker: There is a Calling-Attention Notice.

13.18 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DECISION OF GOVERNMENT TO APPOINT SHRI S. BHOOTHALINGAM AS AMBASSADOR TO E.E.C. AT BRUSSELS

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The reported decision of the Government to appoint Shri S. Bhoothalingam as Ambassador to E.E.C. at Brussels in spite of the adverse remarks against him by the Public Accounts Committee in its Fiftieth Report."

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): I may make a statement here that so far as Shri Bhoothalingam's appointment is concerned, that appointment was made before the Fiftieth Report of the Public Accounts Committee. So far as his posting is concerned, the posting has not been made now. The Government has sent its reply to the Public Accounts Committee. The Public Accounts Committee has not yet made its comments on that and, therefore, there is no question of any posting being made until that report is laid before the House.

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether the Government is in the knowledge of the fact that apart from the serious findings of the P.A.C. against this officer, the Special Police Establishment has also enquired into the conduct of Mr. and Mrs. Bhoothalingam; that Mrs. Bhoothalingam purchased shares of certain companies on the eve of the announcement of the Budget when Mr. Bhoothalingam was the Finance Secretary and when the Budget was out the shares went up and they were sold at higher prices by Mrs. Bhoothalingam. May I know

whether the S.P.E. has inquired into this matter or not?

Shri Sachindra Chaudhuri: A similar suggestion was made in the other House half an hour ago. Before that I did not know anything about it. I shall certainly look into this matter.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालन्दा) : क्या यह सच है कि एस० पी० ई० ने इस मामले के सम्बन्ध में थोड़ी छान बीन की थी लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से इस जांच को रोक दिया गया था? यदि यह सच है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जांच किस स्तर पर रोक दी गई और किसके कहने से रोक दी गई और अभी स्थिति क्या है और क्या गवर्नमेंट इस पूरे मामले की जांच करवाना चाहती है? पी० ए० सी० की पचासवीं रिपोर्ट आने के बाद श्री बूथलिंगम के बारे में जो बातें प्रकाश में आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कोई कमीशन बनायेगी या उच्च स्तर पर इसकी कोई जांच करवाएगी? यदि हां तो कब तक और क्या उस जांच की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी?

Shri Sachindra Chaudhuri: Before I can give any assurance to this House that there will be an inquiry, I must know what the facts are. I have just said in answer to my hon. friend Shri Bhagwat Jha Azad that certain suggestions have been made about this officer and I shall have to look into them and then make up my mind as to what should be done.

So far as the suggestion of the Public Accounts Committee is concerned, Government have made their observations on that, and we are awaiting what the Public Accounts Committee says about it.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): The question was whether the inquiry that was being proceeded with had been suspended.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister has already given the answer.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जवाब आना चाहिये । वह नहीं आया है ।

Mr. Deputy-Speaker: He has already given the answer. He has said that he will look into the papers and then decide.

Shri Umanath (Pudukkottai): He has not said anything about the suspension of the inquiry.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने पूछा था कि एस० पी० ई० ने जो इनक्वायरी शुरू की थी, वह इनक्वायरी सस्पेंड की गई या नहीं की गई और अगर की गई तो किस लेवल पर और क्यों और अभी एस० पी० ई० की इनक्वायरी की स्थिति क्या है ?

Shri Sachindra Chaudhuri: As I have said, I came to know about it only half an hour ago, and therefore, I cannot give an answer. I shall look into it. Apart from that, I do not want to be technical in this matter, but this question does not really arise out of the calling-attention-notice.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : पी० ए० सी० की रिपोर्ट आने के बाद क्या श्री बूथलिंगम ने सरकार के पास अपना कोई एक्सप्लेनेशन भेजा है ? अगर भेजा है तो सरकार उस पर क्या राय रखती है और अगर गवर्नमेंट उससे सैटिसफाइड नहीं है जैसा कि कहा गया है कि क्या किसी हाई कोर्ट जज या हाई पावर कमिशन के सामने इस मामले को ले जा कर के उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका देने का सरकार विचार रखती है ?

Shri Sachindra Chaudhuri: As I have already told this House, so far as the report of the Public Accounts Committee is concerned Government have made a statement on this part of it also and sent it to the PAC, and the reaction of the Public Accounts

Committee is awaited before Government can either start a departmental inquiry, calling upon Shri Bhoothalingam to give an explanation or make up their mind that it is not necessary and it should be before any other authority. For that, we have got to wait for the reply of the Public Accounts Committee.

Shri Bhagwat Jha Azad: Government have only sent their statement. Have they asked the Public Accounts Committee to submit any further report?

Mr. Deputy-Speaker: The statement of Government has been forwarded by Government to the Public Accounts Committee.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): On a point of order. The question was whether any explanation from Shri Bhoothalingam had been forwarded by Government to the Public Accounts Committee, and if so, what the particular points were, and whether Government had formed any opinion on that explanation furnished by Shri Bhoothalingam. That is a question which the hon. Minister must answer.

Shri Sachindra Chaudhuri: In the other House, I was hauled over the coals because I made a reference to what had been sent to the Public Accounts Committee by Government and what the Public Accounts Committee had said in their own report; and I was reminded that until the Public Accounts Committee had given actual consideration to the statement that Government had made to the Public Accounts Committee, there should not be any reference to it, and I was reminded of the highest traditions of democracy and particularly parliamentary practice. May I, therefore, beg of hon. Members here not to press me to give any answers on that point, but wait until the Public Accounts Committee give their own comments or give their own suggestions on anything that I have to do on the Government side?

Shri Bhagwat Jha Azad: Have Government asked for any further report from the Public Accounts Committee? That is what we want to know.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member can ask only one question, and he has already asked the question and the answer has come already.

Shri Bhagwat Jha Azad: I am not asking any second question, I want to know whether Government have asked for any further report from the Public Accounts Committee or not. We know that Government generally send their comments on the findings of the Public Accounts Committee. We want to know whether Government have asked the Public Accounts Committee to submit any further report.

Mr. Deputy-Speaker: The Public Accounts Committee can report only to Parliament and not to Government.

Shri Bhagwat Jha Azad: Have Government asked the Public Accounts Committee to submit another report to Parliament?

Mr. Deputy-Speaker: Government have sent their statement to the Public Accounts Committee already. The hon. Minister has already said that.

But the Public Accounts Committee cannot report to Government.

श्री भागवत झा आज़ाद : आप भी पढ़े हुए हैं और हम भी पढ़े हुए हैं। आप समझते क्यों नहीं हैं ?

We want to know whether Government have asked the Public Accounts Committee to submit any report to Parliament about this or not. We want a reply to that question.

Mr. Deputy-Speaker: That is for the Public Accounts Committee and not for Government. Government cannot direct the Public Accounts Committee.

श्री भागवत झा आज़ाद : हम कहते हैं आम आप कहते हैं इमली। हे भगवान धन्य हो आप।

Mr. Deputy-Speaker: There is no other agenda before the House. So the House will now stand adjourned and meet again at 11 A.M. tomorrow.

13.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 28, 1966|Srawana 6, 1888 (Saka).